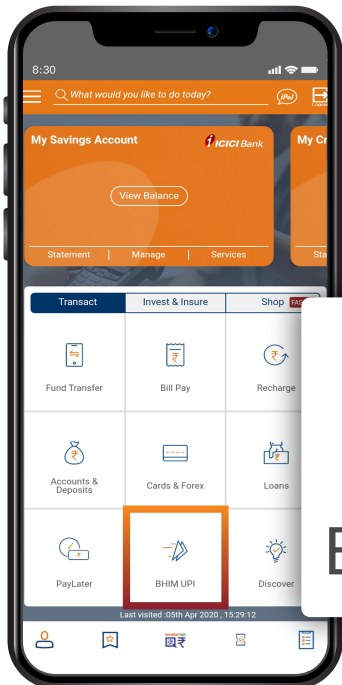


**iMobile पर तुरंत UPI ID
बनाएं और कभी भी कहीं भी
पेमेन्ट्स करें ।**



विशेष डिजिटल अंक

सच को समर्पित समाचार पत्रिका

24 अगस्त 2020, मूल्य ₹25

आउटलुक

www.outlookhindi.com



आज की राम कथा

अयोध्या में मंदिर बाद राजनीति और डिजिटल पीढ़ी के बदलते राम के साथ पौराणिक किस्सागोई का रंग-रूप



नई पीढ़ी के राम

मंदिर बाद राजनीति के साथ सामाजिक परिवेश में भी बदलाव के संकेत

28 पौराणिक पॉप की बढ़ती लोकप्रियता

35 इंटरव्यू: देवदत्त पटनायक

33 एनिमेशन इंडस्ट्री को मिला नया जीवन

37 विशेष लेख: अमीष त्रिपाठी

कवर डिजाइन: दीपक शर्मा, कवर फोटो: त्रिभुवन तिवारी



08

इंटरव्यू: शिक्षा मंत्री
रमेश पोखरियाल
'निशंक'

05 नई शिक्षा नीति: बदलाव कितने कारगर

10 कांग्रेस: बढ़ती चुनौतियों के आगे बेबस

14 सुशांत प्रकरण: मौत पर राजनीति

18 बिहार: संकट में चुनाव का नफा-नुकसान

22 पंजाब: कैप्टन पर वादे निभाने का दबाव

40 अर्थव्यवस्था: अधूरा पैकेज बेमानी

44 हरियाणा: चीन छोड़ने वाली कंपनियों पर नजर

54 शहरनामा: अयोध्या



46

इंसान नहीं
अब रोबोट को
नौकरी

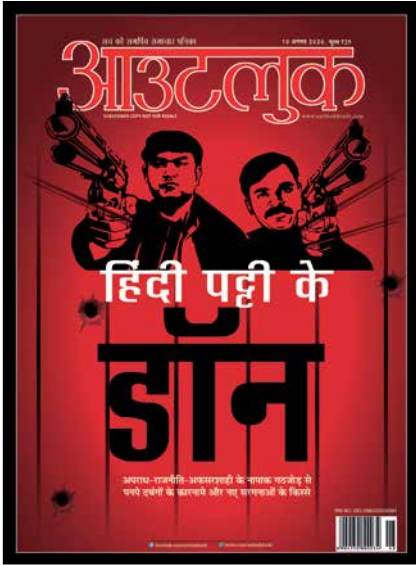
आउटलुक

प्रधान संपादक: रुबेन बनर्जी
कार्यकारी संपादक: गिरिश झा
डिप्टी एडिटर: सुनील कुमार सिंह
एसोसिएट संपादक: प्रशांत श्रीवास्तव
वरिष्ठ सहायक संपादक: हरीश मानव
सहायक संपादक: आकांक्षा पारे काशिव
वेब टीम: उपासना पांडेय, अक्षय दुबे
एडिटोरियल कंसल्टेंट: हरिमोहन मिश्र
डिजाइन: दीपक शर्मा (आर्ट डायरेक्टर) लीला, प्रवीण
कुमार, जी, विनय डामनिक (सोनियर डिजाइनर)
रोहित कुमार राय (डिजाइनर), रंजीत सिंह (विजुअलाइजर)
फोटो सेक्शन: जितेंद्र गुप्ता (फोटो एडिटर), त्रिभुवन
तिवारी (चीफ फोटोग्राफर), संदीपन चटर्जी, अपूर्व
सलकड़े (सोनियर फोटोग्राफर) सुरेश कुमार पांडे (स्टाफ
फोटोग्राफर), जे.एस. अधिकारी (सोनियर फोटो रिसर्चर)
संदर्भ: अलका गुप्ता

बिजनेस कार्यालय:
चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर: इंद्रनील राय
प्रकाशक: संदीप कुमार घोष
सोनियर वाइस प्रेसिडेंट: मीनाक्षी आकाश
सोनियर जनरल मैनेजर: देववाणी टैगोर,
शैलेन्द्र वोहरा
डिजिटल टीम: अमित मिश्रा
मार्केटिंग:
वाइस प्रेसिडेंट: श्रुतिका दीवान
सर्कुलेशन एंड सब्सक्रिप्शन: गगन कोहली, जी.
रमेश (साउथ), कपिल ढल (नार्थ),
अरुण कुमार झा (ईस्ट)

प्रोडक्शन:
जनरल मैनेजर: शशांक दीक्षित
मैनेजर: सुधा शर्मा, गौरव श्रीवास (एसोसिएट
मैनेजर), गणेश साह (डिप्टी मैनेजर)
अकाउंट:
वाइस प्रेसिडेंट: दीवान सिंह बिष्ट
कंपनी सेक्रेटरी एवं लॉ ऑफिसर: अंकित मंगल
प्रधान कार्यालय: ए.बी.-10 सफदरजंग एन्क्लेव,
नई दिल्ली-110029
संपादकीय कार्यालय: ए.बी.-10 सफदरजंग
एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029
टेलीफोन: 011-71280400, फैक्स: 26191420

संपादकीय ईमेल
edithindi@outlookindia.com
ग्राहकों के लिए संपर्क: 011-71280433,
71280462, 71280307
yourhelpline@outlookindia.com
अन्य कार्यालय:
मुंबई: 022-50990990
कोलकाता: 46004506, फैक्स: 46004506
चेन्नई: 42615224, 42615225 फैक्स: 42615095
बेंगलूरु: 43715021
प्रधान संपादक: रुबेन बनर्जी
आउटलुक पब्लिशिंग (इंडिया) प्रा.लि. की तरफ से
इंद्रनील राय द्वारा प्रकाशित। ए.बी.-10 सफदरजंग
एन्क्लेव, नई दिल्ली से प्रकाशित।



राजनीतिक उठापटक

आउटलुक के 10 अगस्त के अंक में सचिन पायलट की महत्वाकांक्षा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बेचैनी पर अच्छी रिपोर्ट है। भाजपा रिसोर्ट पॉलिटिक्स और महत्वाकांक्षी लोगों को शरण देने वाली पार्टी बनकर उभरी है। असम में हेमन्ता बिस्व सरमा, अरुणाचल में कांग्रेसी विधायकों का बीजेपी खेमे में जाना, 2017 में मणिपुर की घटना हो या उत्तराखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात के राज्यसभा चुनाव। सभी एक जैसे उदाहरण हैं।

कृष्ण चंद्र त्रिपाठी | रीवा, मध्य प्रदेश

बड़ा दांव

राजस्थान की सियासी उठापटक में यह तो समझ आ गया है कि सचिन पायलट कुछ ज्यादा ही बड़ा दांव खेल गए। जैसा कि आउटलुक के 10 अगस्त के अंक में लिखा है, गहलोत-पायलट के बीच शह-मात जारी है। पायलट, गहलोत के सामने बहुत नौसिखिए साबित हुए। लेकिन इन सबके बीच जनता खुद को ठगा हुआ महसूस करती है।

राधेश्याम तांबटकर | ठीकरी, म.प्र.

सत्ता का आकर्षण

आउटलुक के 27 जुलाई अंक में, 'शिवराज का सत्ता विष' पढ़ा। सिंधिया ने जिस तरह मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा किया, उसने शिवराज सहित कई पुराने नेताओं को फिलहाल विषपान करने के लिए विवश कर दिया। हालांकि उप चुनावों में नतीजों का ऊंट किस करवट बैठेगा, आगे की बातें उस पर तय होंगी।

बृजेश माथुर | गाजियाबाद, उ.प्र.

चीनी समीकरण

भारत-नेपाल के वर्षों से मैत्रीपूर्ण संबंध पर चीन दस्तक दे रहा है। संबंध बिगाड़ने में चीन के लिस होने के पुख्ता सबूत हैं। चीन की विस्तारवादी नीतियों का नेपाल पर असर है। नेपाल को आर्थिक सहायता की जरूरत है। चीन और नेपाल दोनों ही देशों में कम्युनिस्ट सरकार हैं, ऐसे में दोनों के बीच सामाजिक-सांस्कृतिक समरसता पनप रही है।

गरिमा सिंह | दिल्ली

पुरस्कृत पत्र

इनकी भी चिंता कीजिए

आउटलुक के 27 जुलाई के अंक में, 'देह दूरी का दंश' पढ़ा। हमारा जड़ समाज और उसकी रूढ़ मान्यताओं ने महामारी से ज्यादा विकराल रूप धरा है। यौनकर्मियों की करुणा भरी व्यथा आंखों में आंसू लाने के लिए काफी है। न मानवाधिकारियों को उनकी चिंता है, न ही सत्ता के झंडाबरदारों को। वोट की राजनीति ने समाज के सबसे संवेदी वर्ग को हाशिए पर छोड़ दिया है। शायद ये मतदाता सूची में उस तरह शामिल नहीं हैं या इनके वोट इतने नहीं होते कि किसी उम्मीदवार की जीत-हार पर इनके वोट का फर्क पड़े। गणिकाओं और 'देवदासियों' को अपनाने वाला हमारा देश भारत ऐसा कभी नहीं कर सकता। समाज के स्थाय पक्ष पर प्रकाश डालने के लिए आउटलुक ने यह कदम उठाया यह अच्छी बात है। इस तरह की खबरों से इनकी भी सुध ली जा सकेगी।

हेमंत कृष्णराव पाटीदार | खरगोन, म.प्र.

अब आप अपने पत्र इस मेल पर भी भेज सकते हैं:

hindioutlook@outlookindia.com

श्रेष्ठ पत्र को उपहार स्वरूप 1000 रुपये मूल्य की पुस्तकें

तकनीकी विकास ने पत्र लेखन की विधा को हाशिए पर जरूर धकेला है, लेकिन यह विधा पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। पत्र लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिए आउटलुक हिंदी पत्रिका अपने पाठकों के लिए एक योजना ला रही है। किसी भी पत्रिका के लिए प्रतिक्रिया स्वरूप मिलने वाले पाठकों के पत्र महत्वपूर्ण होते हैं। आउटलुक हिंदी पत्रिका में प्रकाशित लेखों पर 150 शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया भेजें और पाएं हिंदी के प्रतिष्ठित सामयिक प्रकाशन की ओर से एक हजार रुपये मूल्य की पुस्तकें। हर अंक में छपने वाले पत्रों में से एक सर्वश्रेष्ठ पत्र चुना जाएगा।

ध्यान रखें कि पत्र साफ लिखें और हों और लंबे न हों। संबंधित लेख का उल्लेख जरूर करें और अपनी टिप्पणी सटीक रखें। चुने गए पत्र पत्रिका में प्रकाशित किए जाएंगे। अपना नाम एवं पिन कोड सहित पूरा पता जरूर लिखें। संपादकीय निर्णय सर्वोपरि होगा।



सामयिक प्रकाशन
वरियागंज, नई दिल्ली-110002
samayikprakashan@gmail.com
www.samayikprakashan.com

आउटलुक पत्रिका प्राप्त करने के स्थान

दक्षिण: हैदराबाद यादगिरी बुक स्टॉल, 040-66764498, सिकंदराबाद उस्मान बुक स्टॉल, 9912850566

उत्तर: दिल्ली - आईबीएच बुक्स एंड मैगजीन डिस्ट्रिब्यूटर्स, 011-43717798, 011-43717799, लखनऊ - सुभाष पुस्तक भंडार प्रा. लिमिटेड, 9839022871, चंडीगढ़ - पुरी न्यूज एजेंसी, 9888057364, देहरादून - आदित्य न्यूज एजेंसी, 9412349259, भोपाल - इंडियन न्यूज एजेंसी, 9826313349, रायपुर - मुकुंद पारेख न्यूज एजेंसी, 9827145302, जयपुर - नवरत्न बुक सेलर, 9829373912, जम्मू - प्रीमियर न्यूज एजेंसी, 9419109550, श्रीनगर - जेपी न्यूज एजेंसी, 9419066192, दुर्ग (छत्तीसगढ़) - खेमका न्यूज एजेंसी, 9329023923

पूर्व: पटना - ईस्टर्न न्यूज एजेंसी, 9334115121, बरौनी - ज्योति कुमार दत्ता न्यूजपेपर एजेंट, 9431211440, मुजफ्फरपुर - अन्नू मैगजीन सेंटर, 9386012097, मोतीहारी - अंकित मैगजीन सेंटर, 9572423057, कोलकाता - विशाल बुक सेंटर, 22523709/22523564, रांची - मॉडर्न न्यूज एजेंसी, 9835329939, रवि कुमार सोनी, 9431564687, जमशेदपुर - प्रसाद मैगजीन सेंटर, 2420086, बोकारो - त्रिलोकी सिंह, 9334911785, भुवनेश्वर - ए. के. नायक, 9861046179, गुवाहाटी - दुर्गा न्यूज एजेंसी, 9435049511

पश्चिम: नागपुर - नेशनल बुक सेंटर, 8007290786, पाठक ब्रदर्स, 9823125806, नासिक - पाठक ब्रदर्स, 0253-2506898, पुणे - संदेश एन एस एजेंसी, 020-66021340, अहमदाबाद - के.वी. अजमेरा एंड संस, 079-25510360/25503836, मुंबई - दंगत न्यूज एजेंसी, 22017494



कांग्रेस ने अगर धर्मनिरपेक्षता पर सही रुख अपनाया होता, तो देश आज जिस नियति का सामना कर रहा है, वह उसे नहीं करना पड़ता

पिनरई विजयन, मुख्यमंत्री, केरल

फीकी दावत

दिल्ली में मैडम के जन्मदिन का जश्न मनाने की पूरी तैयारी थी। सांसदगण मैडम को मानते भी बहुत हैं। मुख्यमंत्री के साथ जारी ट्विटर वार के बावजूद मैडम के लिए पूरा इंतजाम किया गया। चुनिंदा लोग हाजिर हुए। अवसर खुशी का था तो दावत का रंग भी उसी तरह छाया हुआ था। अचानक सोशल मीडिया पर साहब की डिग्री के जाली होने का मामला वायरल हो गया। उमंग के माहौल पर पानी फिर गया। इसके बाद नेताजी का पारा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। ट्विटर पर जारी जंग का रंग समय के साथ और गाढ़ा होता जा रहा है। लड़ाई निजी बनती जा रही है। राजनीति में कब कौन कहां चला जाए, कहा नहीं जा सकता।

अयोध्या के बीच कश्मीर

वैसे तो 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की ही गहमागहमी थी, लेकिन उस दौरान कश्मीर को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी सक्रिय थे। चर्चा है कि प्रधानमंत्री ने लखनऊ पहुंचते ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रमुख नेता मनोज सिन्हा से मिलने की बात कही। देर रात इस बात का खुलासा भी हो गया कि सरकार के मन में क्या चल रहा था। मनोज सिन्हा जम्मू-कश्मीर के नए उप-राज्यपाल बनाए गए हैं, जबकि पूर्व उप-राज्यपाल जी.सी.मुर्मू को दिल्ली में अहम पद देने की तैयारी है। चर्चा यह भी है कि केंद्र सरकार मनोज सिन्हा को जम्मू-कश्मीर भेजकर राज्य के राजनैतिक दलों को सकारात्मक संदेश देना चाहती है, जो राज्य का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद से अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं।

परेशान नीतीश

बाढ़ के संकट में राहत वितरण, सड़कों का जाल बिछाने, ग्रामीण इलाकों में भी बिजली पहुंचाने और नियमित आपूर्ति को लेकर सफलता हासिल करने वाली नीतीश सरकार की पहली बार कोरोना के कारण किरकिरी हो रही है। कैबिनेट की बैठक में जांच की धीमी गति का ममला उठा तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने ठीकरा सचिव उदय सिंह कुमावत के सिर फोड़ दिया, कहा कि वे उदासीन हैं। बस सीएम फट पड़े और 48 घंटे के भीतर उनका तबादला हो गया। कोरोना काल के दौरान दो स्वास्थ्य सचिव बदल दिए गए हैं। 20 मई को ही संजय कुमार को हटाकर कुमावत को लाया गया था। अब नीतीश कुमार के भरोसेमंद माने जाने वाले प्रत्यय अमृत को जिम्मा मिला है। वह कितनी राहत दे पाएंगे यह तो वक्त बताएगा।

अध्यक्ष बनने की स्वादिष्ट

ऐतिहासिक पार्टी के सांसद महोदय नाराज हैं और उन्होंने विद्रोह का झंडा उठा लिया है। वे दिल्ली दरबार में कुछ विधायकों के साथ हाजिरी लगा चुके हैं तथा कुछ और विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। वे ताकत इतनी बता रहे हैं कि बगावत हुई तो सरकार पर संकट आ सकता है। खुद खामोश हैं मगर सहयोगियों से 'एक व्यक्ति, एक पद' की भी रट लगवा रहे हैं। करीबी बताते हैं कि उनका निशाना प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर है। इस बीच वे विपक्ष के भी संपर्क में हैं। देखना है ज्यादा चालाकी कहीं भारी न पड़ जाए।

घोटाले के बहाने

नौ महीने पुरानी हरियाणा की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार में सहयोगी जननायक जनता पार्टी (जजपा) के प्रमुख और उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के अधीन विभागों में एक के बाद एक घोटाले चर्चा में हैं। चावल मिलों में सरकारी धान का घोटाला, लॉकडाउन के दौरान शराब तस्करी और प्रॉपर्टी रजिस्ट्री घोटालों से गठबंधन सरकार विपक्ष के निशाने पर है। इन घोटालों की जांच और कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक के बाद एक

संबंधित मुलाजिमों और अफसरों पर कार्रवाई कर रहे हैं। चर्चा है कि बार-बार घोटालों में दुष्यंत के हिस्से के विभागों के ही नाम क्यों आ रहे हैं? कही भाजपा रणनीति के तहत गठबंधन में सहयोगी जजपा पर दबाव तो नहीं बना रही है, इसलिए दुष्यंत के विभाग ही निशाने पर हैं? अन्य किसी मंत्री के विभाग में अनियमितताओं की अभी तक कोई खबर नहीं है। दुष्यंत चौटाला से नाराज उनकी पार्टी के ही कुछ विधायकों को घोटालों पर चर्चा को बढ़ाते हुए यहां तक कहने से भी गुरेज नहीं है कि एक ही आदमी के पास 11 महत्वपूर्ण विभागों का बोझ रहेगा तो वह इन विभागों पर ध्यान केंद्रित कैसे कर पाएगा?

अब दारोमदार अमल पर

पहली और दूसरी शिक्षा नीति के अनेक प्रस्तावों पर अमल नहीं,
इसलिए तीसरी नीति पर संशय



प्रकाश कुमार

साल 1968 में घोषित पहली शिक्षा नीति हर आदमी के जीवन को समृद्ध करने, राष्ट्र की प्रगति और सुरक्षा में उन्हें योगदान देने की शक्ति देने, साझी नागरिकता और संस्कृति को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की परिकल्पना पर आधारित थी। तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने इसकी घोषणा की थी। हर स्तर पर गुणवत्ता में सुधार, शिक्षा के अवसर के निरंतर विस्तार, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर फोकस के साथ 14 वर्ष की आयु तक के

बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा और नैतिक मूल्यों के विकास की इस नीति में शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल बदलाव की जरूरत बताई गई थी।

पहली शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा आयोग (1964-66), जिसे कोटारी आयोग के नाम से जाना गया, की सिफारिशों के आधार पर तैयार की गई थी।

राज्यों के ज्यादा रुचि न दिखाने के कारण उसके ज्यादातर प्रस्ताव कागजों पर ही रह गए। इसका एक प्रमुख कारण यह था कि इसमें 10+2+3 पैटर्न को पूरे देश में एक समान लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन तब तक संविधान के तहत शिक्षा पूर्ण रूप से राज्य का विषय था।

नया सिस्टम: पांचवीं तक की पढ़ाई मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगी

42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया गया और इसके अगले साल 10+2+3 पैटर्न भी लागू किया गया। हालांकि बाद के वर्षों में शैक्षिक सुविधाओं में व्यापक विस्तार दिखा, लेकिन 1968 की नीति की अनेक बातों पर अमल न हो सका। नतीजा यह हुआ कि शिक्षा की पहुंच, गुणवत्ता, उपयोगिता और खर्च जैसी समस्याएं साल दर साल बढ़ती गईं।

समस्या के समाधान के लिए मई 1986 में राजीव गांधी सरकार दूसरी शिक्षा नीति लेकर आई। 1992 में प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव के शासनकाल में इसमें कुछ अतिरिक्त बातें जोड़ी गईं। इनमें शिक्षा की पहुंच के नए लक्ष्य तय करने के साथ परीक्षा प्रणाली में सुधार करना शामिल था। 1986 की नीति में सबको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने, ऐसी व्यवस्था करने जिससे 14 वर्ष तक के बच्चे स्कूल न छोड़ें और शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। सबको शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराने के साथ उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और मानकों में सुधार पर भी जोर दिया गया।

इसके अलावा, प्रौढ़ शिक्षा, प्राथमिक स्तर से पहले के बच्चों की देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई), रोजगारपरक शिक्षा, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा और मूल्यपरक शिक्षा दूसरी नीति के मुख्य आधार थे। इसमें शोध को बढ़ावा देने के अलावा छात्रों को करिअर के विकल्प के रूप में स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया गया। 1986 की नीति लागू होने के बाद शिक्षण सुविधाओं का काफी विस्तार हुआ। हालांकि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून लागू करने में 41 साल लग गए। इसे अंततः 2009 में लागू किया जा सका। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार देश में 993 विश्वविद्यालय, 39,931 महाविद्यालय और 10,725 स्टैंडअलोन संस्थान हैं। इनकी बदौलत भारत, अमेरिका और चीन के बाद उच्च शिक्षा संस्थानों का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। स्कूलों की संख्या भी 15.50 लाख हो गई, जिनमें 24.78 करोड़ छात्र पढ़ते हैं। फिर भी, पहली और दूसरी नीति के कई एजेंडे अभी अधूरे हैं।

इसे आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार हाल ही नई शिक्षा नीति लेकर आई है। इसमें स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता सुधारने और उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए बड़े 'परिवर्तनकारी सुधार' प्रस्तावित हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नई शिक्षा नीति-2020 में 10+2 पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 में बदलने का प्रस्ताव है, ताकि तीन से 18 वर्ष के छात्रों के लिए ईसीसीई को औपचारिक स्कूली शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जा सके और 2030 तक स्कूली शिक्षा सर्वसुलभ हो।

स्कूली शिक्षा के शुरुआती चरण में ही कंप्यूटर साक्षरता की बात कही गई है ताकि छात्रों को 21वीं सदी के कौशल से लैस किया जा सके। छठी कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है, ताकि 2025 तक कम से कम 50 फीसदी छात्रों को रोजगारमुखी शिक्षा मिल सके। बच्चे बेहतर तरीके से सीख सकें, इसके लिए एनईपी-2020 में कम से कम पांचवीं कक्षा तक बच्चों को उनकी मातृभाषा, घरेलू भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने पर जोर दिया है। इसमें यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कक्षा तीन उत्तीर्ण होने तक छात्र बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान हासिल कर लें।

छात्रों में परीक्षा का तनाव कम करने और रतने की व्यवस्था समाप्त करने के लिए, नीति में पाठ्यक्रम को फिर से डिजाइन करने का प्रस्ताव है ताकि कोर्स घटाया जा सके। इसमें मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव और बोर्ड परीक्षाओं को 'आसान' बनाने का भी प्रस्ताव है, ताकि इसे छात्रों की याद करने की क्षमता की परीक्षा के बजाय ज्ञान की परीक्षा बनाया जा सके।

इस नीति में सभी विश्वविद्यालयों के लिए समान प्रवेश परीक्षा आयोजित करने और अन्य प्रवेश परीक्षाओं में बदलाव का प्रस्ताव है। छात्रों के पास 10वीं के बाद पढ़ाई कुछ समय के लिए रोकने और बाद में फिर 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने का विकल्प होगा। एनईपी-2020 में अंडर-ग्रेजुएट की पढ़ाई चार साल करने और इसे बहुविषयक बनाने का प्रस्ताव है। छात्रों के पास किसी भी वर्ष पढ़ाई छोड़ने और बाद में फिर दाखिला लेने का विकल्प होगा। यह सुविधा तीन साल के अंडर-ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला लेने वालों को भी मिलेगी। यदि कोई छात्र पहला साल पूरा करने के बाद पढ़ाई छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और तीसरे साल के बाद स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी।

चार साल के बहुविषयक अंडर-ग्रेजुएट कोर्स में छात्रों को अमेरिका की तर्ज पर 'मेजर' और 'माइनर' का विकल्प चुनने के साथ रिसर्च में डिग्री कोर्स का भी विकल्प मिलेगा। मास्टर्स में दो प्रकार के कोर्स होंगे। तीन वर्षीय स्नातक वाले छात्रों के लिए यह दो वर्ष का और चार वर्षीय स्नातक वाले छात्रों के लिए एक वर्ष का होगा। पीएचडी के लिए मास्टर्स डिग्री या रिसर्च के साथ चार साल की बैचलर्स डिग्री अनिवार्य होगी। एमफिल का कोर्स बंद किया जा रहा है।

नई नीति में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) के गठन का प्रस्ताव है। काम के अनुसार इसके चार वर्टिकल होंगे- नियमन, मान्यता, फंडिंग और शैक्षणिक मानक। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) जैसे मौजूदा नियामकों का स्थान लेगा। श्रेष्ठ रैंकिंग वाले विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपना कैंपस खोल सकेंगे। कॉलेजों को



नया कदम: उप-राष्ट्रपति वेंकैया नायडू को शिक्षा नीति की प्रति सौंपते शिक्षा मंत्री 'निशंक' (ऊपर), छठवीं से मिलेगी रोजगारपरक शिक्षा

स्वायत्तता देने की मौजूदा नीति जारी रहेगी। इसके तहत धीरे-धीरे हर कॉलेज को डिग्री प्रदान करने वाले स्वायत्त कॉलेज अथवा किसी विश्वविद्यालय के घटक कॉलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। इस बारे में नई नीति में कहा गया है, "एक पारदर्शी प्रणाली के जरिए कॉलेजों को चरणबद्ध तरीके से स्वायत्तता देने का तंत्र स्थापित किया जाएगा। मान्यता के हर चरण के न्यूनतम मानदंड पूरे करने के लिए कॉलेजों को प्रोत्साहित किया जाएगा, उनकी मंटेरिंग की जाएगी और इन्सेंटिव दिया जाएगा।" नई शिक्षा

नीति के तहत ओपन और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देकर 2035 तक उच्च शिक्षा में ग्रांस एनरोलमेंट रेशियो (जीईआर) बढ़ाकर 50 फीसदी करने का प्रस्ताव है, जो अभी 26.3 फीसदी है। अनुसंधान की मजबूत संस्कृति को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा के सभी क्षेत्र में अनुसंधान क्षमता विकसित करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) नाम से एक शीर्ष निकाय गठित किया जाएगा।

एनईपी-2020 में शिक्षा प्रणाली में बदलाव के लिए कई अन्य प्रस्ताव भी हैं। शिक्षा पर निवेश 'उल्लेखनीय' रूप से बढ़ाने की बात है। इसमें कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को जल्द से जल्द जीडीपी के छह फीसदी तक पहुंचाने के लिए मिलकर काम करेंगी। इस संबंध में कहा गया है, "उच्च-गुणवत्ता वाली और उचित सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के भविष्य की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक और तकनीकी प्रगति और विकास के लिए यह आवश्यक है।" नीति में परोपकारी माध्यमों से धन जुटाने का उल्लेख है। कोई भी सार्वजनिक संस्था इसकी पहल कर सकती है।

नीति में कहा गया है, "शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय जीडीपी के छह फीसदी तक पहुंचाने की बात 1968 की पहली नीति में कही गई थी। 1986 की दूसरी नीति और 1992 की समीक्षा में भी इसे दोहराया गया, लेकिन दुर्भाग्य से वास्तविक व्यय इसके करीब भी नहीं पहुंचा है।" हालांकि नई नीति में भी इस लक्ष्य को हासिल करने की कोई समय-सीमा तय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में अपने घोषणापत्र में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को जीडीपी के छह फीसदी तक ले जाने की बात कही थी, जो 2013-14 में 3.84 फीसदी थी।



पर्यावरण पर नई दृष्टि जरूरी

बहुविषयक पढ़ाई पर्यावरण समझ विकसित करने में मददगार, मगर प्रयोगधर्मी शिक्षा भी अनिवार्य



विपुल सिंह

कई वर्षों से पर्यावरण इतिहास के पठन-पाठन से जुड़े होने के कारण यह गहरा एहसास है कि अर्थशास्त्र, भूगोल, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान जैसे विषयों पर जानकारी के अभाव में उसे ठीक से समझ पाना काफी मुश्किल है। इस मायने में पर्यावरण अध्ययन का संबंध बहुविषयक है। इसके दायरे में वह सब आता है जिससे मानव सभ्यता विकसित हुई और उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है। हम न केवल

जानवरों, पौधों, अन्य जीवों, पानी, मिट्टी, वायु, महासागर, पृथ्वी की पपड़ी, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और महासागर की धाराओं आदि का अध्ययन करते हैं, बल्कि लोगों के साथ उनके संबंधों का भी अध्ययन करते हैं। वे एक-दूसरे के साथ इस तरह गुंथे हुए हैं कि विज्ञान और भूगोल से लेकर मानविकी तक जैसे कई विषय इसमें समा जाते हैं।

इसी मायने में नई शिक्षा नीति, 2020 में बहुविषयक पाठ्यक्रम का घोषित उद्देश्य लंबे समय से चली आ रही बाधा को कम कर सकता है। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) को 1992 में 'पर्यावरण संरक्षण' को एक कोर के रूप में शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था, जिसके आसपास एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बाद में विकसित की गई थी। कक्षा 3 से 5 के छात्रों को स्कूलों में पर्यावरण के बारे में पढ़ाया जाता था। 2006 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, पर्यावरण स्नातक स्तर पर भी अध्ययन का अनिवार्य विषय बन गया। भले ही पर्यावरण शिक्षा स्कूल पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा रही हो, यह जटिल पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने से नहीं जुड़ी है। दुर्भाग्य से, सिर्फ किताबी पढ़ाई से छात्रों में पर्यावरण की समझ नहीं विकसित की जा सकती है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि एनपीई अपने समय से आगे का विचार था और पिछले कुछ दशकों में भारत ने उसके आधार पर ही तीव्र आर्थिक प्रगति की। लेकिन अब जब दुनिया में तेजी से जबरदस्त बदलाव हो रहे हैं, इसमें बदलाव की जरूरत थी। आज हमें जलवायु परिवर्तन जैसी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग आज काफी अहम हो गया है। जब हम सतत विकास की बात करने लगे हैं तो यह जरूरी है कि हमारी शिक्षा नीति में पर्यावरण जागरूकता पर विशेष जोर हो और शिक्षा, समस्याओं को सुलझाने से जुड़ी हो।

हमें इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों है कि पर्यावरण के अच्छे और बुरे के बारे में बच्चों को पढ़ाए जाने के बावजूद समाज का व्यवहार नहीं बदला है। ज्ञान प्रदान करने के पारंपरिक तरीकों ने वांछित परिणाम नहीं दिया है।

इसका समाधान इस तथ्य में निहित है कि प्रकृति

के साथ संबंध केवल प्रकृति में ही बनाया जा सकता है। यह केवल छात्रों के प्रकृति के साथ साक्षात्कार से सम्भव है। हमें उन्हें प्रयोगों में शामिल करना और चीजों को स्वयं बढ़ाना सिखाना होगा, ताकि वे प्रकृति प्रेमियों के रूप में विकसित हो सकें। पर्यावरण शिक्षा का बेहतर तरीका यह है कि छात्र शिक्षक वर्ग के साथ जंगल एवं विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर सच्चाई का अनुभव करें। हमें स्कूलों में गार्डन स्थापित करना चाहिए जो न केवल छात्रों को पर्यावरण से जोड़ेगा, बल्कि उनके जीव विज्ञान के पाठों को भी जीवंत करेगा। इस तरह का सीखना न केवल आसान है, बल्कि स्थायी भी है। इसी तरह, रीसाइक्लिंग पर व्यावहारिक कौशल, कचरे का निपटारा और छात्रों को जैविक खेती की शिक्षा प्रदान की जा सकती है। इन सब की बात इस नई शिक्षा नीति में की गई है।

नई शिक्षा नीति में पर्यावरणीय जागरूकता, जल और संसाधन संरक्षण और स्वच्छता शामिल हैं; और स्थानीय समुदायों का सामना करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों के ज्ञान पर विशेष जोर दिया गया है। पर्यावरण शिक्षा में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता के विषयों को शामिल किया गया है। यह जैविक विविधता के संरक्षण, जैविक संसाधनों के प्रबंधन और जैव विविधता, वन और वन्यजीव संरक्षण के बारे में भी बात करता है। ये तत्व वास्तव में स्थायी भविष्य के लिए अनिवार्य हैं। हम जानते हैं कि शिक्षित आबादी आर्थिक विकास की कुंजी है। तेजी से वैश्वीकृत होती अर्थव्यवस्था में यह भी आवश्यक है कि आर्थिक विकास सतत विकास से जुड़ा हो। यह संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष एजेंडे का हिस्सा भी है और इस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं।

हाल के वर्षों में मशीनों और डिजिटल प्रौद्योगिकी में प्रगति ने नए अवसरों की पेशकश की है। हम युवाओं को नौकरियों के लिए तैयार करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हमारी औपचारिक शिक्षा रोजगार और आवश्यक कौशल से जुड़ी हो। यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी के छात्रों के बीच बहु-विषयक क्षमताओं को विकसित करके हासिल किया जा सकता है।

भारत की जनसांख्यिकीय संरचना ने भी यह मांग की कि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। भारत की आबादी का 62 प्रतिशत 15 से 59 के आयु वर्ग में है और 35 वर्ष से कम उम्र की यहां दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। भारत की आबादी में इस आयु वर्ग का हिस्सा 2036 में सर्वाधिक, 65 प्रतिशत होगा। इसलिए आश्चर्य की बात नहीं कि सरकार ने उसी वर्ष तक नई शिक्षा नीति को हासिल करने का लक्ष्य रखा है। देखना होगा कि सरकार इससे भी बड़ी चुनौती, जो बहुविषयकता पर आधारित पाठ्यक्रम विकसित करने की है, से किस प्रकार निपटती है और अपने आपको राजनीतिक मजबूरियों से कैसे दूर रख पाती है।

पाठ्यक्रम का हिस्सा होने के बावजूद पर्यावरण शिक्षा अहम मुद्दों के हल में नाकाम रही, सिर्फ किताबी पढ़ाई से पर्यावरण की समझ नहीं विकसित की जा सकती

(लेखक पर्यावरण इतिहासकार और दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर हैं)

नई शिक्षा नीति-2020 का उद्देश्य भारत को एक ज्ञान आधारित समाज के रूप में विकसित करना और उसे सुपरपावर बनाना है। इसे हासिल करने के लिए नई शिक्षा नीति में क्या अहम प्रावधान किए गए हैं, इस पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' से प्रकाश कुमार ने बात की। प्रमुख अंश:

हमें नई शिक्षा नीति की क्या जरूरत थी, जबकि अभी पहले की नीतियों के एजेंडे पर ही अमल नहीं हो पाया है?

नई शिक्षा नीति-2020 पुरानी नीतियों के उन अधूरे एजेंडों को भी पूरा करेगी, जिसमें उनका उद्देश्य सबको और बिना किसी भेदभाव के शिक्षा देना था। पिछली शिक्षा नीति 1986 में आई थी, जिसे 1992 में संशोधित किया गया था। संशोधन के बाद शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार बन गया। इसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 बनाया गया। नई शिक्षा नीति-2020, इक्कीसवीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसे 2030 के विकास एजेंडे को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य भारत को एक ज्ञान आधारित समाज में विकसित कर दुनिया में सुपरपावर बनाना है। इसके लिए स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को कहीं ज्यादा समावेशी बनाया गया है। नई नीति को 21वीं सदी की जरूरतों को देखते हुए काफी लचीली और बहु-विषयक शिक्षा प्रणाली के लिए तैयार किया गया है। इसके जरिए हर छात्र की विशेष क्षमता का सदुपयोग किया जा सकेगा।

10+2 की जगह 5+3+3+4 वाला पाठ्यक्रम क्यों अपनाया गया?

नए पाठ्यक्रम को इस तरह तैयार किया गया है कि उससे बच्चे की बुद्धि का विकास हो सके। नीति में कम उम्र से ही बच्चे की इस आधार पर परवरिश करने पर जोर है। इसी कारण 10+2 की जगह 5+3+3+4 वाला पाठ्यक्रम लाया गया है। इसके तहत 3-8, 8-11, 11-14 और 14-18 वर्ष की उम्र के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। इस बदलाव से 3-6 वर्ष की उम्र के बच्चे स्कूली शिक्षा से जुड़ जाएंगे। यह पद्धति पूरी दुनिया में लागू है और माना जाता है कि इससे बच्चों का बेहतर विकास होता है।

देश भर के स्कूलों में लाखों शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, ऐसे में 5+3+3+4 प्रणाली कैसे लागू होगी?

नई शिक्षा नीति में शिक्षकों को केंद्र में रखकर मूलभूत बदलाव करने की बात कही गई है। इसके तहत ऐसी चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिससे सभी स्तर पर सबसे अच्छे लोग शिक्षक चयनित हों। इस पूरी प्रक्रिया में शिक्षक के जीवनयापन, सम्मान, प्रतिष्ठा और स्वायत्तता का भी ध्यान रखा जाएगा। नई व्यवस्था में पढ़ाई की गुणवत्ता और शिक्षकों की जवाबदेही पर भी जोर रहेगा। ऐसे क्षेत्रों में जहां



“21वीं सदी की मांग पूरी करेगी नई शिक्षा नीति”

काफी कम साक्षरता है, छात्रों के मुकाबले शिक्षकों का अनुपात कम है। वहां जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षकों की जरूरतों को समझने के लिए हम तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। इसके जरिए प्रत्येक राज्य अगले 20 साल में विषय के आधार पर शिक्षकों की जरूरत का आकलन करेगा। उसी आधार पर नियुक्तियां की जाएंगी।

स्कूल में अध्यापन का माध्यम क्या होगा ?

ज्यादातर विकसित देशों में शुरुआती स्कूली शिक्षा बच्चों की मातृभाषा में दी जाती है। इसका फायदा यह होता है कि बच्चे के साथ-साथ माता-पिता भी उसकी पढ़ाई में सहभागिता करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कहा गया है कि बच्चों को समझाने और व्यावहारिक ज्ञान देने का तरीका उसकी मातृभाषा में होना चाहिए। नई शिक्षा नीति कहती है, आठवीं कक्षा या हो सके तो उससे आगे की कक्षा में भी पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो पांचवीं कक्षा तक हर हाल में कोशिश होनी चाहिए कि समझाने का माध्यम मातृभाषा ही हो। यह व्यवस्था सरकारी और निजी दोनों स्कूलों के लिए होगी। इस आधार पर केंद्र और राज्य सरकारें बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय भाषाएं जानने वाले शिक्षकों की नियुक्ति कर सकेंगी। इसके लिए अलग-अलग राज्य आपस में शिक्षकों की भर्ती के लिए समझौते भी कर सकते हैं। इस तरह त्रिभाषी फॉर्मूले के आधार उनकी जरूरतें पूरी हो सकेंगी।

बोर्ड परीक्षाओं के लिए नया तरीका क्या होगा ?

दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं चलती रहेंगी। लेकिन परीक्षा के तरीके और प्रवेश परीक्षाओं को ऐसा बनाया जाएगा, जिससे कोचिंग क्लास की जरूरत नहीं रह जाएगी। छात्र के पास चुनने के लिए ज्यादा विषय होंगे। वे अपनी इच्छा के अनुसार विषय पढ़ सकेंगे। परीक्षा की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी। यह इस तरह होगी कि अगर कोई छात्र स्कूल की पढ़ाई के आधार पर एक सामान्य पढ़ाई भी करेगा तो वह परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करेगा। अच्छे नंबर लाने के लिए उसे कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना होगा। परीक्षा का दबाव कम करने के लिए छात्र साल में दो बार बोर्ड परीक्षा देगा। एक प्रमुख परीक्षा होगी तो दूसरी जरूरत पड़ने पर सुधार के लिए ली जाएगी। छात्रों और सभी मान्यता प्राप्त बोर्ड के मूल्यांकन के लिए एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख (समग्र विकास के लिए ज्ञान का मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण) का गठन किया गया जाएगा जो मानक और दिशानिर्देश तय करेगा। एक राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी का भी गठन होगा जो उच्च गुणवत्ता वाला एप्टीट्यूड टेस्ट और विभिन्न विषयों जैसे विज्ञान, भाषा, कला, व्यवसाय, मानविकी के लिए कॉमन प्रवेश परीक्षा लेगी। इस आधार पर विश्वविद्यालयों में साल में दो



“शिक्षा का व्यवसायीकरण रोकने के लिए शिक्षा नीति में एक अलग अध्याय है। कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिनसे व्यवसायीकरण पर रोक लगेगी”

बार प्रवेश परीक्षाएं ली जाएंगी।

नई शिक्षा नीति में स्कूल पाठ्यक्रमों में अहम बदलाव की बात की गई है, जिसके आधार पर अब भारतीय और स्थानीय परंपराओं और मान्यताओं को ज्यादा तरजीह दी जाएगी...

नई नीति का विजन ही ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है जिसमें भारतीय परंपराओं और मूल्यों को जगह मिले, शिक्षा प्रणाली में इंडिया की जगह भारत की झलक मिले। इसका उद्देश्य ऐसी समतावादी और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रणाली बनाना है जिससे एक ज्ञान आधारित समाज का निर्माण हो और भारत दुनिया में एक सुपरपावर के रूप में स्थापित हो। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा समिति की यह जिम्मेदारी होगी कि वह इन मुद्दों को पाठ्यक्रम में शामिल करे। “भारत के ज्ञान” में प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत के समय में लोगों के योगदान को शामिल किया जाएगा। हमें यह समझना होगा कि इसकी सफलता भारत के भविष्य की उम्मीदों की दिशा तय करेगी। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण आदि सब शामिल हैं। इसमें आदिवासियों के ज्ञान से लेकर स्थानीय और परंपरागत तरीकों को भी जगह मिलेगी। इन तरीकों को वैज्ञानिक तरह से

समझ कर ही पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। ये तरीके गणित, ज्योतिष, मनोविज्ञान, योग, कृषि, इंजीनियरिंग, भाषा, साहित्य, खेल, गवर्नेंस, राजनीति, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में शामिल होंगे। सभी पाठ्यक्रमों में जरूरी बदलाव शुरुआती स्तर से ही किए जाएंगे। इसमें भारतीय परंपराओं, मान्यताओं और स्थानीयता की झलक होगी। इसमें संस्कृति, धरोहर, रहन-सहन, भाषा, मनोविज्ञान के प्राचीन और समकालीन ज्ञान को भी शामिल किया जाएगा। पाठ्यक्रम में कहानियां, कला, खेल आदि के उदाहरण ऐसे होंगे जिनमें भारतीय परंपराओं और स्थानीयता का तत्व शामिल होगा। इसी तरह आदिवासियों की चिकित्सा पद्धति, उनके वन संरक्षण, पारंपरिक खेती के तरीके, प्राकृतिक कृषि आदि के लिए पाठ्यक्रम बनाए जाएंगे।

वाम दल इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि नई शिक्षा नीति-2020 से केंद्रीकरण, सांप्रदायिकता और शिक्षा के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

नई शिक्षा नीति में राज्यों की भूमिका को महत्व दिया गया है। नीति का कोई भी हिस्सा राज्यों की मर्जी के बिना नहीं थोपा जाएगा। नीति का जोर इसी बात पर है कि ऐसी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली विकसित की जाए जो सबको गुणवत्तापरक शिक्षा दे सके। शिक्षा के व्यवसायीकरण को कैसे रोका जाए, उस पर शिक्षा नीति में एक अलग अध्याय भी शामिल किया गया है। इसके अलावा कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिनसे व्यवसायीकरण पर रोक लगेगी। सभी शिक्षण संस्थानों का “गैर-लाभकारी” इकाई के रूप में ऑडिट किया जाएगा। अगर कोई संस्थान अतिरिक्त कमाई करता है तो उसे भी शिक्षा के विकास में खर्च करना पड़ेगा। सभी वित्तीय मामलों के लिए पारदर्शी डिसक्लोजर नीति अपनाई जाएगी। नई शिक्षा नीति प्रत्येक भाषा, कला और संस्कृति को समान रूप से विकसित करने पर जोर देती है।



कितनी असरदार: सोनिया-राहुल-प्रियंका की तिकड़ी के सामने पार्टी को पटरी पर लाने की बड़ी चुनौती

उलझन जो सुलझे ना

क्या कांग्रेस की वंशवादी नेताओं के बदले जमीनी कार्यकर्ताओं को तरजीह देने की नीति कारगर होगी?

पुनीत निकोलस यादव

कांग्रेस की नैया खासकर पिछले एक साल से डांवाडोल है, जबसे राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और पिछले 10 अगस्त को बतौर अंतरिम अध्यक्ष उनकी मां सोनिया गांधी के हाथ कमान आई है। पार्टी में न केवल मतभेद बढ़े हैं बल्कि कई अहम नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। नरेंद्र मोदी-अमित शाह की जोड़ी की कांग्रेस-विरोधी हवा को शह देने की रणनीति की काट निकालने में पार्टी अपनी नाकाबिलियत का मानो खामियाजा भुगत रही है।

इसके साथ लगातार चुनावी पराजय और हाल के वर्षों में कुछेक जीते राज्यों में अपने घर को एकजुट रखने में नाकामी भी उसकी दुर्दशा बढ़ा रही है। यही नहीं, रह-रहकर उठने वाली महत्वाकांक्षा की

हुंकार पुराने दिग्गजों और युवा नेताओं तथा कई बार हमउम्र नेताओं के बीच भी कलह की वजह बन जा रही है।

मार्च से कांग्रेस मध्य प्रदेश में सत्ता गंवा चुकी

है, और राजस्थान में भी उसी कगार पर पहुंच गई है, जहां राजनीति के माहिर खिलाड़ी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने 46 साल के राजनैतिक अनुभव के बूते बागी नेता सचिन पायलट और भाजपा की सरकार गिराने की कोशिशों की काट में लगे हैं। दोनों ही राज्यों में पार्टी की सरकार को चुनौती चुनी हुई सरकारों को गिराने में अपनी महारत साबित कर चुकी भाजपा से ही नहीं मिली, बल्कि कमोवेश उतने ही जोरदार ढंग से पार्टी के नेताओं से भी मिली। एक समय ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट कांग्रेस की अगली पीढ़ी के ऐसे नेता माने जाते थे, जिन पर राहुल गांधी पार्टी को मजबूत करने के लिए भरोसा कर सकते थे। लेकिन अब एक तो भाजपा में जा मिले हैं और दूसरे भले फिलहाल भाजपा में न

जाएँ पर पार्टी से नाता तोड़ने का मन बना चुके हैं।

यही नहीं, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में भी, जहां पार्टी अपने बूते या गठबंधन में सरकार में है, बगावत या दलबदल की सुगबुगाहटें हैं (खासकर पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ)। संगठन के स्तर पर भी पार्टी में विरोध के स्वर लगातार मुखर होते जा रहे हैं, जिसमें वरिष्ठ और युवा नेतृत्व के बीच खींचतान चल रही है। लोकसभा सांसद मनीष तिवारी और शशि थरूर जैसे नेता संगठन में बड़ी जिम्मेदारी चाहते हैं। इसके लिए ये नेता पार्टी अध्यक्ष पद से लेकर कांग्रेस कार्यकारिणी में शामिल होने की खातिर संगठन के स्तर पर चुनाव के लिए भी तैयार हैं।

मनीष तिवारी लगातार यह मांग करते रहे हैं कि भाजपा को कारगर चुनावी टक्कर देने के लिए कांग्रेस को विचारधारा और रणनीति पर स्पष्टता की जरूरत है, साथ ही धर्मनिरपेक्षता पर नए नजरिए की दरकार है। भाजपा का अभी तक का सबसे अहम मुद्दा, राम मंदिर निर्माण अब हकीकत में तब्दील होने जा रहा है। ऐसे में पार्टी इन मुद्दों को चुनावों में भुनाने का शायद ही कोई मौका छोड़ेगी। इसे देखते हुए कांग्रेस के अंदर युवा और कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि पार्टी को अपनी मुस्लिम परस्त होने की छवि तोड़ने की बेहद जरूरत है, जो भाजपा की हिंदुत्व परस्त राजनीति की वजह से बन गई है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का कहना है, “हमें लोगों को यह समझाना होगा कि धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब हिंदू विरोधी होना नहीं है। साथ ही, जनता को यह भी समझाना होगा कि सनातन धर्म का असली संदेश सर्वधर्म समभाव है, जिसकी राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है।”

अंतरिम अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी का एक साल पूरा हो रहा है, तो पार्टी में फिर मांग उठ रही है कि उनके 50 वर्षीय बेटे को फिर से कमान सौंप देनी चाहिए। ऐसे में यह सवाल वाजिब हो उठता है कि क्या पिछले एक साल में कमान परिवर्तन से पार्टी के कामकाज में कोई वास्तविक बदलाव आया है? क्या सोनिया गांधी ने पिछले एक साल में चुपचाप यह कोशिश की है कि राहुल गांधी के 18 महीने के कार्यकाल में चली पीढ़ी परिवर्तन की मुहिम पलट दी जाए? पार्टी सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वापस लौटना पक्का है, लेकिन सोनिया अभी कुछ महीने कमान नहीं छोड़ने वाली हैं। हालांकि पार्टी में अब सभी नियुक्तियां राहुल गांधी के जरिए ही होती हैं और सोनिया गांधी प्रमुख रूप से संरक्षक की तरह ही हैं। वे अमूमन सहयोगी दलों के साथ सामंजस्य बनाए रखने और वरिष्ठ नेताओं के मन से उनके भविष्य की चिंताओं को दूर करने की भी कोशिश करती हैं। कभी-कभार बहुत जरूरत



नई पीढ़ी नाराज:
ज्योतिरादित्य
सिंधिया और सचिन
पायलट के कदमों
से उठे सवाल

होने पर असंतुष्ट नेताओं को शांत करने में भूमिका निभाती हैं। उन्होंने देर से ही सही, यह तय किया है कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और बाकी नेताओं को कामकाज में ज्यादा स्वायत्तता दी जाए और हर छोटे-बड़े फैसले के लिए उन्हें 10, जनपथ का रुख न करना पड़े। उदाहरण के तौर पर, सोनिया और राहुल ने उत्तर प्रदेश की सारी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड़ा पर छोड़ दी है और प्रियंका प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार 'लल्लू' पर कहीं ज्यादा भरोसा करती हैं।

लोकसभा चुनावों में लगातार दूसरी बार जब कांग्रेस की हार हुई तो पार्टी की कमान राहुल गांधी के पास थी। हार की जिम्मेदारी लेते हुए जब राहुल ने अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला किया तो उस समय उनके साथियों ने कांग्रेस कार्यकारिणी के

जरिए यह प्रस्ताव पारित कराया कि वे अपने फैसले पर दोबारा विचार करें। यही नहीं, कार्यकारिणी ने राहुल को इस बात की भी जिम्मेदारी दी कि वे पार्टी में आमूल-चूल बदलाव करें। हालांकि राहुल गांधी ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और एक खुला पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर भी सवाल खड़े किए जो चुनावों में मिली बुरी हार के बावजूद अपनी जिम्मेदारी लेने से बच रहे थे।

इसके बाद जब कार्यकारिणी ने सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी तो एक प्रस्ताव भी पारित किया गया कि वे संगठन स्तर पर पार्टी में अहम बदलाव करें। हालांकि इस बात को भी एक साल हो चुके हैं लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी अहम बदलाव की झलक नहीं दिखी है। इस दौरान जिले और राज्य स्तर पर पार्टी के अंदर कई अहम बदलाव जरूर हुए हैं। हालांकि पार्टी के स्तर पर हुए इन बदलावों पर न तो विरोधी मीडिया की नजर गई है और न ही पार्टी में मौजूद विरोधी तत्वों की नजर गई।

कांग्रेस महासचिव तथा राज्यसभा सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने आउटलुक को बताया कि पिछले छह महीने से करीब-करीब हर दूसरे हफ्ते पार्टी में कई अहम बदलाव किए गए हैं। जैसे, कर्नाटक

**सिंधिया और पायलट के विद्रोही
तेवर से पार्टी को समझ में
आ गया है कि वंशवाद और
वफादारी का हमेशा एक जैसा
नाता नहीं होता है**

**साधने की चुनौती:
फेरबदल के बीच
वरिष्ठों का भरोसा
बनाए रखना अहम**



में डी.के. शिवकुमार, उत्तर प्रदेश में अजय कुमार लल्लू, दिल्ली में अनिल चौधरी और गुजरात में हार्दिक पटेल को पार्टी की कमान सौंपी गई है। इसके अलावा सैकड़ों जिले और कई राज्यों में विभिन्न स्तर पर अहम नियुक्तियां की गई हैं, लेकिन इन पर किसी का ध्यान नहीं गया है। वेणुगोपाल का कहना है, इस तरह के अहम बदलाव केंद्रीय स्तर पर इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों की नियुक्तियां राहुल गांधी जब पार्टी अध्यक्ष थे, उस दौरान की गई थी। इन लोगों को नई जिम्मेदारी संभाले बमुश्किल दो साल हुए हैं। वे अफसोस जताते हुए कहते हैं कि पार्टी की जो कमियां सामने आती हैं, उन्हें तो प्रचारित किया जाता है लेकिन पार्टी के अंदर जो सकारात्मक पहल की जा रही है, उसे कोई तरजीह नहीं देता। राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले वेणुगोपाल का कहना है, “लोकसभा चुनावों के बाद जब प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में पार्टी की जिला इकाइयों को भंग किया तो उसकी चर्चा तो हर जगह हुई, लेकिन जब पिछले हफ्ते उन्होंने जिला स्तर पर नए अध्यक्ष और दूसरे पदाधिकारी नियुक्त किए तो उसकी कोई चर्चा नहीं दिखी।”

इन बदलावों के जरिए पार्टी की कोशिश है कि अहम पदों पर जमीन से जुड़े नेताओं को जिम्मेदारी मिले। यह लोगों के बीच बन गई उस छवि से

एकदम अलग है, जिसमें यह कहा जाता है कि पार्टी केवल वंशवाद को तरजीह देती है। वेणुगोपाल कहते हैं, “पार्टी में आया यह बदलाव राहुल गांधी के शुरू किए गए विजन का ही विस्तार है, जिसमें कोशिश रही है कि संगठन में ज्यादा से ज्यादा लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाए और प्रतिभावान लोगों को तरजीह दी जाए।”

राहुल गांधी के एक अन्य करीबी नेता का कहना है, “अगर आप यूपीए सरकार के दौर को देखें तो उस वक्त जिन युवा नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई, वे वंशवाद के सहारे आगे आए थे। इस श्रेणी में जितन प्रसाद, सचिन पायलट, मिलिंद देवड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग शामिल थे। उस दौरान मीनाक्षी नटराजन और मणिकम टैगोर जैसे जमीन से जुड़े युवा नेताओं को तरजीह नहीं मिली

**पार्टी में जमीनी स्तर के कई
नेताओं को तरजीह मिली है।
इस कड़ी में हार्दिक पटेल, अजय
कुमार लल्लू, राजीव सातव जैसे
नेताओं के नाम शामिल हैं**

थी। आज के दौर में भी कांग्रेस के लिए पायलट और देवड़ा जैसे नेता ही चुनौती पेश कर रहे हैं, जबकि टैगोर जैसे नेता उसी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। साफ है कि वंशवाद हमेशा विचारधारा के स्तर पर प्रतिबद्धता नहीं दिखाता है। शायद अब इस बात को कांग्रेस खुद भी समझ रही है।”

लॉकडाउन में श्रमिकों और प्रवासियों की मदद के लिए काफी तारीफ पा चुके और अभी बिहार में बाढ़ पीड़ितों के लिए काम कर रहे, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बी.वी. ने आउटलुक से बातचीत में कहा, “राजनीति में मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। मैं बूथ स्तर पर काम करता था, राहुल ने मुझे वहां से उठाकर भारतीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। अभी कांग्रेस को छोड़कर वे लोग जा रहे हैं, जिन्हें बिना कोई संघर्ष किए सब कुछ थाली में परोसा हुआ मिल गया था। वे जमीन पर काम करने से कतरा रहे हैं।”

श्रीनिवास और हाल ही में राज्यसभा के लिए चुने गए राजीव सातव जैसे कई युवा नेताओं को राहुल गांधी ने पार्टी में शुरू किए गए “प्रतिभा खोज” कार्यक्रम के तहत 2004 से 2009 के बीच चुना था। लेकिन उस दौरान राहुल गांधी को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का साथ नहीं मिला। इस वजह से पार्टी के अंदर चुनाव की प्रक्रिया थम गई। वेणुगोपाल कहते

हैं, “अब समय आ गया है कि युवाओं को नेतृत्व के लिए तैयार किया जाए। सातव, टैगोर, ज्योतिमणि, रम्या हरिदा, हिबी इदेन, जीतू पटवारी और हार्दिक पटेल जैसे नेताओं ने जमीन पर काफी काम किया है। इनमें से कोई भी राजनीति में पैसे या वंशवाद की वजह से नहीं आया है।”

कांग्रेस सचिव चंदन यादव का कहना है, “पार्टी केवल वंशवाद को बढ़ावा देती है, यह नजरिया इसलिए बना है क्योंकि मीडिया में एक ऐसा धड़ा है जो कांग्रेस की ऐसी छवि बनाना पसंद करता है। इसलिए बार-बार यही बातें प्रोजेक्ट की जाती हैं कि कांग्रेस के प्रमुख नेता वंशवाद से निकले हैं, जो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं और बहुत ही रईसी वाला जीवन जीते हैं, जबकि जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी में कोई पूछ नहीं है।” यादव कहते हैं, “टैगोर और हरिदास के अलावा राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम, झारखंड के मंत्री बादल पत्रलेख और गुजरात में विपक्ष के नेता परेश धनानी जैसे कई कांग्रेस नेता हैं जो बहुत ही साधारण परिवार से आए हैं। इन लोगों ने सड़क पर संघर्ष किया है। इन उदाहरणों के बावजूद मीडिया अपने पक्षपाती नजरिए को छोड़ने को तैयार नहीं है।”

जमीन से जुड़े नेताओं के आगे आने का असर पार्टी के मीडिया और सोशल मीडिया विभागों में भी दिखने लगा है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि जमीन से जुड़े मुद्दों को अब ज्यादा तरजीह मिल रही है, हालांकि अभी काफी कुछ करना बाकी है। पिछले साल सितंबर में कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख बने रोहन गुप्ता का कहना है, “पार्टी अपनी सोशल मीडिया रणनीति को नए सिरे से तैयार कर रही है। हम ऐसी रणनीति बना रहे हैं जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम आदमी से सीधा संवाद हो। हमने इसके अलावा ‘कांग्रेस के साथ’ एक नई पहल की है, जिसके तहत हम ऐसे पेशेवरों को जोड़ रहे हैं जो कांग्रेस के सक्रिय सदस्य नहीं हैं लेकिन कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन करते हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस का सोशल मीडिया एंगेजमेंट भाजपा के मुकाबले करीब 30 फीसदी तक बढ़ गया है।”

पिछले दो महीने में कांग्रेस ने ‘स्पीक अप’ के जरिए कई सारे अभियान चलाए हैं। इसके तहत तेल की बढ़ती कीमतों, छात्रों के मुद्दे, भारत-चीन के बीच लड़ाख को लेकर छिड़े विवाद और हाल ही में कांग्रेस शासित राज्यों में भाजपा के सरकार गिराने के षड्यंत्र वगैरह पर पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बनाए वीडियो को सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। गुप्ता का कहना है कि इन सभी वीडियो को बहुत अच्छा समर्थन मिला है। अकेले ट्विटर पर हर एक वीडियो कम से कम तीन लाख बार देखे गए।

जब कोरोना वायरस के बढ़ते को खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन का

ऐलान किया तो उस वक्त सोनिया गांधी ने सरकार द्वारा देरी से उठाए गए फैसले पर सवाल खड़े किए। पार्टी ने 11 सदस्यीय सलाहकार समूह का भी गठन किया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राहुल गांधी को भी शामिल किया गया। इस कदम के जरिए संदेश साफ था कि विभिन्न अहम मुद्दों पर पार्टी मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। इससे यह भी साफ हो गया कि राहुल गांधी एक बार फिर से पार्टी की रोजाना गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। समूह के कम से कम पांच सदस्य के.सी. वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, प्रवीण चक्रवर्ती, सुप्रिया श्रीनेत्र और गौरव वल्लभ की नियुक्ति राहुल गांधी की सिफारिश पर की गई है।

जिस तरह से मोदी सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने में शिथिलता दिखाई है, उससे पहले से ही लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था और बुरी स्थिति में पहुंच गई है। सलाहकार समूह के एक सदस्य का कहना है कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके जरिए राहुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परेशानी में डाल सकते हैं। पार्टी के मीडिया सेल से साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार पर हमला करने में कोई ढिलाई न बरती

1947 के बाद पहली बार गांधी-नेहरू परिवार से एक साथ तीन लोग राजनीति में हैं। सोनिया-राहुल-प्रियंका के सामने पार्टी को पटरी पर लाने की चुनौती

जाए, लेकिन यह भी संदेश है कि प्रधानमंत्री पर कोई व्यक्तिगत हमला न किया जाए, ताकि भाजपा को अपनी कमियां छुपाने का कोई मौका नहीं मिले। राहुल ने 12 फरवरी को जब सरकार पर कोरोना महामारी से सही से नहीं निपटने का आरोप लगाया तो उन्होंने यही कहा कि वे सकारात्मक आलोचना के जरिए ही आगे बढ़ेंगे।

कांग्रेस के ज्यादातर प्रवक्ताओं के बारे में ऐसी राय है कि वे भाजपा प्रवक्ताओं के तीखे हमले पर रक्षात्मक रवैया अपना लेते हैं, लेकिन उनमें भी अब काफी बदलाव दिख रहा है। लड़ाख में भारत-चीन सीमा विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुरू में संकट पर ज्यादा गंभीर न दिखने वाले बयान ने भी कांग्रेस प्रवक्ताओं को भाजपा पर तीखा हमला करने का मौका दे दिया। मोदी ने 19 जून को यह बयान दिया था कि चीन ने गलवन घाटी में कोई घुसपैठ नहीं की है, जबकि उसके ठीक चार दिन पहले ही 20 भारतीय सैनिक, चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में मारे गए थे। इस घटना ने पार्टी प्रवक्ताओं को कांग्रेस पर 1962 में चीन से मिली हार के धब्बे से

उबरने का भी मौका दे दिया।

जिस तरह पार्टी की विभिन्न राज्य इकाइयों में जमीन से जुड़े नेताओं की नियुक्ति हुई, उससे पार्टी में किसी रणनीति के लेकर जो एकरूपता में कमी आ रही थी, उसे भी दूर करने में काफी मदद मिली है। पार्टी के अनेक नेताओं का मानना है कि इन कदमों से साफ है कि राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष पद की कमान संभालने वाले हैं। साथ ही उनकी ताजपोशी बिना किसी बड़े उलटफेर के शांति से की जाएगी। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है, “भले ही पार्टी में कई अहम बदलाव की शुरुआत हो गई है, लेकिन अब भी चुनाव जीतना हमारे लिए चुनौती है। अगले दो साल में बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसमें बिहार और पश्चिम बंगाल में हम मुख्य विपक्षी दल नहीं हैं जबकि उत्तर प्रदेश में हमें अभी नहीं पता है कि प्रियंका गांधी के प्रयासों का कितना फायदा मिलेगा।”

वरिष्ठ पत्रकार तथा कांग्रेस से राज्यसभा सांसद कुमार केतकर पार्टी की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए कहते हैं, “कांग्रेस पार्टी का मौजूदा संकट केवल नेतृत्व का नहीं है, बल्कि इस समय वह अपनी विचारधारा को लोगों को नहीं समझा पा रही है। भाजपा ने राजनीति को नया रूप दिया है और वह जिस तरह से ध्रुवीकरण, विभाजनकारी और घृणा फैलाने वाली राजनीति कर रही है, उसे चुनौती देने के लिए कांग्रेस को अपनी धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी राजनीति को जमीनी स्तर तक पहुंचाना होगा, जिससे देश में एक जन आंदोलन खड़ा हो सके।” एक अन्य वरिष्ठ नेता ने आउटलुक को बताया कि संगठन में बदलाव करने से कोई इनकार नहीं करता है लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि नई पीढ़ी को तैयार करने के चक्कर में हम कहीं चुनावों में बड़ा नुकसान नहीं उठा लें, क्योंकि अगर आपकी चुनावों में एक बार प्रासंगिकता खत्म हो जाती है तो फिर किसी बात का महत्व नहीं रह जाता है। इस समय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि वह सबसे पहले नेताओं के बीच संवाद को बढ़ावा दे, जिसमें वरिष्ठ और कनिष्ठ का भेद न रहे और सार्वजनिक तौर पर पार्टी किसी मुद्दे पर बंटी हुई नजर न आए।

केतकर गांधी परिवार के नेतृत्व पर एक और अहम बात कहते हैं, “मौजूदा परिस्थितियों में नेहरू-गांधी परिवार के नेतृत्व में आगे बढ़ना ही सबसे अच्छा दांव है, क्योंकि 1947 के बाद से केवल एक बार, 1991-97 का समय रहा है जब नेहरू-गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं था। उस समय पार्टी की स्थिति क्या थी, यह जगजाहिर है। आज तो सोनिया-राहुल-प्रियंका तीन लोग इस परिवार से राजनीति में हैं। अब सवाल यही है कि यह तिकड़ी क्या पार्टी को रास्ते पर ला पाएगी।”





आरोप-प्रत्यारोप: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ठाकरे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश में जांच को लेकर ठनी, सुशांत के पिता के.के. सिंह (बीच में)

गिरिधर झा

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने कथित अवसाद के कारण आत्महत्या की या किसी साजिश के तहत उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया? क्या उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान ने भी खुदकुशी की, या उनकी भी निर्मम हत्या की गई? महज छह दिन के अंतराल में दोनों घटनाओं के तार क्या जुड़े हैं? क्या दिशा अपनी मौत के पहले किसी पार्टी में फिल्म इंडस्ट्री की कुछ हस्तियों और रसूखदार लोगों के साथ मौजूद थीं? वहां उनके साथ क्या हुआ? क्या सुशांत दिशा की मौत से संबंधित कुछ रहस्यों काटने वाले थे? सुशांत की गर्लफ्रेंड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की भूमिका इस केस में क्या है? क्या उन्होंने वाकई अपने परिजनों के साथ मिलकर सुशांत के पैसों का गबन किया?

ये कुछ ऐसे सवाल हैं, जिन्होंने सुशांत की हत्या या आत्महत्या को देश की सबसे बड़ी और पेचीदा 'क्राइम मिस्ट्री' बना दिया है। देश और विदेश में

मौत पर मंडराता रहस्य

सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या की उलझी गुत्थी की जांच पर भिड़े बिहार और महाराष्ट्र

सुशांत के लाखों चाहने वालों ने उन्हें ईसाफ दिलाने की मुहिम चला रखी है। उनके अनुसार, मुंबई पुलिस ने सुशांत केस की पड़ताल में घोर लापरवाही बरती है, जिसकी पेशेवराना अंदाज के लिए तुलना अक्सर स्कॉटलैंड यार्ड से की जाती है। मीडिया में भी इस केस का ट्रायल बदस्तूर जारी है।

यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। पांच अगस्त को इस केस की सुनवाई के दौरान न्यायालय

ने मुंबई पुलिस से जांच के दौरान की गई कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट मांगी है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि बिहार सरकार की इस केस को सीबीआई को सौंपने की अनुशंसा मान ली गई है। गौरतलब है, महाराष्ट्र सरकार सुशांत केस को सीबीआई को सौंपने का लगातार विरोध कर रही है। उसका मानना है कि मुंबई पुलिस पेशेवर तरीके से जांच कर रही है। इस मुद्दे पर उसकी बिहार सरकार से ठन भी गई है, क्योंकि पटना पुलिस ने भी स्वतंत्र रूप से इस केस की जांच शुरू कर दी है।

देश के इतिहास में संभवतः यह पहला मौका है, जब दो राज्य किसी मौत की जांच के मुद्दे पर इस तरह आमने-सामने आ गए हैं। यह सब आखिर हुआ कैसे? जिस मौत को प्रथम दृष्टया खुदकुशी का मामला बताकर मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की और अगले डेढ़ महीनों से ज्यादा तक यही मानती रही, वह मामला इतने जटिल रूप में कैसे बदल गया?

दरअसल मुंबई के बांद्रा में पिछले 14 जून को 34 वर्षीय अभिनेता अपने फ्लैट में मृत पाए गए। इसके बाद इसे आत्महत्या का मामला मानते हुए वहां की पुलिस ने जांच शुरू की। बताया गया कि पिछले कुछ महीनों से वे डिप्रेशन का इलाज करा रहे थे और दवा भी ले रहे थे। उनकी मौत से आहत उनके कुछ प्रशंसकों ने बॉलीवुड में भाई-भतीजावाद और गुटबाजी को सुशांत के अवसाद और बाद में उनकी मौत का कारण माना। उनका कहना था कि पिछले साल छिछोरे जैसी सुपरहिट फिल्म देने के

बाद भी सुशांत के पास कोई नई फिल्म नहीं थी। यही नहीं, यह भी आरोप लगाया गया कि फिल्म इंडस्ट्री के कतिपय बड़े निर्माता उन्हें 'बाहरी' होने के कारण आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे। शेखर कपूर जैसे मशहूर फिल्मकार ने भी इसके संकेत दिए, जो सुशांत के साथ अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म *पानी* बनाना चाहते थे। सोशल मीडिया पर जब बॉलीवुड के अंदर भाई-भतीजावाद के खिलाफ स्वतःस्फूर्त दिखने वाली मुहिम चलने लगी, तो मुंबई पुलिस ने इसे आधार बनाते हुए आदित्य चोपड़ा, महेश भट्ट और संजय लीला भंसाली सहित कई चर्चित हस्तियों से पूछताछ शुरू की।

इस केस में अचानक नया मोड़ तब आया, जब दिवंगत अभिनेता के पिता के.के. सिंह की शिकायत पर सुशांत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके कुछ परिजन के खिलाफ पटना पुलिस ने स्थानीय राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज की। उन्होंने रिया पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने और करोड़ों रुपये के गबन का आरोप लगाया। उनका कहना था कि मुंबई पुलिस इस केस की सही तरीके से जांच नहीं कर रही है। इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद बिहार पुलिस ने फौरन एक चार-सदस्यीय टीम जांच के लिए मुंबई रवाना कर दी।

महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को यह नागवार गुजरा। उनका मानना था कि इस मामले की जांच बिहार पुलिस के अधिकार क्षेत्र के बाहर है, क्योंकि घटना मुंबई में हुई है। उनका तर्क था कि कानूनन पटना पुलिस सुशांत के पिता की शिकायत पर दर्ज एफआईआर मुंबई पुलिस को भेजती, क्योंकि इस केस से संबंधित जांच यहां चल रही है। हालांकि बिहार पुलिस की अपनी दलील है। उनका कहना है कि मुंबई पुलिस अभी तक सुशांत की मृत्यु को मात्र आत्महत्या मान कर जांच कर रही है और इस संबंध में उन्होंने एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की है। उनका दावा था कि सुशांत के पिता ने अपने पुत्र के निधन से संबंधित केस पटना में दर्ज किए हैं, इसलिए बिहार पुलिस का यह दायित्व बनता है कि वह इसकी गंभीरतापूर्वक तहकीकात करे।

इसके बाद मामले ने बड़े विवाद का रूप ले लिया। बिहार के पुलिस महानिरीक्षक गुप्तेश्वर पांडेय ने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस पटना से गई टीम के साथ सहयोग नहीं कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मुंबई पुलिस ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जैसे जरूरी कागजात साझा करने से भी इनकार कर दिया और जांच के लिए उनकी टीम को मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया नहीं कराईं। मुंबई पुलिस के कथित असहयोगात्मक रवैये के मद्देनजर बिहार पुलिस ने बाद में एक आईपीएस अधिकारी, पटना मध्य

के सिटी एसपी विनय तिवारी को मुंबई भेजने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि वरिष्ठ अधिकारी के जाने से दोनों राज्यों की पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो जाएगा। लेकिन तिवारी के मुंबई पहुंचने के कुछ घंटे बाद ही बृहन्मुम्बई नगर निगम (बीएमसी) ने उन्हें चौदह दिनों के लिए क्वारंटीन कर



विवाद के नुक्ते: विनय तिवारी और उनके हाथ पर लगी मुहर, दिशा सालियान, सुशांत और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह

दिया। यही नहीं, उनके हाथ पर इस अवधि में बाहर न निकलने के आशय वाली मुहर भी लगा दी, ताकि वे कहीं आ-जा न सकें। बिहार पुलिस ने इसे अपने अधिकारी को नजरबंद करने की संज्ञा दी। इधर, रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पटना में उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को मुंबई स्थानांतरित करने की गुहार लगाई। इसके बाद बिहार

और महाराष्ट्र की सरकारों ने भी इस संबंध में उनकी दलीलें सुनने के लिए कैविएट दायर की।

रिया सुशांत के साथ लिव-इन रिलेशन में थीं। लेकिन उनकी मौत के मात्र छह दिन पहले ही वे उन्हें छोड़कर अपने घर वापस आ गई थीं। सुशांत के परिवार ने उन पर आरोप लगाया है कि वे सुशांत को उनसे मिलने और बातचीत नहीं करने देती थीं। इस आरोप-प्रत्यारोप के बीच, सुशांत के पिता के अनुरोध पर बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने केंद्र से इस केस को सीबीआई को सौंपने की अनुशंसा कर दी।

इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को सूचित किया कि सीबीआई जांच की बिहार सरकार की अनुशंसा स्वीकार कर ली गई है। खबरों के अनुसार, सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मुंबई पुलिस को कहा कि एक आईपीएस अधिकारी को क्वारंटीन करने से गलत मैसेज गया है। कोर्ट ने मुंबई पुलिस को, सुशांत केस से संबंधित जांच की प्रगति संबंधी रिपोर्ट तीन दिनों में पेश करने का भी आदेश दिया। इसके साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय ने रिया को तत्काल किसी भी तरह की मोहलत नहीं दी। अब सारी नजरें उच्चतम न्यायालय के अगले आदेश पर हैं।

सुशांत की मौत के मामले में परिजन और प्रसंशक आशान्वित हैं कि सीबीआई जांच दिवंगत अभिनेता के मौत के रहस्य को उजागर करेगी। हालांकि अपनी एफआईआर में सुशांत के पिता ने रिया और उसके परिजनों पर सुशांत को आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए आरोपित किया है। अभिनेता के कई प्रशंसक उनकी 'हत्या' को उनकी मौत से छह दिन पहले हुई उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की कथित आत्महत्या से जोड़ रहे हैं। हालांकि दिशा के पिता ने मुंबई पुलिस को लिखे पत्र में की गई जांच से कोई असंतोष नहीं जताया है। सोशल मीडिया में ऐसे कई आरोप लग रहे हैं कि दिशा ने आत्महत्या से पहले सुशांत के साथ कुछ राज साझा किए थे, जिसे वह उसकी मौत के बाद दुनिया को बताना चाहते थे और इसी वजह से उनकी 'हत्या' कर दी गई।

मुंबई पुलिस के अधिकारी हालांकि इससे इत्तेफाक नहीं रखते। महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ पार्टी शिवसेना का कहना है कि आगामी बिहार चुनाव के मद्देनजर सुशांत की मौत को राजनैतिक रंग दिया जा रहा है, ताकि जद-यू और भाजपा गठबंधन को इसका फायदा मिल सके। सुशांत की मौत पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और अफवाहों का बाजार गर्म है। अब जब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है, लोगों को एक युवा और चर्चित अभिनेता की मौत की निष्पक्ष जांच की उम्मीद है, जो इस गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझा कर केस को तार्किक परिणति तक पहुंचा सके।

कोरोना काल में बाढ़ की डूब

बाढ़ प्रभावित 45 लाख लोगों के लिए सिर्फ 19 राहत शिविर, यहां दो गज की दूरी रखना मुमकिन नहीं

नीरज झा

बाढ़... यानी सालाना संकट काल, जो इस कोरोना काल में आमजन के लिए विकराल विपदा बनकर टूटी है। अलबत्ता, पी. सईनाथ की प्रसिद्ध किताब *एवरीवन लव्स गुड ड्रॉट* की तर्ज पर कहे तो बाढ़ सत्ता में बैठे हर किसी के लिए संभावनाओं के द्वार भी खोल देती है। हर साल की तरह एक बार फिर बिहार, असम और पूर्वोत्तर के कई राज्य इसकी चपेट में हैं। बिहार के 38 में से 16 जिलों में 66 लाख लोग प्रभावित हैं। उससे पहले बाढ़ ने असम में विकराल रूप दिखाया। वहां के कुल 33 जिलों में से 21 जिले बुरी तरह प्रभावित हैं। कुछ दिनों पहले तक 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप था। वहां अब तक 108 लोगों की मौत हो चुकी है और अब भी करीब 11 लाख लोग प्रभावित हैं। पूर्वोत्तर के इस राज्य में तो बाढ़ का पानी उतार पर है, लेकिन बिहार में यह अपनी

भयावहता दिखा रहा है। सबसे अधिक प्रभावित जिले दरभंगा और मुजफ्फरपुर हैं। दरभंगा में बागमती और कमला बलान नदियों ने कहर बरपा रखा है। यहां 15 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित है। मुजफ्फरपुर में भी 11 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और मधुबनी जिले भी बाढ़ की चपेट में हैं।

जाने-माने पर्यावरणविद, बाढ़ एवं सिंचाई अभियंता और जलतत्व विशेषज्ञ डॉ. दिनेश कुमार मिश्र कहते हैं, “बाढ़ सत्ता, नौकरशाह और ठेकेदारों के लिए हर साल अरबों की कमाई और बंदरबांट का पुख्ता साधन है। इसलिए सरकार इसे जीवित रखना चाहती है और अपनी जिम्मेदारियों से भागती है।” हर साल रणनीतियां बनाई जाती रही हैं, बांध की मरम्मत और रखरखाव के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, लेकिन 21वीं सदी में भी यह चुनौती जस-की-तस है।

एक तरफ बाढ़ तो दूसरी तरफ कोरोना। इससे संक्रमित लोगों की संख्या में तेज इजाफे को देखते हुए बिहार सरकार ने लॉकडाउन 16 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। हर दिन तीन हजार के करीब नए मरीज सामने आ रहे हैं। राजधानी पटना और मुजफ्फरपुर की स्थिति ज्यादा भयावह है। पटना में हर दिन 400 और मुजफ्फरपुर में 200 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं।

कोरोना के बढ़ रहे मामले और बाढ़ के कहर से स्थिति चिंताजनक हो गई है, लेकिन सरकारी इंतजामात नाकाफी दिख रहे हैं। राज्य में 45 लाख लोग बाढ़ से

सभी फोटो: नीरज झा



कहां जाऊं: मुजफ्फरपुर में बाढ़ का पानी भरने के बाद घर से सामान निकालता एक परिवार



आपदा: तिरहुत नहर का तटबंध टूटने के बाद जमा भीड़, (दाएं) सामुदायिक रसोई का दृश्य

प्रभावित हैं, जबकि उनके लिए सिर्फ 19 राहत शिविर बनाए गए हैं। बाढ़ प्रभावित 14 जिलों में से सिर्फ चार में राहत शिविर हैं। यही हाल सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली सामुदायिक रसोई का है। चार जिलों में एक भी सामुदायिक रसोई नहीं है। शेष प्रभावित जिलों में एक हजार से अधिक रसोई संचालित की जा रही हैं। यानी हर सामुदायिक रसोई पर चार हजार लोग आश्रित हैं। सरकारी राहत के नाम पर सिर्फ तिरपाल जिसके नीचे कई कुन्बे साथ बैठने को मजबूर हैं। कहीं-कहीं सामुदायिक रसोई भी हैं, पर हर रसोई पर हजारों लोगों का बोझ है। इस हाल में एक वक्त के भोजन की आस लगाए लोग दो-गज की दूरी का क्या पालन करें। उन्हें कोरोना पकड़ भी ले तो क्या, कहीं कोई टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं। फसलों की बर्बादी का तो कोई आकलन ही नहीं है। कोरोना और बाढ़ की दोहरी मार झेल रहे बिहार की आज यही हकीकत है।

मुजफ्फरपुर शहर से करीब पांच किलोमीटर दूर रजवाड़ा बांध पर बाढ़ पीड़ितों ने बसेरा बना रखा है। सरकारी दावों की पोल खोलते हुए लोग बताते हैं, “एक तिरपाल में पांच-दस लोग एक साथ रहने को मजबूर हैं। महामारी की वजह से कोई भी संस्थान राहत सामग्री देने नहीं आ रहा है। सरकार सोई हुई है। स्वास्थ्य सुविधाएं नदारद हैं। हमलोगों की टेस्टिंग नहीं हुई है। बारिश ने भी कहर ढा रखा है। डर से रात में नींद नहीं आती, पता नहीं कब बांध टूट जाए।” बांध पर ही एक सामुदायिक रसोई चल रही है जिसका जिम्मा रजवाड़ा पंचायत के उपमुखिया गणेश सहनी के पास



बिहार में बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित जिले और प्रभावित लोगों की संख्या

दरभंगा	15,33,660
मुजफ्फरपुर	11,44,310
पूर्वी चंपारण	7,09,368
सारण	2,52,000
गोपालगंज	2,28,713
पश्चिम चंपारण	1,43,283
समस्तीपुर	1,20,500

स्रोत: आपदा प्रबंधन विभाग, आंकड़े 31 जुलाई 2020 के

है। रसोई के इर्द-गिर्द दो सौ से अधिक बच्चे, बूढ़े और महिलाएं बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के खाना तैयार होने का इंतजार कर रहे हैं। सहनी बताते हैं, “क्या करें, लोग मानते ही नहीं। सुबह से डेढ़ क्विंटल चावल बन चुका है। लोगों को समझाते हैं कि लाइन में लग जाइए, लेकिन भूख के आगे कौन सुनता है?”

सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों को लेकर जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के प्रवक्ता अजय आलोक कहते हैं, “सौभाग्य की बात है कि बाढ़ ग्रस्त इलाकों से कोरोना के मामले अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन यह चुनौती है। लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। यह व्यावहारिक नहीं कि किसी का घर डूब गया हो, वह बांध पर शरण लिए हो और उसे सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया जाए। सरकार की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को सख्ती के साथ कोरोना और बाढ़ से बचाव के निर्देश दिए गए हैं।”

बिहार आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत राहत के अनुसार जहां जरूरत नहीं वहां शिविर नहीं बनाए गए या हटा लिए गए हैं। सामुदायिक रसोई में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना मुश्किल है। इसलिए, कोरोना महामारी के बढ़ रहे प्रकोप को देखते हुए 30 जुलाई से इन जगहों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू किया गया है।

बिहार में हर साल बाढ़ से मौतें होती हैं। इस वर्ष अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। साल 2017 में भी बाढ़ ने ऐसी ही तबाही मचाई थी। फर्क बस इतना है कि इस बार लोगों को जानलेवा कोरोना वायरस की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। बीते चार वर्षों में करीब एक हजार लोगों ने बाढ़ में जान गंवाई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2019 में करीब 150 लोगों की मौत हुई थी और 17 जिलों की करीब पौने दो करोड़ आबादी प्रभावित हुई थी। सरकार हर साल बाढ़ रोकने के लाखों दावे करती है, लेकिन हर साल वे तमाम दावे उसी बाढ़ में बह जाते हैं।

केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में इस वक्त 5,254 बड़े बांध हैं और 447 निर्माणाधीन हैं। सरकार बांध को बाढ़ से बचाव का कवच मानती है, लेकिन विशेषज्ञ इसे ही विनाश का कारण मानते हैं। बाढ़ मुक्ति अभियान को लेकर दो दशक से भी अधिक समय से काम कर रहे विशेषज्ञ डॉ. दिनेश कुमार मिश्र बताते हैं, “नदियों को हम बांध नहीं सकते। पहले बाढ़ ढाई दिनों के लिए आती थी, लेकिन बांध निर्माण के बाद ये ढाई महीने की मुसीबत बन गई। नदी में जल स्तर बढ़ने के साथ पानी अपना रास्ता खुद खोज लेता था। सरकार ने बांध निर्माण तो किया, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि ये पानी जाएगा कहाँ।” बाढ़ पर दर्जनों किताब लिखने वाले डॉ. मिश्र बताते हैं कि इस हाल के लिए सीधे तौर पर सरकार की गलत नीतियां और कुप्रबंधन जिम्मेदार हैं। बांध, बैराज, तटबंध बनाकर नदियों के दायरे को सीमित कर दिया गया, जिससे फायदे के बदले केवल नुकसान हुआ।

संकट कोरोना का, सुर्खियां चुनाव की

कोरोना संक्रमण पर जल्द ही काबू न किया गया तो लोगों के बढ़ते गुस्से का सत्तारूढ़ गठबंधन को उठाना पड़ सकता है खामियाजा



पीटीआइ

गिरिधर झा

बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव शुरू होने में लगभग तीन महीने ही बचे हैं, लेकिन निरंतर बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण इसके नियत समय पर होने पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुआई में सत्तारूढ़ एनडीए के प्रमुख घटक दलों— जनता दल—यूनाइटेड (जद-यू) और भाजपा ने तो चुनाव की तैयारियां जोर-शोर से शुरू भी कर दी हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में गठित महागठबंधन का मानना है कि अभी जनता के बीच

जाने का माकूल समय नहीं है। विपक्ष का कहना है कि ऐसे समय में, जब कोरोनावायरस संक्रमण ने विकराल रूप धारण कर लिया है और राज्य में मृतकों की संख्या दिनोदिन बढ़ती जा रही है, चुनाव करवाना प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा।

अपने पिता लालू प्रसाद के अनुपस्थिति में राजद की कमान संभालने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया है कि नीतीश अपनी कुर्सी बरकरार रखने के लिए लाशों के ढेर पर चुनाव करवाना चाहते हैं। उनके अनुसार, बिहार कोरोना संक्रमण से सबसे बुरी तरह से ग्रस्त है और स्वास्थ्य विशेषज्ञों को आशंका है कि जांच की संख्या अत्यंत कम होने और लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से आने वाले दिनों में यहां अनगिनत मौतें होंगी। इसलिए यह समय

चुनाव के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।

हाल ही में लिखे एक ब्लॉग में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कोरोना की भयावहता की परवाह न करते हुए महज अपने पद के नवीनीकरण की जुगत में लगे हैं। वे कहते हैं, “उन्हें बिहारवासियों के स्वास्थ्य की बिलकुल चिंता नहीं है, अगर चिंता है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी की। हम लाशों की ढेर पर चुनाव नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि तीन महीने बाद लोग पोलिंग बूथ की बजाय श्मशान जाएं।”

लेकिन बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी तेजस्वी की तुलना ऐसे कमजोर विद्यार्थी से करते हैं जो परीक्षा टालने के बहाने सदैव खोजता रहता है। वे कहते हैं, “विधानसभा चुनाव समय पर

बढ़ते मामले: जुलाई में कोरोना संक्रमण में उछाल आया तो लॉकडाउन एक माह बढ़ा

हों या टल जाएं, एनडीए चुनाव आयोग के निर्णय का पालन करेगा। हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसे कमजोर विद्यार्थी परीक्षा टालने के मुद्दे खोजते हैं, वैसे ही राजद अपनी संभावित हार को देखते हुए चुनाव टालने के बहाने खोज रहा है।”

सुशील मोदी के अनुसार, चुनाव में तीन महीने से ज्यादा का समय है, इसलिए इस मुद्दे पर ज्यादा सोचने के बजाय कोरोना संक्रमण से निपटने पर ध्यान देना चाहिए। एनडीए नेताओं का कहना है कि इस संबंध में चुनाव आयोग का जो भी फैसला होगा, वह सबको मान्य होना चाहिए। लेकिन एनडीए का घटक दल, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी विपक्ष के साथ है। पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है कि कोरोना संक्रमण के कारण न सिर्फ लोगों को खतरा होगा बल्कि मतदान प्रतिशत भी काफी कम होगा।

चुनाव आयोग के लिए यह फैसला आसान नहीं है। उसने पिछले महीने नियत समय पर चुनाव होने की बात कही थी, लेकिन विपक्ष का कहना है कि परिस्थितियां अब बिलकुल बदल गई हैं। वे डिजिटल माध्यम से भी चुनाव कराने का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल, आयोग ने राज्य के प्रमुख राजनैतिक दलों से चुनाव प्रचार के तरीकों को लेकर उनके सुझाव

सोनू किशन



सोनू किशन



पीटीआर



अपने-अपने रंग:
नीतीश पर तेजस्वी
(बीच में) का आरोप
कि वे राष्ट्रपति शासन
से डर रहे हैं, चिराग
पासवान भी अभी
चुनाव के खिलाफ

मांगे हैं, ताकि इस संबंध में कोई फैसला किया जा सके। पिछले सप्ताह, राजद समेत नौ विपक्षी दलों ने आयोग को एक ज्ञापन सौंपकर कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखकर ही चुनाव संबंधी कोई निर्णय लेने का आग्रह किया था।

इसमें दो मत नहीं कि बिहार में जुलाई में कोरोना संक्रमण की संख्या में अचानक उछाल आया है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई—सी लगती है। चार अगस्त तक यहां संक्रमितों की संख्या 60 हजार तक पहुंच गई। 16 जुलाई से पूरे बिहार में एक महीने के लिए फिर लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन स्थिति संभलने का नाम नहीं ले रही है। पटना स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) सहित तमाम राजकीय अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। पिछले दिनों बिहार सरकार के गृह विभाग में कार्यरत अवर सचिव उमेश रजक का एम्स के बाहर भर्ती होने का इंतजार करने का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसने स्थिति की भयावहता को उजागर किया। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल में उनकी भर्ती तो हो गई लेकिन उन्हें बचाया न जा सका। राज्यभर से ऐसे कई मामले प्रकाश में आए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नीतीश सरकार ने पटना के कई निजी अस्पतालों में कोरोना का इलाज करने की पहल की है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार यह कहना मुश्किल है कि स्थिति आगामी चुनाव तक नियंत्रण में आ जाएगी।

विपक्ष ने मुख्यमंत्री पर निजी राजनैतिक स्वार्थों के कारण कोरोना संकट की अवहेलना करने का आरोप लगाया है, लेकिन इससे बेअसर, जद-यू और भाजपा ने वर्चुअल रैलियों के साथ प्रचार शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री खुद 7 अगस्त से वर्चुअल चुनाव

प्रचार का आगाज करने वाले थे, लेकिन फिलहाल इसे टाल दिया गया है। दूसरी ओर, राजद या इसकी किसी सहयोगी पार्टी ने डिजिटल प्रचार के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। तेजस्वी का कहना है कि अगर भाजपा-जद-यू पूरी तरह आस्वस्त हैं कि बिहार में कोरोना कोई समस्या नहीं है और चुनाव समय पर ही होने चाहिए, तो उन्हें वर्चुअल नहीं, परंपरागत रूप से चुनाव प्रचार करने की पैरवी करनी चाहिए। वे कहते हैं, “मैं नीतीशजी की मनःस्थिति समझ रहा हूँ। वे डर रहे हैं कि अगर किसी कारणवश चुनाव टलता है तो राष्ट्रपति शासन में भाजपा उनके साथ वह सब करेगी, जो उन्होंने पिछले वर्षों में भाजपा के साथ किया।”

रांची के अस्पताल में इलाजरत, चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू यादव ने भी नीतीश और जद-यू नेताओं की वर्चुअल रैलियों पर ट्विटर के जरिए निशाना साधा है। राजद प्रमुख ने ट्वीट किया, “बिहार में कोरोना के कारण स्थिति दयनीय, अराजक और विस्फोटक है। स्वास्थ्य व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। कोरोना नियंत्रण के लिए सरकार को बाज बनना था लेकिन जद-यू नेता लोगों का शिकार करने के लिए ‘गिद्ध’ बनकर रैली कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चार महीने में चार बार भी आवास से बाहर नहीं निकले।”

बिहार में नवंबर के अंतिम सप्ताह में नई सरकार का गठन हो जाना निर्धारित है। राजनैतिक विशेषज्ञों के अनुसार, चुनाव टलने की स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और उस अवधि में सत्ता की बागडोर परोक्ष रूप से भाजपा के हाथों होगी। एनडीए नेता राजद नेताओं के चुनाव टालने के तर्क को हास्यास्पद करार देते हैं। जद-यू के प्रधान राष्ट्रीय महासचिव के.सी. त्यागी कहते हैं कि जब अमेरिका

में इस परिस्थिति में चुनाव हो सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं? वे इसे विपक्ष का डर और घबराहट से उपजा कुतर्क करार देते हैं। जवाब में तेजस्वी पूछते हैं कि क्या माननीय मुख्यमंत्री बिहार में अमेरिका से अधिक लोगों को मरवाना चाहते हैं? वे यह भी कहते हैं कि अमेरिका में चुनाव परंपरागत रूप से बलेट पेपर से होते हैं, न कि ईवीएम से। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भी अब अपने देश में चुनाव स्थगित करने की वकालत करने लगे हैं। राजद नेताओं का यह भी कहना है कि बिहार में मात्र 34 प्रतिशत आबादी के पास स्मार्टफोन हैं, इसलिए डिजिटल माध्यम से चुनाव होने पर बहुत सारे लोग वोट देने के अधिकार से वंचित हो जाएंगे।

राजद की परंपरागत ढंग से चुनाव करने की मांग को खारिज करते हुए सुशील मोदी कहते हैं कि बिहार में चुनावों में धनबल और बाहुबल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कांग्रेस और राजद ने ही किया। “जिनके राज में बिहार बूथलूट और चुनावी हिंसा के लिए बदनाम था, वे आज अपने दाग धोना चाहते हैं। ज्ञापन देने वाले बताएं कि बलेट पेपर के पुराने तरीके से चुनाव करने की मांग क्यों की जा रही है? मतपेटी से लालू का जिन निकलने का वह दौर क्या चुनाव की पारदर्शिता का परिणाम था?”

एनडीए का कहना है कि बिहार चुनाव पर निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ चुनाव आयोग को है। भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद का मानना है कि चुनाव आयोग स्वच्छ, स्वतंत्र और सुरक्षित चुनाव कराने को प्रतिबद्ध है। वे कहते हैं, “लोकतंत्र के लिहाज से समय पर चुनाव कराना चुनाव आयोग की चिंता है। कोरोना के दौर में सुरक्षित चुनाव को लेकर चुनाव आयोग काम कर रहा है।”

राजनैतिक विश्लेषकों के अनुसार कोरोना का बढ़ता संकट चुनाव के पूर्व नीतीश सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप उभरा है। अगर कोरोना पर जल्दी काबू न किया गया, तो लोगों के बढ़ते गुस्से का खामियाजा सत्तारूढ़ गठबंधन को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उठाना पड़ सकता है। फिलहाल सस्पेंस की स्थिति बरकरार है।



कमजोर विद्यार्थी की तरह राजद अपनी संभावित हार को देखते हुए बहाने खोज रहा है सुशील कुमार मोदी उपमुख्यमंत्री, बिहार

रांची से नवीन कुमार मिश्र

राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो)-कांग्रेस गठबंधन सरकार में अनबन की खबरों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक साथ कई मोर्चों पर जूझना पड़ रहा है। एक तरफ कोविड-19 का बढ़ता संक्रमण है, तो दूसरी तरफ सहयोगी पार्टी कांग्रेस का सरकार पर दबाव है। कांग्रेस सरकार में हिस्सेदारी को लेकर दबाव बना रही है, लेकिन पार्टी के भीतर भी खींचतान चल रही है। इससे राजनैतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। गठबंधन सरकार को बने अभी

बहुत दिन नहीं हुए हैं, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तथा राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने यह कहकर तहलका मचा दिया कि कांग्रेस के चार विधायकों पर भाजपा डोरे डाल रही है। सूत्रों का कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सरकार अस्थिर हो सकती है। इसके पीछे कांग्रेस असंतुष्टों का वह दावा है, जिसमें उनका कहना है कि नौ विधायक उनके साथ हैं। नौ विधायकों के एकजुट होने का मतलब हेमंत सरकार

दबाव और खींचतान की उलझन

गठबंधन सहयोगी कांग्रेस का सोरेन सरकार पर दबाव बढ़ा, तो भाजपा भी सक्रिय हुई

के लिए चिंता का विषय है।

हालांकि रामेश्वर उरांव के बयान को दबाव की राजनीति के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि उरांव के बयान के एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने 18 आइएएस अधिकारियों का तबादला किया था। इन तबादलों में ज्यादातर जिलों के उपायुक्त बदले गए थे। इससे पहले अप्रैल में एक साथ 35 आइपीएस के ट्रांसफर हुए थे। लेकिन इन तबादलों को अलग नजरिए से देखा जा रहा है। खुद रामेश्वर उरांव के विभाग के 70 वाणिज्यिक अधिकारी बदले गए हैं। वहीं कांग्रेस के ही ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने 90 प्रखंड विकास अधिकारियों का तबादला कर दिया। कांग्रेस से ही आने वाले स्वास्थ्य मंत्री बना गुप्ता ने कई सिविल सर्जनों और चिकित्सा पदाधिकारियों का तबादला किया। कांग्रेस के खाते से बने मंत्रियों के विभागों में हुए बड़ी संख्या में तबादलों को कांग्रेस को संतुष्ट करने का कदम माना जा रहा है।

बावजूद इसके कांग्रेस में विरोध के स्वर थम नहीं रहे हैं। कभी रामेश्वर उरांव के करीबी माने जाने वाले राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू असंतुष्टों का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस के तीन विधायक इरफान अंसारी, उमाशंकर अकेला और राजेश कच्छप सरकार और प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ शिकायत लेकर दिल्ली गए थे। वहां इन लोगों ने सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल और गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की और बताया कि सरकार में उनकी सुनी नहीं जा रही। यह खेमा प्रदेश नेतृत्व में बदलाव चाहता है। साथ ही, जो विधायक मंत्री नहीं बन सके उनके लिए मंत्री स्तर के पदों यानी निगमों में कोई पद चाहता है।

उधर, उरांव ने भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का नाम लिए बिना कहा, “जमशेदपुर विधायकों के संपर्क में हैं।” लेकिन रघुवर दास ने कांग्रेस की एकजुटता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि वह यह कैसे बता सकते हैं कि कौन किसके संपर्क में है। वे कहते हैं, “कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, नेतृत्व से नाराजगी के कारण ही यह सब हो रहा है।” रघुवर की बात पर सियासी गलियारों में इसलिए भी विश्वास किया जा रहा है कि कांग्रेस का एक असंतुष्ट खेमा, राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी सहित तीन विधायक दिल्ली जाकर पार्टी आलाकमान को शिकायतों का पुलिंदा पकड़ा आया है।

असंतुष्टों की एक व्यक्ति एक पद की भी मांग है। रामेश्वर उरांव का कहना है, “पार्टी आलाकमान का जो फैसला होगा, वह मुझे मान्य है। मैं उनकी बदौलत पार्टी में नहीं हूँ। न उन्होंने मुझे टिकट दिया है न ही उन्हें मुझे मंत्री बनाने का अधिकार है।” इस बीच प्रदेश कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर मौजूदा स्थितियों से काफी आहत हैं। वे कहते हैं, “किसी को पार्टी से कितनी भी शिकायत हो, उस शिकायत को रखने



दबाव की राजनीति: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उरांव (बीच में) के साथ अन्य नेता



सरगर्मियां: मुख्यमंत्री सोरेन पर भाजपा के अर्जुन मुंडा (बाएं) की नजदीकियों की चर्चा, तो रघुबर दास (दाएं) भी सुर्खियों में



के लिए पार्टी फोरम ही सबसे मुनासिब जगह है। मीडिया के माध्यम से असंतोष उछालना किसी तरह मुनासिब नहीं है। जहां तक भाजपा की बात है कि उसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला क्योंकि जनता जान चुकी है कि चुनी हुई सरकार को साजिश कर गिराने की उनकी आदत है। झारखंड में इस साजिश का कोई असर नहीं पड़ने वाला।” कांग्रेस के असंतुष्ट विधायक आने वाले दिनों में अपनी गतिविधि तेज कर सकते हैं। वे लोग दिल्ली को साधने में लगे हुए हैं। कांग्रेस नेतृत्व भी झामुमो के साथ संबंध मजबूत करने और पार्टी के भीतर दोबारा सब ठीक करने में लगा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास कहते हैं, “तबादलों के जरिए विरोध की आग बुझाने की कोशिश की गई है।” लेकिन जानकारों का मानना है कि जैसे ही कोरोना संकट कम होगा और सरकार में कामकाज शुरू होगा तो ठेका-पट्टे को लेकर विवाद की आग और बढ़ेगी। भाजपा नेतृत्व होने वाले इन्हीं विवादों पर नजर बनाए हुए हैं और असंतुष्टों का मूड भांप रही है।

हालांकि झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। कांग्रेस के एक खेमे में असंतोष पर बिना नाम लिए उनका कहना है कि धीरज साहू प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं। वे भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के उस आरोप को भी सिरे से नकार देते हैं, जिसमें दुबे ने आरोप लगाया था कि झारखंड के अग्रवाल बंधुओं और उनकी कंपनी ने झामुमो को चंदा दिया था। गोड्डा से भाजपा सांसद दुबे पहले से ही हेमंत सरकार के खिलाफ काफी मुखर हैं। विवाद निशिकांत दुबे की पत्नी के नाम एक जमीन से शुरू हुआ था। इसके बाद भट्टाचार्य और दुबे के बीच ट्विटर वार छिड़ गया। फिर तो दुबे ने हेमंत सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने अग्रवाल बंधुओं की कोलकाता में 22 मंजिली इमारत, रांची और उसके आसपास तीन-चार सौ एकड़ जमीन खरीद में नेताओं के पैसे लगने को लेकर सवाल उठाया है। दुबे का कहना है कि इन प्रॉपर्टी खरीद की जांच की जानी चाहिए। बदले में

जानकारों के मुताबिक गठबंधन सहयोगी कांग्रेस की खींचतान से परेशान मुख्यमंत्री सोरेन की ओर भाजपा पींगें बढ़ा रही है

झामुमो ने निशिकांत दुबे की दिल्ली विश्वविद्यालय से मैनेजमेंट की डिग्री और उग्र प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए चुनाव आयोग से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

कांग्रेस के अंदरूनी संकट के साथ झामुमो का संकट भी बढ़ता जा रहा है। करीब 22 करोड़ रुपये की आय से अधिक आमदनी के आरोप की वजह से

मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल तिवारी की सीएमओ से छुटी कर दी गई और उनके खिलाफ निगरानी जांच बैठा दी गई। झामुमो के कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल को भी पद से हटा दिया गया। लेकिन साफ तौर पर बताया नहीं जा रहा कि दोनों को क्यों हटाया गया। दोनों का जाना इसलिए भी चर्चा का विषय है क्योंकि दोनों की ही हैसियत ज्यादा थी। हालांकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही इसे पार्टी की अंदरूनी राजनीति का हिस्सा बताते हैं।

इन सबके बीच चौतरफा घिरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्र सरकार ने अलग ही तरह के धर्मसंकट में डाल दिया है। कुछ दिनों पहले केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने अचानक रांची पहुंच कर कई दशक से लंबित मांगों के मद्देनजर कोयला खदानों की जमीन के एवज में सोरेन सरकार को 250 करोड़ रुपये की रॉयल्टी दी है। राजनैतिक जानकारों का कहना है कि यह हेमंत सरकार को भाजपा का चारा है। जोशी करीब एक घंटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर रुके और उनके साथ कोयला खदानों की नीलामी सहित अन्य मुद्दों पर बात की। उसके बाद हेमंत सोरेन के सुरु भी बदले हुए थे।

हेमंत सोरेन ने बाद में कहा कि ऐसा समन्वय पहले हुआ होता तो झारखंड का स्टैंड अलग होता। कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ हेमंत सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। केंद्र की यह महत्वाकांक्षी योजना है, ऐसे में झारखंड का सुप्रीम कोर्ट जाना उसे रास नहीं आया था। कोयला खदानों की कामर्शियल माइनिंग से केंद्र से हेमंत के तलख हुए रिश्तों पर मरहम लगाने का काम केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा को सौंपा गया था। मुंडा जब झारखंड के मुख्यमंत्री थे, तब सोरेन उप-मुख्यमंत्री थे। धुर विरोधी झामुमो को भाजपा के करीब लाने का श्रेय भी मुंडा को ही जाता है। बहरहाल, झामुमो और कांग्रेस में टकराव बढ़ता है तो ये चर्चाएं और गरम हो सकती हैं। ऐसा हुआ तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान के उठापटक का नजारा झारखंड में भी दोहराया जा सकता है।



बढ़ती चुनौतियाँ
अमरिंदर पर भारी
पिछले विधानसभा
चुनाव के वादे

प्रभजोत सिंह गिल

कैप्टन की कमान ढीली

अवैध शराब से मौतों से घोषणा-पत्र के 'नौ नुक्तों' पर अपनों की ही
नुक्ता-चीनी में घिरी अमरिंदर सरकार

चंडीगढ़ से हरीश मानव

मार्च 2017 में दूसरी बार पंजाब का मुख्यमंत्री बनने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया था कि यह उनकी आखिरी पारी होगी। करीब साढ़े तीन साल के कार्यकाल में अपने ही ऐलान से पलटे कैप्टन अब मार्च 2022 में तीसरी पारी की तैयारी में हैं। लेकिन पिछले चुनाव घोषणा-पत्र की नौ अहम घोषणाएं और नारा “नवें नरोगे पंजाब लई कैप्टन दे नौ नुक्तें” (नए-नकोर पंजाब के लिए कैप्टन के नौ नुक्ते) अब सरकार के गले की

फांस बना है। भाजपा के ‘कांग्रेस मुक्त भारत’ अभियान के बीच पंजाब जैसे अहम राज्य में कांग्रेस की सरकार आगे भी बनी रहे, इसके लिए कांग्रेस आलाकमान का कैप्टन सरकार पर दबाव है कि 2022 के चुनाव से एक साल पहले ये नौ नुक्ते कारगर हों। 2017 के विधानसभा चुनाव अभियान के रणनीतिकार प्रशांत

किशोर 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को जीत के नुक्ते देंगे, इसके संकेत मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी से दे रहे हैं। प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि पंजाब आकर कैप्टन की मदद करने में उन्हें खुशी होगी। अमरिंदर ने यह तक कहा कि उनकी पार्टी के 55 विधायक 2022 के चुनाव अभियान को

प्रशांत किशोर की सलाह पर चलाने के पक्ष में हैं।

2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नौ नुक्तों में सबसे अहम कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के चार हफ्ते के भीतर सूबे से नशे का खात्मा करना था। नशे के खात्मे की सौगंध साढ़े तीन वर्ष से अधूरी है। किसानों को कर्ज मुक्त करने का नुक्ता भी सिरे नहीं चढ़ पाया। बैंकों और आदतियों के कुल करीब 90,000 करोड़ रुपये के कर्ज में से तकरीबन 30,000 करोड़ रुपये की कर्जमाफी के वादे में साढ़े तीन साल में करीब 6000 करोड़ के कर्ज ही माफ हो पाए हैं। ‘पंजाब दा पानी, पंजाब वास्ते’ के मामले में हरियाणा से नहर (एसवाइएल) जल विवाद सुप्रीम कोर्ट में अटका है। राज्य की कुल आबादी में 33 फीसदी एससी आबादी में तमाम बेघरों को घर के लिए 5 मरले (प्रति मरला करीब 30 वर्ग गज) का प्लाट और एक लाख रुपये मदद की दरकार है। ‘घर-घर रोजगार’ से सूबे के युवा बेजार हैं। उन्हें स्मार्टफोन का भी इंतजार है। इस बारे में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, “सरकार के पास 50 हजार स्मार्टफोन की खेप पहुंच गई है। ये फोन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को बांटे जाएंगे। उन विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास स्मार्टफोन नहीं हैं और स्मार्टफोन की मदद से वे ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख सकेंगे।”

केबल टीवी, ट्रांसपोर्ट, खनन और शराब माफिया के सफाए पर साढ़े तीन साल से सरकार की सफाई जारी है। अपने ही नौ नुक्तों पर कांग्रेस के



पीटीआइ

सांसदों और विधायकों ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आउटलुक से बातचीत में राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, “कैप्टन ने पंजाब से चार हफ्ते में नशे के खात्मे के लिए सार्वजनिक सभा में गुटका साहिब (श्री गुरुग्रंथ साहिब का पावन लघु रूप) की सौगंध खाई थी, पर साढ़े तीन साल में बढ़े नशे और इससे हुई मौतों की वजह से कैप्टन ने कांग्रेस सरकार की किरकिरी कराई है। हाल ही में जहरीली शराब से ही 110 से अधिक मासूम जिंदगियां छिन गई हैं।” अवैध शराब और ड्रग्स के नेटवर्क को तोड़ने का दावा करने वाली कैप्टन सरकार सवालों के घेर में है। नवजोत सिन्धू के करीबी कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को कमजोर मुख्यमंत्री बताते हुए आउटलुक से कहा, “जिन मुद्दों को लेकर साढ़े तीन वर्ष पहले हमने सरकार बनाई थी वे क्यों पूरे नहीं हुए? सरकार के साढ़े तीन साल के कार्यकाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं, डेढ़ साल बाद चुनाव में जनता को इसका जवाब नेताओं को देना होगा। जिस तरह दस साल अकाली-भाजपा गठबंधन की सरकार चल रही थी, उसी रंग-ढंग में कैप्टन सरकार चल रही है। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है।” कादियां से कांग्रेस विधायक फतेह जंग सिंह बाजवा ने कहा, “मुख्यमंत्री को कुछ अफसरों और करीबियों ने बंधक बना लिया है।” नौ नुक़्तों के सवाल पर पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आउटलुक से कहा, “घोषणा पत्र पांच साल के लिए होता है, सरकार ने कई वादे पूरे किए



हैं और बाकी वादे भी अगले डेढ़ साल में पूरे कर दिए जाएंगे।

शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता और पूर्व कैबिनेट मंत्री दलजीत सिंह चीमा का कहना है, “चार हफ्ते में नशे का खात्मा कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र में सबसे अहम था, लेकिन पंजाब आज तक नशे के इस दंश से मुक्त नहीं हो सका है।” नशे के कारोबार में पाकिस्तानी शह, राजनीतिक संरक्षण और स्थानीय लोगों की संलिप्तता कितनी है, उसे सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि राज्य में नशे का यह अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा।

2017 में हुए विधानसभा चुनाव के समय पंजाब में नशे की तस्करी बड़ा मुद्दा चुनावी हो गया तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसके नाम पर खूब रैलियां कीं। पंजाब के राजनीतिक विश्लेषक प्रो. रौणकी राम का कहना है कि पंजाब में 2017 के चुनाव अभियान के दौरान कांग्रेस के राहुल गांधी समेत कैप्टन अमरिंदर सिंह और अन्य नेताओं ने बड़े जोर-शोर से नशे को

110 मौतों के बाद: जहरीली शराब के पीड़ित और इसके खिलाफ प्रदर्शन करते आप समर्थक

मुद्दा बनाया था। कांग्रेस ने लोगों के बीच यह संदेश पहुंचाने की कोशिश की कि फौजी रहे अमरिंदर किसी भी कीमत पर नशे के कारोबार को खत्म करके ही दम लेंगे, लेकिन साढ़े तीन साल बाद भी सरकार का दम फूल रहा है।

राज्य में अवैध शराब का कारोबार इसलिए भी फल-फूल रहा है, क्योंकि यहां का आबकारी एक्ट कमजोर है। पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट में मानवाधिकार अधिकवक्ता एच.सी. अरोड़ा का कहना है, “आबकारी एक्ट में नशे के कारोबार पर सजा का प्रावधान सिर्फ तीन साल की जेल या एक लाख रुपये का जुर्माना है। यहां जमानत भी आसानी से मिल जाती है। इसी कारण अवैध शराब के धंधे में शामिल लोगों को कानूनी डंडे का डर नहीं होता है। पंजाब में नशे के कारोबार में स्थानीय लोगों से लेकर सीमा सुरक्षाबलों के जवानों तक की मिलीभगत के आरोप हैं। अवैध शराब ही नहीं, सीमा पार से आने वाले ड्रग्स के धंधे में भी बीएसएफ और पंजाब पुलिस के भी अफसर पकड़े जा चुके हैं। अमृतसर, फाजिल्का, गुरदासपुर और फिरोजपुर में सीमा पार से ड्रग्स की सप्लाई के गोरखधंधे में राजनीतिक संरक्षण के अलावा सीमा सुरक्षा ड्यूटी में तैनात अधिकारी और सीमा पर बसने वाले लोगों की मिलीभगत बताई जाती है। पंजाब में बीते दिनों नशे के कारोबार के रास्ते कश्मीर में आतंकी फंडिंग के नेटवर्क का पर्दाफाश भी हो चुका है।

सरकार की इस नाकामी से अपनों के अलावा विपक्षी भाजपा भी एक्शन मोड में आ गई है। हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी यहां के कार्यकर्ताओं की वर्चुअल रैली में कहा कि वे 23,000 बूथों पर राज्य के मौजूदा हालात की समीक्षा करें। कार्यकर्ताओं को यह पता लगाने के लिए कहा गया है कि कैसे पंजाब में कांग्रेस सरकार ने केंद्र के भेजे राशन की बंदरबांट कर अपनी राजनीति चमकाई है। जाहिर है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए चुनौतियां कई हैं।



कैप्टन ने पंजाब से चार हफ्ते में नशे के खात्मे के लिए गुटका साहिब की सौगंध खाई थी, पर साढ़े तीन साल में बढ़े नशे और इससे हुई मौतों की वजह से कैप्टन ने कांग्रेस सरकार की किरकिरी कराई है

प्रताप सिंह बाजवा

राज्यसभा सांसद, कांग्रेस



भव्य आयोजन: अयोध्या में भूमि पूजन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ

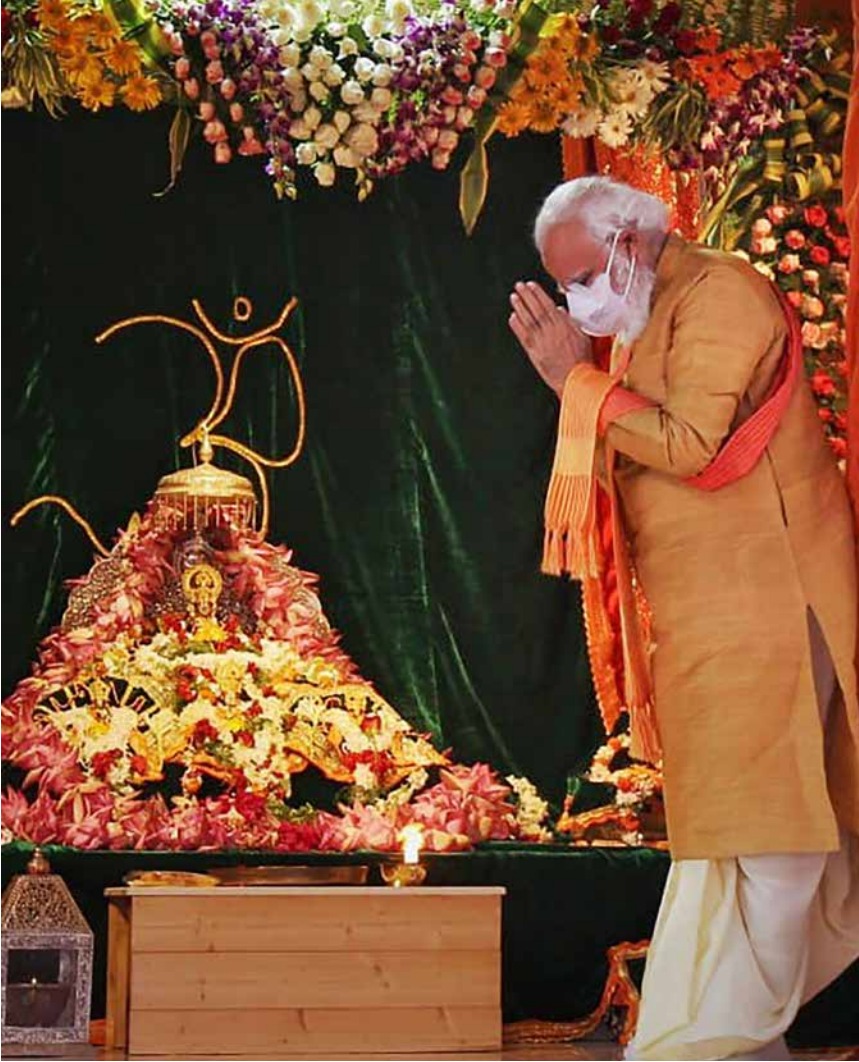
नई लीला के राम

हरिमोहन मिश्र

अयोध्या सजी थी, लाखों दीये जगमग थे, शंखध्वनियां और तुरही का नाद उठ रहा था। महामारी और आर्थिक तबाही का वह सन्नाटा शायद कहीं दुबक गया, जिससे देश त्रस्त है। अलबत्ता, अयोध्या वही है मगर 5 अगस्त के बाद उसके सुर-ताल कुछ दूसरे हो गए, या कहिए वहां विशाल राम मंदिर के लिए भूमि पूजन के भव्य आयोजन में सत्ता के इकबाल से उठी नगाड़ों की धुन नई लीला का मंच तैयार कर रही हैं, जिसका उद्घोष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर

अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण से राजनीति और सामाजिक नैरेशन और ताने-बाने में कई बदलावों की संभावना, लेकिन कई सवाल भी

सभी फोटो: पीटीआइ



राम के नाम: रामलला के दर्शन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इंदौर में बने 5 लाख लड्डू (दाएं)

से गुंजा। पहले साष्टांग दंडवत (कोई चाहे तो 2014 में पहली बार संसद में पहुंचे मोदी का घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाना याद कर सकता है) और फिर भूमि पूजन के बाद मोदी ने मंच पर और वहां मौजूद चुर्नीदा दर्शकों-श्रोताओं लेकिन टीवी चैनलों के जरिए करोड़ों घरों में लोगों से कहा, “5 अगस्त भी 15 अगस्त की तरह अविस्मरणीय तिथि है, जब कई पीढ़ियों का बलिदान फलीभूत हुआ।” मंच पर मौजूदगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और श्रीराम तीर्थक्षेत्र न्यास के अगुआ नृत्यगोपाल दास की ही थी, जो नए राजनैतिक ताने-बाने का यकीनन संकेत लिए हुए हैं।

गौरतलब है कि तकरीबन तीन दशक पहले राम



मंदिर का आंदोलन का आगाज करने वाले और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के दौरान मौजूद रहे रथी, नायक, पटनायक, सभी लगभग दृश्य से गायब रहे। आप चाहें तो उनके नाम लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, कल्याण सिंह वगैरह के रूप में याद कर सकते हैं। यह भी अलग बात है कि 1989 में शिलान्यास के बाद दोबारा यह आयोजन किया गया मगर नींव नहीं रखी जा सकी क्योंकि मंदिर का नया नक्शा अभी मंजूर नहीं हो पाया है। लेकिन इन ब्यौरों और सुर्खियों से ज्यादा अहम वे सवाल हैं, जो इससे निकलती नई राजनीति की शिला रखते लग रहे हैं।

इससे शायद ही कोई इनकार कर पाए कि 5 अगस्त की तारीख एक नई इबारत लिख गई। संभव है, मोदी सरकार ने इसे सुनियोजित तरीके से चुना है क्योंकि आजादी की लड़ाई की कम से कम दो बड़ी तवारिखें अगस्त के महीने की 9 और 15 हैं। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी। साल भर पहले 5 अगस्त को ही संविधान के अनुच्छेद 370 को बेमानी बनाकर जम्मू-कश्मीर से विशेष दर्जा हटा लिया गया और उसे दो केंद्रशासित राज्यों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। उससे वहां खासकर घाटी में शुरू हुई नाकेबंदी, पाबंदियां, गिरफ्तारियां, कर्फ्यू साल भर बाद भी पूरी तरह हट नहीं पाई है। तो, कम से कम दो ऐसी घटनाएं 5 अगस्त को मोदी के नेतृत्व में हुईं, जिसे संघ परिवार और हिंदुत्ववादी संगठन आजादी का अधूरा एजेंडा मानते रहे हैं। बस फर्क, कुछ जानकारों के मुताबिक, यह है कि आजादी के दौरान की तारीखें उदारचेता, समावेशी और विविधता बहुल राष्ट्र निर्माण की हैं, जबकि 2019 और 2020 का 5 अगस्त इसके विपरीत रुझान लिये हुए है। जैसा कि, देश में चोटी के बुद्धिजीवी तथा राजनीति शास्त्री प्रताप भानु मेहता ने अपने ताजा स्तंभ में लिखा, “यह बहुसंख्यकवादी अहंकार और कई तबकों में कमतर होने के एहसास और आजादी सीमित होने का प्रतीक है। इस मायने में यह प्राचीन, मध्ययुगीन भारतीय परंपरा और आजादी के दौरान उपजे भारत-विचार का विलोम है।” इससे भी अहम यह है कि जो राजनैतिक धाराएं अभी पिछले साल तक हिंदुत्ववादी एजेंडे के विरोध का दावा हलके या कुछ तेज आवाज में करती रही हैं, उनके स्वर गुम हैं या स्वागत ही कर रही हैं—कुछ खुलकर तो कुछ प्रतीकों में, लेकिन विरोध के स्वर बेहद अल्पमत में हैं। इसी से नई राजनैतिक और कुछ हद नए सामाजिक ताने-बाने का संकेत मिलता है।

कांग्रेस की ओर से ही कुछ थमे स्वर में कश्मीर के मसले पर और अब मंदिर के मामले में खुलकर स्वागत की आवाजें उठीं, जो खुद को मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्ववादी एजेंडे का

इकलौती राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्वी होने का दावा करती है। इस 5 अगस्त की पूर्व-संध्या पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का “जय सियाराम” का स्वागत बयान आया। अलबत्ता, यह ‘जय श्रीराम’ के उद्धोष के विपरीत लोक परंपरा का आभास देता है, जिसे बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद कई बुद्धिजीवियों ने याद दिलाया था, ताकि राम के इर्दगिर्द यह नई पुरुष-सत्तात्मक आक्रामक बुनावट की काट की जा सके। लेकिन काट के लिए प्रतीक भर कारगर कम ही होते हैं। फिर तो कई कांग्रेस नेताओं के हनुमानचालिसा का पाठ भी सामने आ गया। दूसरी तमाम पार्टियों सपा, बसपा, राजद, तृणमूल कांग्रेस, बीजद, द्रमुक के बयान भी समर्थन या प्रतीकों में सहमे से विरोध के ही रहे हैं। वामपंथी पार्टियों ने सिर्फ सरकारी शिरकत का विरोध किया। प्रतिकूल मुस्लिम पक्ष रखने का बीड़ा सिर्फ एआइएमआइएम के असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया, जिसकी सियासी वजहें जानना कोई मुश्किल नहीं है। बाकी देश और अयोध्या के मुसलमान या उनके नेता तो मानो इसे नियति का खेल मानकर मौन हो गए।

एक दलील यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल फैसला सुना दिया तो इसे सबको स्वीकार कर लेना चाहिए। वैसे, कुछ न्यायविद और अन्य लोग फैसले पर अलग राय जाहिर कर चुके हैं। सर्वोच्च अदालत ने फैसला भले विवादित स्थल पर मंदिर और बगल में मस्जिद बनाने का दिया हो मगर उसने 1949 में बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखने और 1992 में मस्जिद ढहाए जाने को आपराधिक कृत्य माना। इस पर लखनऊ में सीबीआई अदालत में बयान दर्ज हो रहे हैं और उसे 31 अगस्त तक फैसला सुनाना है। फिलहाल आडवाणी, जोशी समेत सभी आरोपियों ने कहा है कि वे निर्दोष और उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। यह अलग बात है कि वे 6 दिसंबर 1992 को मौके पर मजबूत थे। लेकिन यहां मामला राजनैतिक नैरेशन का है, न कि मंदिर निर्माण का। बेशक, इस नैरेशन की कड़ी चुनावी राजनीति से भी जुड़ी है। मोदी इसके सहारे 2024 के अगले लोकसभा चुनाव और आदित्यनाथ इसी के सहारे 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी नैया खे ले जाने का एजेंडा बना चुके होंगे, वरना भाद्र मास और वर्षाकाल में देव-विश्राम के समय शास्त्र वर्जित शुभ कार्य के तर्क आधुनिक दौर की राजनीति ही हो सकती है। योजना के मुताबिक, मंदिर 2022 तक आधा और 2024 तक पूरा तैयार



भाद्रमास और वर्षाकाल में देव विश्राम के समय शास्त्र वर्जित शुभ कार्य के तर्क आधुनिक दौर की राजनीति ही हो सकती है



हर जगह उल्लास: बनारस में गंगा के किनारे दीप प्रज्ज्वलित कर खुशी मनाते लोग

हो सकता है।

लेकिन बाकी दलों को भी चुनावी पेशबंदी मंदिर का समर्थन करने या मौन बनाए रखने को बाध्य कर रही होगी, वरना आडवाणी का रथ बिहार में रोकने वाले लालू प्रसाद यादव की राजद के सुर आज क्यों बदले हैं और उत्तर प्रदेश में 1990 में अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की पहली 'कार सेवा' पर पाबंदी लगाने वाले मुलायम सिंह यादव की पार्टी सपा ही क्यों मौन रहती। दोनों ही पार्टियों में कमान नई पीढ़ी क्रमशः तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के हाथ आ गई है। बसपा की मायावती ने

भी पहले दलित पुजारियों की गैर-मौजूदगी का मुद्दा उठाया, फिर राम के हवाले से समावेशी संस्कृति की बात भर की। चुनाव बंगाल में भी होने हैं। सो, ममता बनर्जी ने भी राम के हवाले से सधा-सा बयान दिया। यह बताता है कि नए राजनैतिक नैरेशन की ताकत आज क्या है, जो सबको समर्पण करने पर बाध्य कर रहा है। यह फर्क तब और साफ सुनाई पड़ सकता है, जब आप 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के वक्त को याद करें। तब मुलायम, लालू या ऐसे तमाम नेता खम ठोंककर मंदिर आंदोलन के खिलाफ बोलते थे और उनकी बात सुनी जाती थी। बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में सपा-बसपा गठजोड़ को बहुमत मिला और उनका नारा ही था 'मिले मुलायम-कांशीराम हवा हो गए जय श्रीराम।' आज वैसा नारा शायद ही कोई लगा पाए। बेशक, इस दौर परिवर्तन में तमाम भाजपा विरोधी पार्टियों की भी अपनी अहम भूमिका गिनाई जा सकती है। न सिर्फ धर्मनिरपेक्षता पर

इन दलों ने अजब-गजब तेवर अपनाए, बल्कि पहचान और वोटबैंक की राजनीति के साथ-साथ सरकारों में निकम्मापन और भ्रष्टाचार के किस्से भी लोगों के मोहभंग का कारण बने। लिहाजा, 2014 में भाजपा और एनडीए की सरकार बनने के बाद संघ परिवार का नैरेशन जोर पकड़ने लगा और 2019 के चुनावों में उससे भी बड़ा बहुमत हासिल करके उसने हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद और राम के अपने नैरेशन को ऐसे मुकाम पर पहुंचाने में कामयाबी पाई कि अब बाकी पार्टियों के लिए हालात मुश्किल होते जा रहे हैं।

बहरहाल, यह नैरेशन सिर्फ राजनीति में ही नहीं बदला है, बल्कि साहित्य खासकर पॉप साहित्य में भी इस तरह की व्याख्याएं युवा पीढ़ी को लुभा रही हैं। अंग्रेजी से आया यह फैशन हिंदी में परवान चढ़ने लगा है और कई युवा लेखक राम, शिव और पौराणिक पात्रों को नए जमाने के मुताबिक ढालकर किस्सागोई करने लगे हैं। लेकिन एक बात तो तथ्य है कि ये राम तुलसीदास के 'गरीबनवाज' और कबीर के 'घट-घट व्यापी' राम से कुछ अलग हैं, जहां भव्यता ही लुभाती है। संभव है, जनमानस में राम की पुरानी लोकहितैषी छवि लौट आए, जो बकौल तुलसी उनके हृदय में बसते हैं जिन्हें *जात-पात धन धरम बढ़ाई* नहीं सुहाती। लेकिन मौजूदा राजनैतिक वातावरण तो कुछ और ही कहता है।



धर्म की राजनीति का अंत हो

मंदिर-मस्जिद की दीवारों को तोड़ आर्थिक उन्नति के नए संकल्प का सूत्रपात ही अयोध्या का बड़ा सबक



हेमंत शर्मा

वह जून 1989 का दौर था। इस दौर में जब हिमाचल के पालमपुर में भाजपा ने अपनी पार्टी की कार्यकारिणी में अयोध्या विवाद को एजेंडे में लिया तो शायद भाजपा नेताओं को भी भरोसा नहीं रहा होगा कि पांच सौ साल का यह विवाद उनकी पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना देगा। अयोध्या हिंदू पुनरुत्थान का केंद्र बना जाएगा। 5 अगस्त को अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर का शिलान्यास ही नहीं, बल्कि दुनिया के नक्शे पर वेटिकन, मक्का जैसे एक शहर की नाँव पड़ेगी। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की टीम ने काम करना शुरू भी कर दिया है।

मंदिर निर्माण की शुरुआत से अयोध्या कांड ने समय का एक चक्र पूरा कर लिया है। ऐसा हो सकता है मंदिर निर्माण के साथ धर्म की राजनीति का अंत हो, शताब्दियों से भारतीय जनमानस को मथते इस मुद्दे का दम निकले। पर प्रश्न यह है कि क्या दो सभ्यताओं के इस चिरंतन संघर्ष का घाव भी भरा जा सकेगा? अयोध्या आजादी के बाद आस्था और विभाजन की पीड़ा से फूटा हुआ एक घाव है। ऐसे घाव बहुत मुश्किल से भरते हैं। वर्तमान को बदलना फिर भी आसान होता है मगर इससे इतिहास नहीं बदलता।

दरअसल अयोध्या सही मायनों में धर्म की राजनीति से मुक्ति का अहसास है। भारतीय राजनीति में ध्रुवीकरण की प्रक्रिया अयोध्या से ही शुरू हुई थी। मंडल के जवाब में कर्मंडल आया था। वह कामयाब भी रहा। देश की राजनीति और समाज को उसने सीधे तौर पर बांटा। देश की राजनीति मंदिर और मस्जिद के गिर्द घूमती रही। भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा भी हुआ। वह दो सीटों से बढ़ती-बढ़ती 303 सीटों तक पहुंच गई। इस मुद्दे पर हमेशा से दुविधा में फंसी कांग्रेस 415 सीटों से नीचे आते-आते 52 पर आ गई। 1985 के बाद हर चुनाव में यह बोलत का जिन्न बाहर आता और चुनाव बाद बोलत में वापस चला जाता रहा। अब तो मंदिर वहीं बन रहा है। इसलिए आने वाले चुनावों में यह मुद्दा न रहे। धार्मिक ध्रुवीकरण खत्म हो। यह बात मुसलमानों को भी समझ में आ रही थी कि इस ध्रुवीकरण ने संसद में लगातार मुस्लिम प्रतिनिधित्व को घटाया है। इस विवाद से पहले 1980 में जहां लोकसभा में 49 मुस्लिम सांसद चुने जाते रहे, वहीं 2019 आते-आते इनकी संख्या घटकर 27 हो गई।

लंबी और थका देने वाली लड़ाई से दोनों पक्ष यह समझने भी लगे थे कि यह मुद्दा अब कारगर नहीं रहा। फैसले के बाद दोनों तरफ की प्रतिक्रिया से यही सिद्ध होता है कि आज की नई पीढ़ी को वैसे भी इस विवाद में कोई रुचि नहीं रही। आज कुल आबादी का 38 प्रतिशत उन लोगों का है जो 1992 के ध्वंस के बाद पैदा हुए हैं। जो मंदिर-मस्जिद के इस विवाद के बारे में ठीक से जानते भी नहीं। उन्हें सिर्फ यह पता है कि कोई राष्ट्र या समाज नफरत की बुनियाद पर

ज्यादा दिन नहीं चल सकता। इसीलिए उसने अतीत से आगे बढ़ने का अदालती रास्ता पा लिया है। इतिहास का मतलब है स्मृतियां और स्मृति के घाव आसानी से नहीं भरते। फिर अयोध्या का घाव तो उस चेतन-अचेतन धड़कन का प्रतिनिधि है, जिससे धर्म, सभ्यता और मान-सम्मान के तमाम पहलू बंधे हुए हैं। बाबर ने तलवार के बूते जिस आस्था का ध्वंस चाहा, वह आस्था साढ़े चार सौ साल बाद भी इतिहास के इस घाव को नहीं भुला सकी। यह आस्था हर कालखंड में हर कीमत पर मंदिर वहीं बनवाने के लिए संकल्पबद्ध रही। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा समाधान निकाला जिससे यह ध्वनि निकले कि न कोई जीता, न कोई हारा। इस फैसले ने दोनों ही समुदाय को मौका दिया कि वे अपने गिले-शिकवे भुलाकर नए भारत के निर्माण के लिए काम करें।

सभ्यताओं का संघर्ष मरता नहीं है। वह अचेतन में निरंतर चलता रहता है। अयोध्या हो या येरूशलम, सभ्यताओं के ये कुछ चिरंतन घाव हैं, जिनके संघर्ष पर विराम आसान नहीं है। ये घाव लगातार खून बहाते हैं। नए लक्ष्य देते हैं और सतत संघर्ष की धुरी बने रहते हैं। मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद मीर बाकी ने साल 1528 में बनवाई थी। तबसे 491 साल हो गए। हिंदू आस्था पर की गई यह चोट इस बीच हमेशा हरी रही। मुकदमों का दौर चला। मुकदमों के भी 161 साल हो गए। दोनों ओर से आशा और धीरज जवाब देने लगा। राष्ट्र का संयम और धैर्य खो रहा था। इस अधीरता के चरम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया।

अयोध्या का मतलब है, जिसे जीता न जा सके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इसे एक बार फिर साबित कर दिया कि अयोध्या अजेय है। उसे जीता नहीं जा सकता। इसके साथ ही कुछ जटिल प्रश्न भी हमेशा के लिए तय हो गए। यानी राम जन्मभूमि वहीं है जहां आज रामलला विराजमान हैं। उस जमीन का बंटवारा नहीं हो सकता। अयोध्या ने मंदिर और मस्जिद दोनों मंजूर किया। सरयू ने माना कि उसका पानी पूजा और वजू दोनों के लिए है। राम की मर्यादा रामराज्य से है और रामराज्य की असली तस्वीर मर्यादा, सद्भाव और संवाद से है। हमें इस सिद्धांत में भरोसा करना होगा। इसकी मर्यादा का मान रखना होगा, तभी अयोध्या के सदियों पुराने घाव का वर्तमान की सुखद स्मृतियों में रूपांतरण होगा। फिर न कोई टीस बचेगी और न ही कोई कसक। अयोध्या एक स्वर्णिम अवसर की तरह है। ये

अवसर इस देश की राष्ट्रीय एकता का मिशन बन सकता है। सामाजिक कटुता और वैमनस्य की विष बेलों को सद्भाव और भाईचारे के स्थायी समाधान में बदल सकता है। मंदिर-मस्जिद की दीवारों को तोड़ देश की आर्थिक उन्नति के नए संकल्प का सूत्रपात कर सकता है। जीवन, समाज और राष्ट्र के लिए जरूरी मुद्दों की मुख्यधारा में वापसी का मानक बन सकता है। हमें इस अवसर को किसी भी सूरत में नहीं गवाना चाहिए। ये इतिहास की अग्नि परीक्षा है। ये काल का यक्ष प्रश्न है। हमें पूरी ईमानदारी और सदभावना के साथ इस प्रश्न का सामना करना होगा। यही अयोध्या का सबसे बड़ा सबक है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। अयोध्या पर उनकी पुस्तक चर्चित है)

फैसले के बाद दोनों तरफ की प्रतिक्रिया से यही सिद्ध होता है कि आज की नई पीढ़ी की इस विवाद में कोई रुचि नहीं रही। यह मुद्दा अब कारगर नहीं रहा



पौराणिक पाँप

टीवी धारावाहिकों और अंग्रेजी पॉप साहित्य की देखादेखी हिंदी के लोकप्रिय साहित्य में पौराणिक पात्रों के इर्दगिर्द किस्सागोई की ओर युवा लेखकों और प्रकाशकों का रुझान बढ़ा

आकांक्षा पारे काशिव

अमूमन 'जो रुचे, सो बिके' ही कारगर मंत्र होता है। इसे पलट दें तो यह भी कह सकते हैं कि 'जो बिके, सो रुचे।' डिजिटल दौर में स्मार्टफोन और आइ-फोन वगैरह की दीवानी नई पीढ़ी किताबों से बेरुख हुई तो इसी पीढ़ी या आसपास की पीढ़ी के लेखकों और प्रकाशकों ने नया फंडा ईजाद किया। राम, शिव और अन्य देवी-देवताओं तथा पौराणिक पात्रों के इर्दगिर्द बुनी नई किस्सागोई का बाजार बढ़ने लगा। वैसे, हर दौर के अपने फैशन होते हैं और उसकी

सामाजिक-राजनैतिक वजहें भी स्पष्ट होती हैं। लेखन और प्रकाशन की दुनिया में फैशन की फिजा तो मुख्यधारा के साहित्य में भी परवान चढ़ती है लेकिन लोकप्रिय या 'पॉप' साहित्य में फैशन अमूमन ऐसे चढ़ता है कि उसका डंका बजने लगता है। पिछले दशक में यह फैशन कुछ अतीतोन्मुखी हुआ और कुछ जादुई एहसास दिलों को झूने लगा तो टीवी धारावाहिकों से लेकर लेखन-प्रकाशन में भी पौराणिक और रामायण-महाभारत के पात्रों के इर्दगिर्द नई किस्सागोई बिकाऊ बन चली। शायद यही एहसास कोरोनावायरस

की रोकथाम के घोषित लक्ष्य से लगाए गए लॉकडाउन के शुरुआती दौर में टीवी पर पुराने *रामायण* और *महाभारत* धारावाहिकों का प्रसारण फिर करने की भी हो सकती है।

दिलचस्प यह भी है कि हमारे देश में हर फैशन, खासकर प्रकाशन के क्षेत्र में अमूमन अंग्रेजी से उतरता है, इस बार भी वही हुआ। अंग्रेजी में देवदत्त पटनायक, अमीष त्रिपाठी, अश्विन सांघी, आनंद नीलकंठन वगैरह की धूम मचने लगी तो हिंदी में भी कई युवा लेखकों और प्रकाशकों की नई पीढ़ी ने पौराणिक और मिथकीय पात्रों की ओर रुख किया। 'मिलेनियल' पीढ़ी को यह रुच रहा है, मानो उसे पश्चिमी सुपरमैन और अन्य तरह के कॉमिक्स का रुचिकर देसी वर्जन मिल गया है। यह कथानक लोकप्रिय संस्कृत साहित्य के अति परिचित नायकों और खलनायकों से बना जाता है। कह सकते हैं कि यह नया चलन गीता प्रेस और जे.के. रॉलिंग (हैरी पॉटर वाली) का अजीबोगरीब मिश्रण है।

हालांकि हिंदी और भारतीय भाषाओं के मुख्यधारा और लोकप्रिय साहित्य में पौराणिक, ऐतिहासिक और मिथकीय पात्रों को लेकर अकूत साहित्य भरा पड़ा है। गीता प्रेस, गोरखपुर ने तो बेहद सस्ते प्रकाशनों से वेद, पुराण, रामायण, महाभारत से लेकर तमाम पौराणिक साहित्य खासकर उत्तर भारत के हर घर में वर्षों से

अंग्रेजी में धूम मचने लगी तो हिंदी में भी कई युवा लेखकों और प्रकाशकों की नई पीढ़ी ने पौराणिक और मिथकीय पात्रों की ओर रुख किया

पहुंचाता रहा है। आधुनिक दौर में हिंदी में मैथिलीशरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय से लेकर अनेक नामवर साहित्यकारों ने कई पौराणिक चरित्रों की नए सिरे से व्याख्या की है। हम सब उर्वशी, उर्मिला, यशोधरा की व्यथाएं, कर्ण की नई व्याख्या के कवित से परिचित हैं। यह फेहरिस्त काफी लंबी हो सकती है और मौजूदा दौर की कविताओं, कई उपन्यासों में भी उसकी गूँज सुनाई पड़ती है। इसी तरह मराठी, बांग्ला, ओडिया, असमी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम में भी प्रचुर साहित्य निरंतर लिखा जाता रहा है, जिसका कुछ अनुवाद हिंदी में भी हुआ है। मराठी में विष्णु सखाराम खांडेकर का *ययाति*, शिवाजी सावंत का *मृत्युंजय* और हाल में *हिंदू* जैसा रोचक उपन्यास हिंदी पाठकों की भी उपलब्ध है।

लेकिन लोकप्रिय या 'पॉप' साहित्य के नए लेखकों का पौराणिक और मिथकीय पात्रों के इर्दगिर्द कुछ जादुई अंदाज में कथा बुनने का रुझान अंग्रेजी से शुरू हुआ। अमीष त्रिपाठी की शिव त्रयी, देवदत्त पटनायक की *द प्रेजेंट किंग* और अशोक बैंकर की *रामायण* सीरीज बाजार में तहलका मचाने लगी। बाजार की तलाश में प्रकाशकों की नई पीढ़ी को फौरन इसमें संभावना दिखी और ये किताबें हिंदी पाठकों तक भी पहुंचीं। फिर तो हिंदी के कुछ अपने लेखक भी नमूदार हुए।

दरअसल देवदत्त पटनायक *आउटलुक* से बातचीत में कहते भी हैं, "मुझे लगता है कि शुरुआत हैरी पॉटर की लोकप्रियता से हुई है। हैरी पॉटर जब लोकप्रिय हो गया, उस पर फिल्में भी आने लगीं तो लोगों की रुचि लोककथाओं और दंतकथाओं, आख्यानों में बढ़ने लगी। यह सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में हो रहा है। मैं यही मानता हूँ कि दंतकथाओं की वापसी हुई तो पौराणिक चरित्रों में नई दिलचस्पी भी बढ़ी है" (देखें इंटरव्यू)। शिव त्रयी से चर्चित हुए अमीष त्रिपाठी के मुताबिक, भारत के लोग अपने देवी-देवताओं की कहानियों से कभी ऊबते नहीं हैं। वे *आउटलुक* से कहते हैं, "वे बार-बार नए ढंग से कही गई कहानियों में रस लेते हैं। उनका मन कभी उचटता नहीं।" हालांकि इसका एक सूत्र बाजार से भी जुड़ा है। देवदत्त की



पंकज कौरव

शानि: प्यार पर टेढ़ी नजर
प्रकाशन वर्ष 2019

ज्योतिष को लेकर समाज में बढ़ता अंधविश्वास लिखने की प्रेरणा बनी। उपन्यास का मुख्य पात्र सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पिता के साथ उसके संबंधों में कुछ वैसा ही तनाव है जैसा शनि और सूर्य की पौराणिक कथा में रहा है। यह प्रेम त्रिकोण, कारपोरेट प्रतिस्पर्धा और महत्वाकांक्षा की कथा है



शैलेंद्र तिवारी

रावण एक अपराजित योद्धा और
लंका रावण की नगरी
प्रकाशन वर्ष 2019

राम को समझने के लिए रावण को समझना जरूरी है। राम-रावण को लेकर सवालों का जवाब इस किताब में देने की कोशिश है। दूसरी किताब में युद्ध को करीब से बताने का प्रयास किया। मैं राम और रावण नई पीढ़ी को करीब से दिखाना चाहता हूँ



आशुतोष गर्ग

अश्वत्थामा और इंद्र
प्रकाशन वर्ष 2019

अश्वत्थामा में मुख्य रूप से अश्वत्थामा की दृष्टि से महाभारत की कथा है। मेरा दूसरा उपन्यास इंद्र पर है। इस उपन्यास में देवलोक के वर्तमान राजा पुरंदर के जीवन से जुड़ी तैंतीस रोचक घटनाओं को गूँथकर देवराज इंद्र के चरित्र को उजागर किया गया है। जल्द ही इसका दूसरा संस्करण भी आने वाला है



सबसे ताजा किताब कैसे बनें धनवान भी आ गई है। इसी वजह से ऐसे लेखन में कुछ विवाद और सुर्खियों के तत्व भी तलाशे जाते हैं। मसलन, अमीष त्रिपाठी की शिव त्रयी कुछ विवादों के लिए चर्चित हुई। वे कहते भी हैं, “मैं मानता हूँ कि ज्यादातर कन्ट्रोवर्सी लोग खुद फैलाते हैं। इससे किताबों की मार्केटिंग हो जाती है। यह मार्केटिंग स्ट्रेटजी है।” उनकी शिकायत यह भी है कि हिंदी के प्रकाशकों की मार्केटिंग स्ट्रेटजी सही नहीं है।

बेशक, यह मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी अपना कमाल दिखा रही होगी। हिंदी के कुछ युवा लेखकों ने भी कई विवादास्पद, विरोधाभासी, उपेक्षित पौराणिक पात्रों की किस्सागोई पर कलम चलाई है। ये पात्र पुराण, उपनिषद, महागाथाओं से निकलते हैं और आज के दौर की लोकप्रिय बहसों के सूत्रों में पिरोए जाते हैं। लेकिन आलोचक विवादास्पद और रोचक किस्सागोई को ही इसकी कामयाबी का स्रोत मानते हैं। उन्हें ऐसी किस्सागोई में पुराणों की कथा-वस्तु में फेरबदल पर आपत्ति है। एक उपेक्षित मिथकीय पात्र शर्मिष्ठा को लेकर इसी नाम से उपन्यास लिखने वाली युवा लेखिका अणुशक्ति इससे सहमत नहीं हैं। वे कहती हैं, “पौराणिक कथाओं की अपनी शैली होती है। उसमें अमूमन त्रियाँ गौण होती हैं। इसलिए मैंने शर्मिष्ठा की कहानी कही, जैसे उसकी कहानी कही

जानी चाहिए थी।” यह भी दिलचस्प है और आज के दौर के सियासी माहौल से मिलता-जुलता है कि महाभारत और रामायण के पात्र और कथाएं ही नए लेखकों को सबसे ज्यादा लुभाती हैं। आशुतोष नाइकर ने महाभारत से शकुनि को विषय बनाया है। दरअसल माधवी, द्रोपदी, कर्ण, सत्यवती, कुंती, गांधारी, भीष्म, अश्वत्थामा, रावण, शकुनि पात्रों में बहुत-कुछ कहने की गुंजाइश है और लोगों की दिलचस्पी भी खासी है।

इस नए ढंग के लेखन पर प्रकाशकों में खासी दिलचस्पी है। वाणी प्रकाशन में नई पीढ़ी की अदिति माहेश्वरी कहती हैं, “मिथकीय या पौराणिक चरित्र पर किताब प्रकाशित करना बड़ी जिम्मेदारी होती है।” रेड ग्रेब बुक्स के वीनस केसरवानी के पास इस तरह के पात्रों पर लिखी किताबें सबसे ज्यादा हैं। उन्होंने 2014 में सीता के जाने के बाद राम नाम की किताब से इस यात्रा की शुरुआत की थी और अब ज्यादातर किताबें मिथकीय या पौराणिक पात्रों पर ही हैं। वीनस कहते हैं, “हमने पुस्तक मेला और सोशल मीडिया से पाठकों तक पहुंच बनाई। हमारे लिए ज्यादातर नए लेखक ही इन विषयों पर किताबें लिखते हैं और युवा वर्ग ही इन किताबों को पढ़ता है।” हालांकि वे मानते हैं कि पाठकों का वर्ग तैयार करने में शुरुआती दिनों

में उन्हें दिक्कत हुई थी, लेकिन अब ऐसी किताबों की बिक्री बढ़ गई है।

खासकर मोबाइल और स्मार्टफोन युग की नई पीढ़ी में ये किताबें नई दिलचस्पी ठीक उसी तरह जगा रही हैं, जैसे इस मिलेनियम के शुरुआती वर्षों में चेतन भगत, शिवेंद्र सिंह जैसे ‘पॉप’ लेखकों ने जगाई थी। कक्षा बारहवीं में पढ़ने वाले अक्षत शर्मा कहते हैं, “रावण पर लिखी किताब मुझे बहुत प्रिय है। इससे मैंने रावण के कई पहलुओं को जाना और फिर शकुनि भी पढ़ी। हम जिन्हें डार्क कैरेक्टर समझते हैं, दरअसल उनके पीछे की कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है।” प्रकाशक पेंगुइन (भारतीय भाषा) की वैशाली माथुर कहती हैं, “युवा इसके जरिए अपनी जड़ों और आधुनिक स्थितियों में पात्रों की बेहतर समझ हासिल कर पा रहे हैं। मिथकीय साहित्य को पढ़ने की उनकी रुचि इतिहास और राजनीति को जानने के लिहाज से पैदा हुई है।”

गौरतलब है कि बिक्री के आंकड़ों में उछाल के बिना यह रुझान परवान नहीं चढ़ता। रूपा पब्लिकेशंस के कपिश मेहरा स्वीकार करते हैं कि बिक्री के लिहाज से इन किताबों की सफलता अच्छी है। वे कहते हैं, “हमने पौराणिक पात्रों पर कई किताबें छपी हैं। इनकी कामयाबी हर माध्यम में दिख रही है। टीवी में ही देखिए, ऐसे कितने धारावाहिक चल रहे हैं।”



अणुशक्ति सिंह

शर्मिष्ठा

प्रकाशन वर्ष 2019

हमारे मिथक कई बार पितृसत्तात्मक नजरिए को पुष्ट करते नजर आते हैं, शर्मिष्ठा के जरिए मैंने कोशिश की है कि उन किस्सों को स्त्री की अंतरदृष्टि प्रदान कर सकूँ। उसे वैसे ही कह सकूँ जैसी एक वास्तविक स्त्री की परिकल्पना होगी। सुखद है कि पाठकों को एक मिथकीय चरित्र का नवपाठ पसंद आ रहा है



सौरभ कुदेशिया

आह्वान: महाभारत आधारित

पौराणिक रहस्य गाथा खंड 1

प्रकाशन वर्ष 2020

मैंने मिथक और कल्पना के बीच की यात्रा को यथार्थ के धरातल से जोड़ा है। यह नए युग की कहानी भी है। वैदिक शास्त्रों और समकालीन अनुसंधानों के साथ इसमें रहस्य भी है। यह किस्सागोई धर्म, अध्यात्म और युद्धनीति पर भी रोशनी डालती है



विवेक कुमार

अर्थला: संग्राम-सिंधु गाथा और मल्हार

प्रकाशन वर्ष 2017

मैं प्राचीन दौर से आज के दौर तक शक्ति प्रदर्शन, भोग के उपकरणों को बढ़ाने, नए संसाधनों पर अधिकार करने और सर्वोच्च बनने की होड़ को दिखाना चाहता था। यह कहानी दो भागों में लिख पाया। इसी का दूसरा भाग मल्हार की कहानी वहीं से शुरू होती है, जहां पहली खत्म हुई थी



एक वक्त युवाओं की यह दिलचस्पी कॉमिक बुक्स, *अमर चित्र कथा* और *चंदामामा* जैसे प्रकाशनों से पूरी होती थी। लेकिन इनका प्रकाशन सीमित हो गया, टीवी के परदे ने कॉमिक्स पर अपना कब्जा जमा लिया। इसलिए ये किताबें युवाओं में नई दिलचस्पी जगा रही हैं। *रावण* लिखने वाले शैलेन्द्र तिवारी का मानना है, “महाकाव्य की जमीन बहुत विस्तृत है। कई तरह की बारीकियां हैं जो लेखकों को कहानी बुनने में मददगार होती हैं।” विवेक कुमार की *अर्थला* पुराण की जमीन पर है लेकिन फिर भी वह पुराण के बाहर की कहानी है। वे कहते हैं, “कोई भी मिथक अपनी सभ्यता के प्रारूप के संकेत बिंदु होते हैं।” *अश्वत्थामा* और *इंद्र* लिखने वाले आशुतोष गर्ग कहते हैं, “जब आप किसी रोचक घटना का वर्णन करते हैं तो अनजाने ही उससे जुड़ते चले जाते हैं। उस पात्र के सहारे आप खुद की भावनाओं पर प्रकाश डालते हैं।”

मंजुल प्रकाशन के कपिल सिंह कहते हैं, “हमने जब *नीलकंठ* छापी तो इसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा। हमें *इंद्र* पर लिखी किताब पर भी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। यही वजह है कि हम इन्हें ई-बुक फॉर्मेट में भी लाए। मूल हिंदी में लिखी *इंद्र* का दूसरी भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी में भी अनुवाद हो रहा है।” प्रकाशक मानते हैं कि हिंदी में किताबों की वैसी

मार्केटिंग नहीं होती, जैसी अंग्रेजी में होती है।

अंग्रेजी में न सिर्फ मार्केटिंग होती है, बल्कि इस दौर में अंग्रेजी पाठक वर्ग में नई दिलचस्पी भी पैदा हुई है। इसलिए लेखक भी खूब आ रहे हैं। देवदत्त पटनायक, अमीष त्रिपाठी, अश्विन सांघी, आनंद नीलकंठन के साथ नई पीढ़ी भी कदमताल कर रही है। आनंद नीलकंठन वही हैं, जिनकी किताब पर *बाहुबली* का पहला भाग आधारित था। अमेरिका वासी रोशनी चौकसी बहुत कम उम्र में ही लिखना शुरू कर चुकी थीं। पांडव श्रृंखला पर उनकी किताब से उन्हें बहुत शोहरत मिली। अनुजा चंद्रमौली की *द गॉड ऑफ डिजायर ऐंड शक्ति: द डिवाइन फेमिनिन* और *गंगा: द कॉन्सटेंट गॉडसेस* के अलावा *अर्जुन: सागा ऑफ ए पांडव वॉरियर प्रिंस* अर्जुन के अलग पक्ष को सामने

लेखकों को महाभारत और रामायण के पात्र पसंद आ रहे हैं, क्योंकि इन पात्रों की कथाओं में बहुत गुंजाइश है, जो युवाओं को लुभाती हैं

लाती है। इरावती कर्वे के *युगांत*, कृष्णा उदयशंकर की त्रयी *गोविंदा*, कौरव और कुरुक्षेत्र के अलावा कृतिका नायर की किताब *अंटिल द लॉयंस: इकोज फ्रॉम महाभारत* और कविता काणे की *कर्णस वाइफ: द आउटकास्ट क्वीन* की भी खूब चर्चा रही।

मिथकीय और पौराणिक पात्रों की लोकप्रियता का ग्राफ सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी तक ही सीमित नहीं है। ऐसा ही रुझान दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं में भी बढ़ा है। अलबत्ता, क्षेत्रीय भाषाओं में अपने नए लेखकों का अभी टोटा है। अमीष की 2011 की किताब *इममॉर्टल मेल्हू* का कन्नड़ में अनुवाद करने वाले मैसूर स्थित लेखक एस. उमेश का करीब दशक भर बाद कहना है, “अगर आप पौराणिक कथाओं को नए संदर्भों में पेश करेंगे तो युवाओं में उसका बाजार अच्छा है।”

धारवाड़ स्थित मनोहर ग्रंथ माला के समीर जोशी भी कहते हैं कि देवदत्त पटनायक की कुछ साल पहले *जय* और इस साल जून में *सीता* के कन्नड़ अनुवाद की बिक्री अच्छी हुई। आनंद नीलकंठन के *असुर* और *राइज ऑफ शिवगामी* के कन्नड़ अनुवादों की बिक्री भी अच्छी हुई। लेकिन एक समस्या है। अंकित पुस्तक के प्रकाशक कंबलहाली कहते हैं, “कन्नड़ में ऐसे मूल लेखक नहीं के बराबर हैं। बाजार तो है मगर बहुतों को शायद इसके बारे में जानकारी नहीं है।”



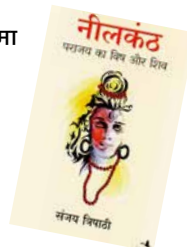
प्रशांत सिंह
कल्किकाल कथा- समयान्त रहस्य
प्रकाशन वर्ष 2019

समयान्त रहस्य में मैंने विज्ञान और पौराणिक पात्रों के संगम से कथा बुनी है। मैंने भाषा सरल रखी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा इस पुस्तक श्रृंखला से जुड़ सकें। पौराणिक पात्रों पर अंग्रेजी में ही ज्यादा उपन्यास लिखे गए हैं हिंदी में वैक्यूम था, जो अब खत्म हो रहा है



संजय त्रिपाठी
नीलकंठ पराजय का विष और शिव
प्रकाशन वर्ष 2019

पहली कृति *मेरा राम मेरा देश* लिखी थी। फिर इतिहास के प्रति रुचि जगी। आर्य आए तो द्रविड़ों से संघर्ष हुआ। आर्यों की ओर से विष्णु थे तो द्रविड़ों की ओर से शिव। आर्य जीते लेकिन पराजय का विष जिसने पूरी गरिमा के साथ पिया वो शिव ही थे। यही वजह है कि शिव सबसे बड़े देवता बनकर उभरे



आशुतोष नाइकर
शकुनि
प्रकाशन वर्ष 2019

पौराणिक कहानियों को तार्किक और रोचक ढंग से पेश करने की जरूरत है। आज पूरी दुनिया में धर्मान्धता चरम पर है। सुपर कंप्यूटर युग में भी धर्म महत्वपूर्ण है। जरूरत है, तो इसके मर्म को सही ढंग से जानने की। इसमें पौराणिक और धार्मिक कथाएं ही इसे जानने के बेहतर जरिया हो सकती हैं



गीता प्रेस का गुजरा जमाना

आजादी के दौरान 1923 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शुरू हुए गीता प्रेस महात्मा गांधी की प्रेरणा से राष्ट्र और अपनी संस्कृति के प्रति लोगों में अलख जगाने के महती कार्य में जुटा तो उत्तर भारत और हिंदी पट्टी के लोगों के घरों की देहरी उसकी किताबों और कल्याण पत्रिका से सजती गई। गांधी ने इसके संस्थापकों हनुमान प्रसाद पोद्दार और जय दयाल गोयंदका के सामने शर्त रखी थी कि दाम इतने सस्ते हों कि एकदम नीचले पायदान का आदमी खरीद सके और कोई विज्ञापन न छपा जाए। यही गीता प्रेस की आज भी कसौटी है। वरना आज भी 5 रुपये में किताबें आप कहाँ पाएंगे।

लेकिन इससे यह न जानिए कि बिक्री के आंकड़े कोई थोड़े हैं। तुलसीदास के रामचरितमानस की ही सालाना बिक्री तकरीबन 200 करोड़ रुपये की रही है। गीता प्रेस से छपी रामायण, महाभारत देश ही नहीं, दुनिया भर में भारतवर्षियों के लिए कम से कम एक पीढ़ी पहले तक अनिवार्य सी रही हैं।

यह भी सही है कि कन्नड़ में पौराणिक पात्रों के साहित्य की कभी कमी नहीं रही है। मसलन एस.एल. भैरप्पा महाभारत पर आधारित *पर्व* (1979), ए.आर. कृष्णाशास्त्री का *वचना भारता*, कुवेम्पु का *रामायण दर्शन* वगैरह। इसके अलावा आधुनिक दौर के शिवराम कारंथ, यू.आर. अनंतमूर्ति, लंकेश जैसे अनेक नामवर लेखकों के महत्वपूर्ण काम हैं।

इसी तरह तमिलनाडु में भी अमीष और देवदत्त के तमिल अनुवाद अब बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। हालाँकि चेन्नै में किताबों की सबसे बड़ी दुकान ओडिशी के मालिक अश्विन का कहना है कि अंग्रेजी की मूल किताबें ही ज्यादा बिकती हैं, तमिल अनुवाद के ग्राहक थोड़े ही हैं। तमिलनाडु में बड़े प्रकाशन समूह में एक एलार्थस पब्लिकेशंस के मालिक श्रीनिवासन कहते हैं कि राजाजी और चो रामस्वामी के महाभारत और रामायण ही पौराणिक साहित्य में सबसे अधिक बिकते हैं। वे कहते हैं, दिसंबर-जनवरी में सालाना पुस्तक मेले में भी उन्हीं की किताबें बिकीं। 60 के दशक में कि.वा. जगन्नाथन और पी. श्री जैसे लेखकों के निधन के बाद उस कोटि के लेखक नहीं उभरे।

इसी तरह ओडिया में पौराणिक कथा-वस्तु पर लिखी किताबों का टोटा नहीं है। सबसे चर्चित ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त लेखिका प्रतिभा राय *यज्ञसेनी*, रमाकांत रथ की *श्रीराधा* और हरिप्रसाद दास की *वंशा 70* और 80 के दशक की हैं। रामचंद्र बेहरा की *गोपापुरा*, प्रदीप दास की *चारु चिबरा चरज्ञ* और अर्चन नायक की *रानी श्यामबती* भी महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं। लेकिन 2016 में *अंबा* से चर्चित लक्ष्मीप्रिया आचार्य इस रुझान को



समर्पण: गोरखपुर में गीता प्रेस का द्वार

उसकी 1926 में शुरू हुई पत्रिका *कल्याण* के ग्राहकों की संख्या भी लाखों में रही है। अब भी उसका सर्कुलेशन दो लाख के करीब बताया जाता है। बेशक, गीता प्रेस के प्रकाशन लागत से आधे या 90 फीसदी कम पर बेचे जाते हैं और यह गांधी की शर्त के मुताबिक सरकारी मदद भी नहीं लेता, लेकिन किताबों के बिकने की वजह तो उसका मिशन ही रहा है, जो लोगों में आस्था जगाता रहा है। हालाँकि पिछले कुछ समय से नई पीढ़ी की दिलचस्पी घटने से गीता प्रेस में संकट की खबरें भी आईं। संभव है, मूल शास्त्रों-ग्रंथों में घटती दिलचस्पी का ही यह नतीजा हो। इसी की वजह से नए पौराणिक 'पॉप' साहित्य का रुझान भी परवान चढ़ा हो सकता है।

गीता प्रेस हिंदी के अलावा 15 भाषाओं में किताबें प्रकाशित करता है। अंग्रेजी में पत्रिका का नाम *कल्याण-कल्पतरु* है। इसका सर्कुलेशन भी करीब एक लाख है। गीता प्रेस पर पुस्तक लिखने वाले पत्रकार और शोधार्थी अक्षय मुकुल कहते हैं कि संस्था हर वक्त नए तरीकों से भी परहेज नहीं करती। संस्था की वेबसाइट से ऑनलाइन किताबें मंगवाई जा सकती हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या नई पीढ़ी इससे आकर्षित होगी या 'पॉप' में ही रमी रहेगी।



उत्कर्ष श्रीवास्तव

रणक्षेत्रम

प्रकाशन वर्ष 2017

मैंने आर्यावर्त की भूमि को एकता

के सूत्र में बांधकर

चक्रवर्ती सम्राट भरत

के अखंड भारतवर्ष

की स्थापना की

कल्पना की। मैं

रणक्षेत्रम के अंतिम

खंड पर काम कर

रहा हूँ। मैंने *रणक्षेत्रम* के

पहले दो खंडों का अंग्रेजी में अनुवाद

किया। उन्हें पढ़कर ऐसा लगा कि

कथानक की मूल भावना नहीं आ पा

रही, इसलिए हिंदी में ही डटे रहने का

फैसला किया



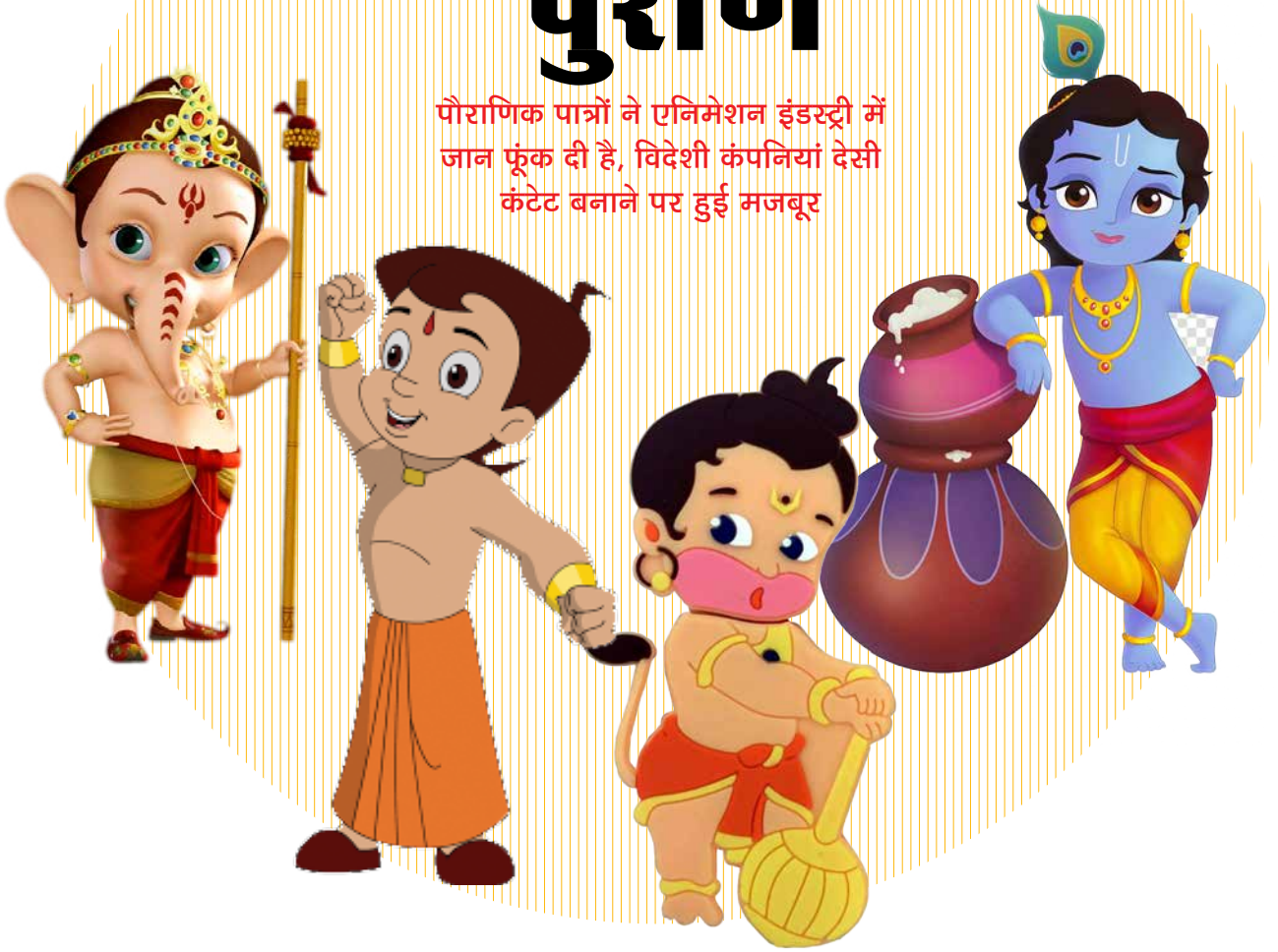
नया कहने से सहमत नहीं हैं, "रामायण और महाभारत 5000 साल पुराने हैं। उनसे हर दौर में लेखकों को प्रेरणा मिलती है।" ओडिया में इसका चलन भी नहीं है।

हिंदी में मुख्यधारा के अलावा लोकप्रिय साहित्य में नरेन्द्र कोहली के राम और दूसरे पौराणिक पात्रों की कहानियाँ भी खूब पढ़ी गईं। एक वक्त बेहद सस्ती गीता प्रेस, गोरखपुर की किताबें और पत्रिका *कल्याण* हर घर की शोभा हुआ करती थीं, लेकिन वह दौर सिमटता गया है तो नए युवाओं के लिए ये नए तरह का साहित्य कुछ उसकी भरपाई कर रहा है। दूसरी वजह टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में खासकर हिंदी प्रकाशकों की सिकुड़ती दुनिया भी नए बाजार की तलाश के लिए बाध्य कर रही है। ज्यादातर प्रकाशक अपनी किताबों की खरीद के लिए सरकारी और कॉलेज-विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरियों पर आश्रित हो गए थे और खुली बिक्री के लिए किताबें बहुत ही कम छपने लगी थीं। सरकार तथा सत्ता प्रतिष्ठान का रुख बदला तो संभव है, उन्हें अपने प्रकाशनों का रंग-ढंग भी बदलना पड़ा हो। लेकिन क्या यह दौर भी गुजर जाएगा? एका (वेस्टलैंड) की मीनाक्षी ठाकुर कहती हैं, हमारे पौराणिक साहित्य में युद्ध, प्रेम, षड्यंत्र, जासूसी, बहुविवाह, राक्षसी कारनामों और जितने ही तरह के जादुई असर की आप कल्पना कर सकते हैं, सब कुछ है। जाहिर है, 'मिलेनियल' पीढ़ी की दिलचस्पी के लिए बहुत कुछ है।

—साथ में चेन्नै से **जी.सी. शेखर**, भुवनेश्वर से **संदीप साहू** और बेंगलूरु से **अजय सुकुमारन**

कॉमिक्स पुराण

पौराणिक पात्रों ने एनिमेशन इंडस्ट्री में
जान फूंक दी है, विदेशी कंपनियां देसी
कंटेन्ट बनाने पर हुई मजबूर



प्रशांत श्रीवास्तव

मनुष्य का दिमाग जो कुछ भी सोच सकता है उसको मूर्त रूप देने की क्षमता एनिमेशन विधा में होती है। वॉल्ट डिजनी का यह प्रसिद्ध कथन आज भारतीय पौराणिक पात्रों पर हूबहू लागू हो रहा है। हनुमान, बाल गणेश, कृष्ण, भीम, राम, घटोत्कच, अर्जुन जैसे पात्र आज भारतीय एनिमेशन इंडस्ट्री के असली हीरो बन गए हैं। यही नहीं, इन पात्रों ने पूरी दुनिया में प्रसिद्ध चरित्रों को भी टक्कर दे दी है। भारतीय दर्शकों के पास अब उनका अपना सुपरमैन हनुमान है। इसी तरह श्रीकृष्ण स्पाइडरमैन से कहीं ज्यादा लोगों को लुभा रहे हैं। बदलती पसंद

का ही आलम है कि न केवल देसी कंटेन्ट की मांग बढ़ रही है, बल्कि उसको पूरा करने के लिए 300 एनिमेशन, 40 वीएफएक्स और 80 गेम डेवलपमेंट स्टूडियो खुल गए हैं, जिनमें करीब 15,000 प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। अनुमान यह है कि 10 हजार करोड़ रुपये की एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री अगले पांच साल में 20 हजार करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लेगी।

इंडस्ट्री से जुड़े और कंटेन्ट राइटर अभिषेक शुक्ला कहते हैं, “पिछले एक दशक में भारतीय एनिमेशन

इंडस्ट्री में बहुत कुछ बदल गया है। पहले कंटेड का मतलब आउटसोर्सिंग होता था। यानी सुपरमैन, स्पाइडर मैन जैसे आयातित पात्र ही हम भारतीय दर्शकों को परोसते थे। इसकी वजह से उनकी लोकप्रियता एक दायरे तक सीमित थी। लेकिन जब से इंडस्ट्री ने भारतीय पात्रों को कंटेड का हिस्सा बनाया है, सब कुछ बदल गया है।”

मांग पूरा करना मुश्किल

अभिषेक के अनुसार मांग इतनी है कि उसे पूरा करना मुश्किल हो रहा है। भारतीय संस्कृति के सभी लोकप्रिय पात्रों को लोग देखना चाहते हैं। ये पात्र लोगों के हीरो हैं। जिनकी कहानियां लोगों ने सुनी है या पढ़ी है, उसे अब वे जीवंत रूप में देखना चाहते हैं। एनिमेशन इसका अहम माध्यम बन गया है। क्योंकि यहां पर प्रयोग करने की छूट कहीं ज्यादा है। इसी वजह से पौराणिक और ऐतिहासिक पात्र काफी तेजी से लोकप्रिय हुए हैं, जिसको भुनाने के लिए भारतीय कंपनियों के साथ-साथ विदेशी कंपनियां भी भारत में तेजी से पैर पसार रही हैं।

विदेशी भी लगा रहे दांव

केपीएमजी की 2019 में आई रिपोर्ट के अनुसार एनिमेशन इंडस्ट्री को इस समय सभी प्लेटफॉर्म से मांग मिल रही है। टेलीविजन, डिजिटल और फिल्म इंडस्ट्री तीनों से ग्रोथ आ रही है। विदेशी प्रोडक्शन हाउस भारत में देसी कंटेड के लिए दांव लगा रहे हैं। ऐसा करने की बड़ी वजह बड़ा बाजार और सस्ती प्रोडक्शन लागत है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में एनिमेशन डेवलपमेंट उत्तरी अमेरिका, फिलिपींस और कोरिया से करीब एक तिहाई सस्ता है।

इस वजह से भारतीय स्टूडियो इस समय सोनी, डिज्नी, बीबीसी, 20 सेंचुरी फॉक्स, वार्नर ब्रदर्स, डीएम वर्क्स, वॉयकॉम, टर्नर जैसे विदेशी प्रोड्यूसर के साथ काम रहे हैं। एनिमेटेड कंटेड के सबसे बड़े दर्शक बच्चे हैं। इनमें भी 61 फीसदी बच्चे शहरों के और 39 फीसदी ग्रामीण इलाकों के हैं। बढ़ती डिमांड का ही परिणाम है कि आज भारत में बच्चों के 44 चैनल प्रसारित हो रहे हैं।

ऐसा नहीं कि केवल टीवी पर ही पौराणिक कंटेड की मांग है, छोटा कृष्ण और घटोत्कच-मास्टर ऑफ मैजिक जैसी फिल्मों भी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। श्री-डी फिल्म छोटा कृष्ण को एशियन टेलीविजन अवार्ड्स से नवाजा गया था। इसी तरह घटोत्कच को 2008 में कान फिल्म



बच्चों पर दांव: देसी कंटेड बच्चों को सबसे ज्यादा लुभा रहे हैं

महोत्सव में भी प्रदर्शित किया गया। इसी तरह हनुमान और द रिटर्न ऑफ हनुमान ने भारतीय सिनेमाघरों में खूब धूम मचाई।

ज्यादा एपिसोड

पौराणिक पात्रों की लोकप्रियता की एक बड़ी वजह भारतीयों की सोच भी है। इसे गाजियाबाद के रहने वाले नीरज पांडे की बातों से समझा जा सकता है। वह कहते हैं, “मेरी दो बेटियां हैं, उन्हें अपनी संस्कृति को बताने का सबसे अच्छा और आसान तरीका ये कार्यक्रम और फिल्में हैं। हम लोग जब छोटे थे तो दादा-दादी से कहानियां सुनते थे या फिर किताबों में पढ़ते थे। आज संयुक्त परिवार नहीं रह गए हैं, किताबें पढ़ने का भी दौर नहीं है, ऐसे में अपनी संस्कृति और पूर्वजों को बच्चों तक पहुंचाने का यह आसान रास्ता है। अब तो मोबाइल पर भी कंटेड मौजूद हैं, जिससे यह आसान हो गया है।”

दर्शकों की बढ़ती रुचि को देखते हुए प्रोड्यूसर्स ने कार्यक्रम बनाने का तरीका भी बदल दिया है। केपीएमजी की रिपोर्ट के अनुसार पहले प्रोड्यूसर किसी पात्र या कहानी पर कोई कार्यक्रम बनाते थे तो उसे वह ज्यादा से ज्यादा 12-13

एपिसोड का बनाते थे। लोकप्रियता ज्यादा हुई तो 25-26 एपिसोड तक बन जाते थे, पर अब यह ट्रेंड बदल गया है। अब कार्यक्रम 100-200 एपिसोड के बनाए जा रहे हैं। जैसे, वॉयकॉम-18 अपने तीन चैनलों के जरिए बच्चों के लिए 205 घंटे का कार्यक्रम तैयार कर रहा है, जबकि 2018-19 में उसने केवल 105 घंटे का कार्यक्रम तैयार किया था। इसी तरह डिस्कवरी किड्स ने भी 2019-20 में कंटेड की अवधि दोगुना कर दी। इन सभी चैनलों का जोर देसी कंटेड पर है। चैनलों की बदली रणनीति की वजह ये आंकड़े बताते हैं। निक चैनल के दर्शकों में 58 फीसदी भारतीय कंटेड देखा जाता है। पोगो चैनल पर 56 फीसदी, डिस्कवरी किड्स पर 54 फीसदी और सोनी वाईएवाई पर 52 फीसदी भारतीय कंटेड देखा जा रहा है। जब स्थानीय कंटेड की इतनी ज्यादा मांग है तो प्रोड्यूसर्स को भी उसी पर फोकस करना होगा।

भारत में इंटरनेट यूजर्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब पौराणिक पात्र मोबाइल पर भी पहुंच गए हैं। इस वजह से कई कंपनियों ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए इस बड़े बाजार तक पहुंचने की तैयारी कर ली है। इसी के मद्देनजर करीब 50 फीसदी एनिमेशन प्रोडक्शन डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए किए जा रहे हैं। बढ़ती मांग को वाऊ किड्स के 2.6 करोड़ सब्सक्राइबर से समझा जा सकता है, वाऊ किड्स कॉसमॉस-माया का यूट्यूब नेटवर्क है।

साफ है कि पौराणिक और ऐतिहासिक पात्रों ने सुस्त चाल से चल रही एनिमेशन इंडस्ट्री को नया मंत्र दे दिया है। आने वाले दिनों में लोगों को कहीं ज्यादा देसी कंटेड मिलेंगे, जिसमें उनका साक्षात्कार देसी मिट्टी से निकले हीरो से ज्यादा होगा और जिनकी गाथाएं जन-जन की जुबान पर हैं।





“हैरी पॉटर की लोकप्रियता से बड़ा पौराणिक गल्प”

गैरी इमेजेज

अंग्रेजी में पौराणिक पात्रों के इर्द-गिर्द कथा बुनकर कई किताबों और फिल्मों में अपनी आमद-रफ्त से मशहूर हुए देवदत्त पटनायक से आकांक्षा पारे काशिव की बातचीत के अंश:

हिंदी में पौराणिक चरित्रों पर बढ़ते लेखन और अचानक इन चरित्रों को लेकर दिलचस्पी का आप क्या कारण मानते हैं?

मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत हैरी पॉटर की लोकप्रियता से हुई है। हैरी पॉटर लोकप्रिय हो गया और उस पर फिल्में आने लगीं तो लोगों की रुचि लोककथाओं और दंतकथाओं, आख्यानों में बढ़ने लगी। यह सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में हो रहा है। मैं यही मानता हूँ कि दंत कथाओं की वापसी हुई तो पौराणिक चरित्र साहित्य का हिस्सा हो गए।

आपको कब विचार आया कि पुराण या मिथकीय चरित्रों को लेकर लोगों के बीच जाना चाहिए। लोगों को ये कहानियां अचानक क्यों लुभाने लगीं?

मैं लंबे अरसे से इन विषयों पर काम करता रहा हूँ। लगभग 20 साल से मैं इन पर काम कर रहा हूँ। लेकिन जब हैरी पॉटर की बात हुई तो लोगों को लगा कि हमारे पास भी ऐसी कथाएं हैं और वे दंतकथाओं की ओर मुड़ने लगे। एक कारण यह हो सकता है। लेकिन हमारे यहां भारत में एक दिक्कत यह भी है कि हमारा शिक्षा तंत्र तकनीकी पढ़ाई पर ज्यादा जोर देता रहा है। हमारे यहां

“इन कथाओं ने कल्पना के द्वार खोल दिए हैं, इसलिए ये कहानियां लोगों को लुभा रही हैं। माइथोलॉजी और फिक्शन दोनों अलग-अलग हैं। इसका घालमेल ठीक नहीं”

विज्ञान पर ज्यादा जोर होता है, साहित्य पर नहीं। हमारे यहां कल्पना पर ज्यादा जोर नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ, हर व्यक्ति में कल्पना और कहानी के लिए प्राकृतिक जिज्ञासा और प्रतिभा होती है। इन कथाओं ने कल्पना के द्वार खोल दिए हैं, इसलिए भी हो सकता है कि ये कहानियां लोगों को लुभा रही हैं।

आजकल कई युवा इनमें हाथ आजमा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इन पात्रों की नए सिरे से व्याख्या कर रहे हैं, उन्हें अपने नजरिये से लिख रहे हैं, आपको लगता है इन पात्रों से इस तरह छेड़छाड़ उचित है?

सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि माइथोलॉजी और माइथोलॉजी फिक्शन दो अलग-अलग हैं। माइथोलॉजी में हम जानना चाहते हैं कि वाल्मीकी क्या व्यक्त करना चाहते थे, तुलसीदास क्या व्यक्त करना चाहते थे। लेकिन जब आप इसमें फिक्शन जोड़ देते हैं तो बात दूसरी हो जाती है। यह समझना ही होगा कि माइथोलॉजी फिक्शन नहीं है और दोनों को अलग ही रहना चाहिए। आप

देखिए कि अलग-अलग भाषाओं में जो रामायण और महाभारत लिखी गई, उनमें उस काल की अभिव्यक्ति है। लेकिन आजकल जो लेखन हो रहा है, उसमें लेखक अपनी इच्छाएं देवी-देवताओं के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। जब हम इसमें फिक्शन जोड़ देते हैं तो हम परंपराओं के बारे में नहीं सीखते, बल्कि अपनी ओर से ही कहानी कह रहे होते हैं। जो लोग फेमिनिज्म की बात करना चाहते हैं वो सीता, द्रौपदी या शूर्पणखा के माध्यम से इसे व्यक्त करते हैं। जो राष्ट्रवाद की बात करना चाहते हैं वे शिव, राम, कृष्ण को लेकर राष्ट्रवाद के बारे में बात करते हैं। उनकी न रामायण में रुचि है, न शास्त्रों में या न ही पुराणों कि उनमें क्या लिखा गया। नए दौर के लेखन या फिक्शन राइटिंग के लेखक वेदों में रुचि नहीं रखते बल्कि कल्पना या अपने विचार व्यक्त करने के लिए इनका सहारा ले रहे हैं और देवी-देवताओं को पात्र बनाते हैं।

आप सरल भाषा में पुराण समझाते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि इतना सरलीकरण पुराणों का हो ही नहीं सकता। कई बार पुराणों की कहानियों को लेकर भी मतभेद सामने आते हैं, जब आप अपनी पुस्तक लिखते हैं तो इनकी विश्वसनीयता के लिए क्या उपाय करते हैं?

जो लोग पुराणों के बारे में ऐसा कहते हैं, उन्हें पुराणों का ज्ञान ही नहीं है। पुराण लिखे गए थे, ताकि वेदों का ज्ञान आसान और सरल तरीके लोगों तक पहुंच सके। कहानी लोक परंपरा या यूँ कहें देसी परंपरा है। मंत्र और तत्व ज्ञान गूढ़ भाषा में होता है। यह केवल ब्राह्मणों तक सीमित रहता है, लेकिन लोक परंपरा तक जाने के लिए कहानियों की जरूरत पड़ती है। एक पौराणिक कथा के अलग-अलग रूप होते हैं, जो देश और काल के हिसाब से बदलते हैं। वाल्मीकि रामायण और *रामचरितमानस* की तुलना करेंगे, तो पाएंगे कि वाल्मीकि रामायण दो हजार साल पहले संस्कृत में लिखी गई थी, जबकि तुलसीदास ने *रामचरितमानस* 500 साल पहले अवधी में लिखा। तुलसीदास जब लिख रहे थे तब भारत में मुगलों का राज था। माना जाता है कि लिखित वाल्मीकि रामायण जो हमें मिली है, वह मौर्य और गुप्त काल के बीच की है। *रामचरितमानस* में ज्यादातर भक्ति युग दिखाई देता है, जबकि वाल्मीकि रामायण में ज्ञान योग और कर्म योग को ज्यादा महत्व दिया गया है। साथ ही इसमें धर्म को भी महत्व दिया गया है। *रामचरितमानस* में भक्ति और मोक्ष को भी महत्व दिया गया है। इसी तरह अलग-अलग प्रांतों में आप देखें तो पाएंगे कि ओडिशा के जगन्नाथदास की नंदी रामायण बिलकुल अलग दिखाई पड़ती है। या 17वीं शताब्दी में तुलसीदास के साथ ही लिखी गई वैदेही विद्वांस की रामायण पढ़ें तो पाएंगे कि उसमें शृंगार और माधुर्य भाव की अधिकता है। उड़िया



“आजकल जो लेखन हो रहा है, उसमें लेखक अपनी इच्छाएं देवी-देवताओं के जरिए व्यक्त कर रहे हैं। इसमें फिक्शन जोड़ देते हैं तो उसमें परंपरा नहीं रह जाती है”

रामायण में इस भाव की अधिकता है। हर प्रांत में, हर समय में, हर देश-काल में यह बदलाव दिखाई देता है। जब हम कहते हैं कि रामायण और महाभारत एक ही हैं, तो यह गलत है। हर देश-काल के अनुसार इसमें अंतर है।

साहित्य में मिथक या पुराण लेखन का बहुत बाजार नहीं था, प्रकाशक भी इस तरह की चीजें छापने से कतराते थे। आपको अपनी किसी पुस्तक के प्रकाशन में कभी किसी दिक्कत का सामना करना पड़ा?

नहीं मुझे कभी ऐसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। बीस साल पहले भी प्रकाशक ही मेरे पास आए थे और अब भी आते हैं। बीस साल पहले भी मुझे प्रकाशक ने पूछा था कि क्या मैं

उनके लिए किताबें लिख सकता हूँ। मेरी किताबें लोगों को पसंद आती हैं, इसकी मुझे खुशी है। मैं अभी भी साल में चार किताबें और सौ के करीब लेख लिखता हूँ।

जिस तरह से साहित्य में कहानी या उपन्यासों की बिक्री होती है, आप मानते हैं कि मिथकीय चरित्रों पर लिखी किताबों का भी उतना ही बाजार है?

आप उपन्यासों को मिथकीय चरित्र पर लिखी किताबों के न समकक्ष रख सकते हैं, न तुलना कर सकते हैं। दोनों में बहुत फर्क है। सबसे पहले तो यह समझना होगा कि कौन सा विषय मनोरंजन के लिए है, कौन सा आध्यात्म के लिए और कौन सा शिक्षा के लिए। उपनिषद पर लिखी किताब उपन्यास नहीं हो सकती। आप रामायण को शेक्सपियर या हैरी पॉटर की कथा से नहीं जोड़ सकते। हैरी पॉटर फैंटेसी है, कल्पना है। लेकिन मिथकीय पात्र कल्पना नहीं हैं। इसे इतिहास भी नहीं कहा जा सकता। इतिहास और कल्पना के बीच में जो है, वह मिथकीय पात्र हैं। मैं देखता हूँ कि लोग ईश्वर को लेकर लिखते हैं और उसे फिक्शन कह देते हैं। ईश्वर को आप फिक्शन नहीं कह सकते। यह आस्था का विषय है, उसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। माइथोलॉजी बिलकुल अलग बात है और फिक्शन बिलकुल अलग। दोनों का घालमेल करना ठीक नहीं।

कन्दोवर्सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है

लेकिन कंटेंट तो अहम है, उसी से दिलचस्पी पैदा होती है, जरूरी यह भी है कि किताबें ज्यादा लोगों तक पहुंचें



अमीष त्रिपाठी

ईमानदारी से कहूं तो मैंने बहुत सोच-विचार कर नहीं लिखा। कभी यह नहीं सोचा कि अगर मैं भगवान शिव पर लिखूं तो लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, किताब प्रकाशित होगी कि नहीं, बिकेगी कि नहीं। यूँ समझ लीजिए, शायद मैं अपने लिए या अपने परिवार के लिए लिख रहा था। मेरी आत्मा में यह कहानी बस गई थी, मेरे अंदर यह फलसफा बस गया था। मैं इसे बस लिखना चाहता था। यही वजह थी कि मैंने बिना

ज्यादा सोच-विचार के इसे लिखना शुरू कर दिया। मेरे मन में कहीं न कहीं गीता का उपदेश चल रहा था। प्रभु श्रीकृष्ण ने हमें जो उपदेश दिया है, कर्मण्ये वा धिकारस्ते..., मैं उसी राह पर निकल पड़ा था। इस कहानी को लिखने का मेरे अंदर इतना जबर्दस्त प्रवाह था कि मैं यह सोचने में वक्त लगाना ही नहीं चाहता था कि लिखने के बाद क्या होगा।

शिव पर लिखने की वजह यही रही कि मुझे खुद उनके बारे में जानने की बहुत उत्कंठा थी। हमारे यहां सिर्फ *शिव पुराण* ही नहीं, कई महापुराण हैं, जिनमें शिव के बारे में लिखा गया है। *शिव पुराण* को शैव उपासना से जोड़ा जाता है। लेकिन *स्कंद पुराण*, *लिंग पुराण* और भी कई हैं जिन्हें शैव पुराण कहा जाता है। इन सबमें जो कहानियां हैं वो बचपन में मैंने कई बार सुनी थीं, कुछ मन में ज्यों की त्यों बसी हुई थीं। मेरे बाबाजी, यानी दादा काशी में पंडित थे। मां-पिताजी भी काफी धार्मिक हैं। परिवार में शुरू से धार्मिक माहौल था, बचपन से ही धर्मग्रंथों के बारे में सुना था, उन्हें पढ़ा था। मैं मानता हूँ कि कहानी लिखने की जो पहली इच्छा है, वह परिवार से ही मिली। मेरी पैदाइश ऐसे परिवार में हुई, यह मेरी खुशकिस्मती है। मुझ पर शिवजी का ही आशीर्वाद है जो मैं ये कहानियां लिख पाया। या यह कहूं कि उन्होंने मुझसे लिखवा लिया। उनका आशीर्वाद है तो मेरे लिए लिखना कठिन नहीं रहा।

कुछ लोग कहते हैं कि मैंने देवी-देवताओं की कहानी लिखने की नई परंपरा शुरू की है। ऐसा नहीं है, देवी-देवताओं की कहानियां नए रूपों में कहना पुरानी भारतीय परंपरा रही है। हमेशा से हमारे यहां नए रूप में ऐसी कहानियां कही जाती रही हैं। *रामचरितमानस* को ही लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मूल वाल्मीकि रामायण में बहुत तब्दीली की है। कोई भी संस्कृत नाटक देख लीजिए। इसमें आपको तब्दीली मिलेगी। कालिदास खुद कहते थे कि उनकी राय में भास उनसे बेहतर लेखक थे। भास ने तो अपने नाटक *पंचरात्र* में महाभारत की पूरी कहानी बदल डाली थी। ऐसे कई उदाहरण हैं। भारत के लोग अपने देवी-देवताओं की कहानियां सुनने में न कभी थकते हैं, न ऊबते हैं। हम हर कहानी को बार-बार सुन सकते हैं, अलग-अलग पहलू से सुन सकते हैं। इसलिए इस तरह के चरित्रों या पात्रों पर बहुत किताबें आ रही हैं। यह अच्छा है कि और लेखक यह सब लिख

रहे हैं और बड़ी बात है कि हिंदी में लिख रहे हैं। इससे हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति को और शक्ति मिलती है। यह सही है कि हमारे यहां हिंदी किताबों की बिक्री उतनी नहीं होती, क्योंकि इनकी मार्केटिंग ठीक से नहीं होती। लेकिन यह दिक्कत सिर्फ हिंदी की नहीं, बल्कि सभी भारतीय भाषाओं में है। हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकों की मार्केटिंग होती ही नहीं है, जबकि अंग्रेजी में किताबों की मार्केटिंग बड़े जोर-शोर से होती है। शायद यही वजह है कि इनकी बिक्री ज्यादा हो जाती है। मेरा मानना है कि हिंदी प्रकाशकों को भी अपनी मार्केटिंग सुधारना चाहिए और दायरा विस्तृत करना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में अच्छी किताब लिख देने भर से किताब नहीं बिकती। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि कंटेंट अच्छा न हो। कंटेंट तो अच्छा होना ही चाहिए लेकिन किताबों की पहुंच ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए।

जब मैं *शिव-त्रयी* लिख रहा था तो कई लोगों का कहना था कि शिव के मेरे अपने पाठ पर कन्दोवर्सी हो सकती है। मैं मानता हूँ कि ज्यादातर कन्दोवर्सी लोग खुद फैलाते हैं। इससे किताबों की मार्केटिंग हो जाती है। यह मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। लेकिन जो भी मेरी किताबें पढ़ेंगे, भले ही उसे किताबें पसंद आए या न आए, वह यह तो मानेगा कि मैंने शिव की कहानी को बहुत प्रेम से लिखा है, श्रद्धा से लिखा है। जिन देवी-देवताओं के बारे में मैं लिखता हूँ, मैं खुद उनकी पूजा करता हूँ, उनमें श्रद्धा रखता हूँ। मैं खुद कभी नहीं चाहता कि जिनके बारे में मैं लिख रहा हूँ, उनकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच आए। शायद इसलिए भी कन्दोवर्सी नहीं होती।

मैंने कई पौराणिक कथाएं और इतिहास पढ़ा है। यह बहुत ही रोमांचक है। मैं लोगों को कहता हूँ कि इसे पढ़ना ही चाहिए। मैं बार-बार यह भी कहता हूँ कि हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार होना चाहिए। हमारे शास्त्रों और पुराणों की जानकारी बच्चों को दी जानी चाहिए, क्योंकि इनमें मौजूद कहानियां वाकई बहुत रोमांचक हैं। यहां मैं सिर्फ अपनी किताबों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे जो शास्त्र हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये कहानियां पढ़कर बच्चों को वाकई मजा आएगा, साथ में उन्हें सीख भी मिलेगी, वे अपनी जड़ों से जुड़ेंगे। इन कहानियों में इतनी ताकत है, इसका अंदाजा टेलीविजन धारावाहिक *रामायण* से लगा लीजिए। 1985 में यह पहली बार टेलीविजन पर प्रसारित हुआ था। 35 साल बाद इसका दोबारा प्रसारण हुआ। आज के धारावाहिकों की तुलना में इसमें कोई चमक-दमक नहीं थी। इसका बजट कम था। लेकिन इसकी व्यवस्थापन लगभग आठ करोड़ तक पहुंच गई। दुनिया भर के सबसे बड़े शो *गेम ऑफ़ थ्रोन्स* को पूरी दुनिया में उतने दर्शक नहीं मिले, जितने *रामायण* को सिर्फ भारत में ही मिल गए। सोचकर देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि हम सब अपनी जड़ों से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। युवा पीढ़ी को भी इन कहानियों में बहुत रुचि है और वह भी इससे जुड़ी हुई है।

(शिव त्रयी के लेखक। आकांक्षा पारे काशिव से बातचीत पर आधारित)

भारत के लोग अपने देवी-देवताओं की कहानियां सुनने में न कभी थकते हैं, न ऊबते हैं। इसलिए इस तरह के चरित्रों या पात्रों पर बहुत किताबें आ रही हैं



सरकारी दरखल पर कई बवाल

चारधाम समेत 51 मंदिरों पर नियंत्रण के लिए बोर्ड बनाने का विरोध, इसे धामों की गुल्लक पर कब्जे का प्रयास बताया, भाजपा में ही असंतोष

☞ देहरादून से अतुल बरतरिया

उत्तराखंड सरकार ने राज्य के चारधाम समेत अन्य देवस्थलों पर सरकारी नियंत्रण के लिए एकट बनाकर चारधाम देवस्थानम बोर्ड का गठन किया है। इस बोर्ड का पुजारी और तीर्थ पुरोहित विरोध कर रहे हैं। सरकार इसे चारधाम विकास के लिए ऐतिहासिक कदम बता रही है तो विरोध करने वाले इसे धामों की गुल्लक पर कब्जे का प्रयास मान रहे हैं। एक भाजपा सांसद इसके

क्यों चाहिए नियंत्रण: उत्तराखंड चारधाम में से एक बदरीधाम मंदिर

खिलाफ हाइकोर्ट भी गए, लेकिन कोर्ट ने एकट को सही करार दिया। इसके बाद भी विरोध जारी है। गंगोत्री धाम मंदिर समिति ने तो बोर्ड की सहमति लिए बिना ही सैनिकाइजेशन के नाम पर धाम को 15 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया है।

उत्तराखंड स्थित केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम विश्व प्रसिद्ध हैं। इन धामों में हो रहे विकास कार्यों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी कई बार मॉनिटरिंग कर चुके हैं। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड सरकार ने एक एकट के तहत उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड का गठन किया है। इसमें उक्त चार धामों के साथ आसपास के ही छोटे-बड़े 47 अन्य मंदिरों और देवस्थलों को भी शामिल किया है।

अभी तक बदरीधाम और केदारनाथ की व्यवस्था के लिए एक मंदिर समिति थी। यह भी एक तरह से सरकारी ही थी, लेकिन यह व्यवस्था दशकों पुरानी थी। अन्य दो धामों और मंदिरों में व्यवस्था सदियों से अलग-अलग समुदाय

के पुजारियों और पुरोहितों के हाथ में थी। दान और चढ़ावा भी इन्हीं के हाथों में आता था और व्यवस्थाएं भी इनकी समितियां बनाती खिलाफ हाइकोर्ट भी गए, लेकिन कोर्ट ने एक्ट को सही करार दिया। इसके बाद भी थीं। अब सब कुछ सरकारी नियंत्रण वाले बोर्ड के अधीन आ गया है।

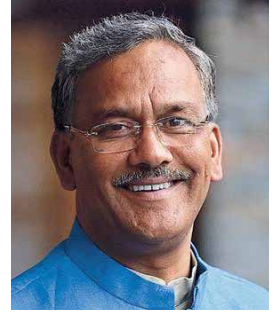
श्रीबदरीनाथ डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के अध्यक्ष आशुतोष डिमरी कहते हैं, “हम विकास का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सदियों से चली आ रही व्यवस्था पर हमला सहन नहीं किया जाएगा।” डिमरी बताते हैं कि अंग्रेजों के समय 1939 में बदरी-केदार मंदिर समिति का गठन किया गया था और 1964 में इसमें कुछ संशोधन हुए। यही समिति दोनों धामों का सारा काम देखती है। यहां का मुख्य पुजारी रावल केरल के नंबूदरीपाद संप्रदाय से होता है। उनका वेतन नियत है। विशेष पूजा से आने वाली राशि का साढ़े सात फीसदी रावल को दिया जाता है और साढ़े तीन फीसदी स्थानीय पुजारियों को मिलता है। धाम परिसर में ही बने लक्ष्मी मंदिर और कामधेनु मंदिर के साथ ही हवन-पूजन, चरणामृत, भोग पर भी डिमरी समुदाय के पुजारियों का हक है। आरती के थाल पर भंडारी, मेहता, कामदी और श्योकार समाज का हक है। घंटाकर्ण पर भंडारी समुदाय का हक है। इसी तरह, गंगोत्री धाम पर पूरी तरह से सेमवाल समुदाय के पुजारियों और पंडों का हक है। गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल कहते हैं कि सरकार इस धाम के विकास के नाम पर पुजारियों के पुश्तैनी हक को खत्म करना चाहती है। यमुनोत्री धाम के लिए भी एक मंदिर समिति है। इस धाम पर उनियाल समुदाय का हक है। समिति के सचिव कीर्तेश्वर उनियाल कहते हैं कि सरकार की निगाहें धाम के गुल्लक पर लगी हैं। सरकार अगर इस धाम का विकास करना चाहती है तो समिति हर तरह का सहयोग करने को तैयार है, लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं। इसी के खिलाफ नैनीताल हाइकोर्ट की शरण ली गई थी।

बोर्ड गठन से पहले केवल केदारनाथ धाम को एक तरह से सरकारी नियंत्रण में कहा जा सकता था। यहां के मुख्य पुजारी रावल और नायब रावल को मंदिर समिति की ओर से मासिक वेतन दिया जाता है। अन्य कर्मचारी भी वेतनभोगी हैं। यहां के रावल कर्नाटक के लिंगायत समुदाय से आते हैं। इस धाम के अधीन आने वाले अन्य देवस्थलों पर परंपरागत रूप से स्थानीय पुजारियों और तीर्थ पुरोहितों का नियंत्रण है।

सरकार ने जो देवस्थानम् बोर्ड बनाया है, उसका सीईओ अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम स्केल पाने वाले अफसर को बनाया गया है। मुख्यमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष और संस्कृति मंत्री उपाध्यक्ष हैं। सदस्यों में से तीन पद इन हक-हकूकधारी पुरोहितों और पुजारियों के लिए हैं,

बोर्ड बनाने का मकसद चारधाम और अन्य देवस्थलों का विकास करना है। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि सभी तीर्थ पुरोहितों के हितों पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े। कोर्ट ने भी फैसले पर मुहर लगा दी है

त्रिवेन्द्र सिंह रावत
मुख्यमंत्री, उत्तराखंड



लेकिन इन्हें नामित सरकार ही करेगी। एक्ट के अनुसार पुजारियों, न्यासियों, तीर्थ पुरोहितों और पंडों के हक-हकूक और प्रचलित देय या दस्तूरत यथावत रहेंगे। हर देवस्थल पर चढ़ावे के लिए हुंडी (दानपात्र) लगाई जाएगी, इन पर केवल बोर्ड का अधिकार होगा। बोर्ड ही धामों के विकास के लिए पैसा खर्च करेगा, लेकिन एक धाम का पैसा किसी दूसरे धाम में नहीं लगाया जाएगा।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का कहना है कि

1939 में अंग्रेजों के समय बदरी-केदार मंदिर समिति का गठन किया गया था। 1964 में इसमें कुछ संशोधन हुए थे। तब से यही समिति दोनों धामों का काम देखती थी

सरकार ने चारधाम और अन्य देवस्थलों के विकास और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए देवस्थानम् बोर्ड का गठन किया है। एक्ट बनाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि सभी तीर्थ पुरोहितों के हक-हकूकों पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े। नैनीताल हाइकोर्ट ने भी सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है।

बोर्ड का विरोध करने वालों के अपने तर्क हैं। इनका कहना है कि बोर्ड में सभी धामों और अन्य देवस्थलों को शामिल करके सरकार स्थानीय पुजारियों और पुरोहितों का हक मारने की कोशिश कर रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस एक्ट का वक्फ बोर्ड और सिख गुरुद्वारा अधिनियम पर कोई असर नहीं होगा। साथ ही, कभी भी नए मंदिरों को इस बोर्ड में शामिल किया जा सकेगा। बोर्ड विरोधी कहते हैं, आखिर क्या कारण है कि सरकार केवल हिंदू समाज के मंदिरों का ही

सरकारीकरण करने पर आमादा है। तमाम विरोधों के बीच नवगठित बोर्ड ने कार्यभार संभाल लिया है और पहली बार चारधाम यात्रा का संचालन कर रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी भी बोर्ड के विरोधी हैं। उन्होंने इसके गठन को एक जनहित याचिका के जरिए नैनीताल हाइकोर्ट में चुनौती दी। रूरल लिटिगेशन एंड एनटाइटलमेंट केंद्र (रूलक) ने खुद को इस याचिका में पक्षकार बनवाया और बोर्ड के गठन को जायज करार दिया। हाइकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद फैसला दिया कि एक्ट में किसी तरह के संशोधन की जरूरत नहीं है।

स्वामी ने एक ट्वीट के जरिए उत्तराखंड भाजपा पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने लिखा कि उत्तराखंड भाजपा के नैतिक पतन से दुखी हूं। भाजपा के लोग ईसाई संस्थाओं से पैसा लेकर मेरी याचिका का विरोध कर रहे हैं। नैनीताल से लोकसभा सदस्य अजय भट्ट भी कह चुके हैं कि इस बोर्ड को खत्म करना चाहिए। यह एक्ट भलाई के लिए लाया गया था, लेकिन अब अगर यह बुराई बन रहा है तो सरकार इसे खामियां दूर करने तक के लिए स्थगित कर दे या इसे खत्म कर दे। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडेय ने भी पुरोहितों के पत्रों का हवाला देते हुए सरकार से इस पर पुनर्विचार करने की अपील की है।

पार्टी नेताओं के रवैये से उत्तराखंड भाजपा की स्थिति असहज हो गई है। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष बंशीधर भगत कहते हैं, “मेरी जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं कि किसी नेता ने ईसाई संस्था से पैसे लिए हों। स्वामी वरिष्ठ नेता हैं, हो सकता है उनके संज्ञान में कुछ आया हो।” प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ ही मीडिया प्रभारी का दायित्व संभाल रहे डॉ. देवेंद्र भसीन कहते हैं कि ऐसे लोगों के नाम सार्वजनिक करने चाहिए थे। गंगोत्री धाम मंदिर समिति ने नए अंदाज में बोर्ड का विरोध शुरू किया है। समिति ने पहले तो चारधाम यात्रा शुरू करने के बोर्ड के निर्णय का विरोध किया। बाद में धाम के कपाट 15 अगस्त तक के लिए बंद कर दिए। तर्क दिया कि कोरोना संकट के चलते वहां सफाई और सैनिटाइजेशन का काम किया जाना है।



एस.के. सिंह

विक्रम देकाते की औरंगाबाद में डेक्सन कास्टिंग नाम की कंपनी है, जो दोपहिया वाहनों के लिए एल्युमिनियम कास्टिंग करती है। उन्होंने प्रॉपर्टी के एवज में एक एनबीएफसी से कर्ज ले रखा था। लॉकडाउन के दौरान कैशफ्लो घट गया तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत वर्किंग कैपिटल लोन लेने की सोची। एनबीएफसी के अलावा कई सरकारी और निजी बैंक गए, पर सरकार की शर्तों के विपरीत सब कोलैटरल मांग रहे हैं। पुराने कर्ज की ईएमआइ पर तीन

महीने का मोरेटोरियम लिया है, लेकिन उससे ईएमआइ की अवधि 10-11 महीने बढ़ गई। चिंता है कि अगर फिर मोरेटोरियम लेना पड़ा तो ईएमआइ कई साल के लिए बढ़ जाएगी। स्थिति खराब हुई तो कर्मचारियों की छंटी करनी पड़ेगी, हो सकता है

पैकेज बिना सब सूना

मुख्य आर्थिक सलाहकार के अनुसार दूसरा राहत पैकेज कोरोना का वैक्सीन आने के बाद, लेकिन पैकेज को अनिश्चितता से जोड़ना कितना उचित

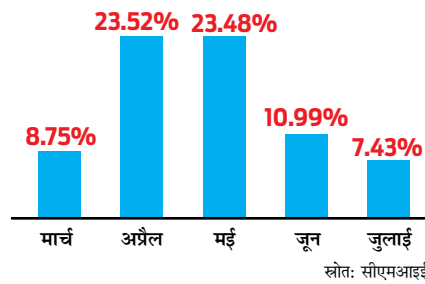
कंपनी भी बंद करनी पड़े। इसलिए विक्रम चाहते हैं कि सरकार ऐसे कदम उठाए जिनसे मांग बढ़े और कैशफ्लो सुधरे।

लेकिन सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यम के बयान के बाद विक्रम को भरोसा नहीं कि स्थिति जल्दी सुधरेगी। सुब्रमण्यम के अनुसार कोविड-19 महामारी का वैक्सीन तैयार होने के बाद सरकार दूसरा राहत पैकेज लेकर आएगी। उद्योग जगत तो तत्काल राहत की उम्मीद लगाए बैठा ही है, ज्यादातर अर्थशास्त्री भी मानते हैं कि सरकार जितनी देर करेगी, हालात उतने खराब होंगे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इनफॉर्मल सेक्टर एंड लेबर स्टडीज से हाल ही रिटायर हुए और इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैनेजमेंट रिसर्च के पूर्व महानिदेशक प्रो. संतोष मेहरोत्रा ने आउटलुक से कहा कि राहत पैकेज को वैक्सीन से जोड़ना सर्वथा अनुचित है। सरकार को कर्ज लेकर खर्च करने की जरूरत है। आइएचएस मार्किट के एपीएससी (एशिया-प्रशांत) चीफ इकोनॉमिस्ट राजीव विश्वास कहते हैं, कई वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के चरण में हैं, सबसे एडवांस ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप का है और उसके भी दिसंबर से पहले पूरा होने की उम्मीद नहीं है। वैक्सीन के बाजार में आने की कोई तय समय सीमा नहीं है। इसलिए राहत पैकेज को अनिश्चित टाइमलाइन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, खासकर तब जब अर्थव्यवस्था घोर मंदी की ओर

बढ़ रही हो और करोड़ों लोग इसकी मार झेल रहे हों। हालांकि कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि इंतजार करने में बुराई नहीं। उद्योग चैंबर सीआइआइ की चीफ इकोनॉमिस्ट विदिशा गांगुली कहती हैं कि वैक्सीन का उपभोक्ता सेंटिमेंट पर सकारात्मक असर होगा, इसलिए उस समय सरकार जो भी खर्च करेगी उसका अर्थव्यवस्था पर असर भी अधिक होगा। सरकार के पास फंड की समस्या है और अतिरिक्त खर्च से रेटिंग घटने और वित्तीय अस्थिरता का खतरा रहेगा।

भारत में जुलाई में कोरोना संक्रमण 200% बढ़ा और मरने वालों की संख्या 116% बढ़ी। इसे रोकने के लिए राज्य सरकारें जब-तब लॉकडाउन कर रही हैं, जो अर्थव्यवस्था को पट्टी पर लाने में बड़ी बाधा बन रहे हैं। मैनुफैक्चरिंग लगातार चौथे महीने गिरी, जुलाई की स्थिति जून से भी खराब है। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में मैलकम आदिशेषैया चेयर प्रोफेसर अरुण कुमार का मानना है कि शुरू में लॉकडाउन ठीक से लागू नहीं किया गया, इसलिए बार-बार ऐसा करना पड़ रहा है। डिमांड बढ़ाने के लिए मदद जरूरी है, खासकर उनकी जिनकी नौकरियां चली गई हैं। असंगठित क्षेत्र में 20 करोड़ नौकरियां गई हैं और ये गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। इस तरह कुल 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, इनके लिए सर्वाइवल पैकेज चाहिए। प्रो. अरुण कुमार के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की तरह शहरों के लिए भी रोजगार गारंटी स्कीम की जरूरत है, क्योंकि अनेक ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरी तो चली गई पर वे अपने गांव वापस नहीं गए या गांव से लौटकर तो आए, लेकिन शहरों में काम नहीं मिला है। सीएमआई के अनुसार संगठित क्षेत्र में 1.4 करोड़ नौकरियां गई हैं,

बेरोजगारी दर में सुधार



खर्च बढ़े पर राजस्व घटा

टैक्स	संग्रह	अंतर
कुल कर	2,69,686	-32.6%
कॉर्पोरेशन टैक्स	54,212	-23.2%
आयकर	62,123	-35.9%
कुल खर्च	8,15,944	13%

(आंकड़े अप्रैल-जून 2020 के, कर संग्रह करोड़ रुपये में)

अनेक लोगों के वेतन में भी कटौती हुई है।

कुछ वस्तुओं की मांग बढ़ी पर यह कुछ इलाकों तक सीमित है। ग्रामीण इलाकों में शहरों की तुलना में पाबंदी कम है, इसलिए वहां मांग में वृद्धि है। वहां बेरोजगारी दर भी शहरों से कम है, लेकिन आगे

खरीदार कहां: जुलाई के पहले पखवाड़े फैशन रिटेल कंपनियों की बिक्री एक चौथाई रह गई

मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रो. मेहरोत्रा के अनुसार गांवों में लोगों को इसलिए काम मिला क्योंकि मार्च-अप्रैल में जब वे गांव लौटे तो उस समय फसल कटाई का मौसम था, उसके बाद खरीफ की बुवाई-रोपाई होने लगी। अब वहां कोई काम न होने के कारण मजदूर वापस शहर आना चाहते हैं, लेकिन शहरों में भी उनके लिए काम की कमी है। कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह शुरू नहीं हुआ, इसलिए इस सेक्टर में पहले जितने मजदूर थे उतने नहीं खप सकते। सर्विस सेक्टर में एयरलाइंस, पर्यटन, होटल एवं रेस्तरां, ट्रांसपोर्ट ज्यादातर में बिजनेस ठप पड़े हैं। सीआइआइ की विदिशा भी मानती हैं कि मिनी लॉकडाउन से काफी अनिश्चितता पैदा हो रही है और बिजनेस करना मुश्किल हो रहा है। सरकार के अधिकारी भले 'हरी कॉपलें' दिखने की बात कह रहे हों, आइएचएस मार्केट के राजीव के अनुसार महामारी पर नियंत्रण पाने तक स्थायी रिकवरी मुश्किल है।

गैर-जरूरी खर्च घटे

असंगठित क्षेत्र में तो बेहिसाब नौकरियां गई हैं, संगठित क्षेत्र में भी कम ही हैं जिनकी नौकरी और सैलरी दोनों बची है, इसलिए लोग गैर-जरूरी खर्च नहीं कर रहे हैं। केपीएमजी के एक सर्वे में 78% उपभोक्ताओं ने कहा कि वे जरूरी वस्तुओं को छोड़ बाकी खर्चों में कटौती करेंगे। भारी-भरकम डिस्काउंट के बावजूद फैशन रिटेल कंपनियों का 'एंड ऑफ सीजन सेल' फ्लॉप साबित हुआ है। पहले सेल के दौरान सामान्य दिनों की तुलना में दो से ढाई गुना ज्यादा बिक्री होती थी। इस बार बिक्री 10% से 20% ही बढ़ी। रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार जुलाई के पहले पखवाड़े में फैशन रिटेल कंपनियों की बिक्री एक चौथाई रह गई। डाटा एनालिटिक्स फर्म नीलसन के अनुसार एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में एफएमसीजी की बिक्री में अभी तक गिरावट का ही ट्रेंड है। हालांकि एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल समेत कुछ सेक्टर ने जून की तुलना में जुलाई में बेहतर प्रदर्शन किया है।

रियल एस्टेट ब्रोकरेज फर्म प्रॉप टाइगर के अनुसार अप्रैल-जून के दौरान आठ बड़े शहरों में घरों की बिक्री 79 फीसदी घटकर 19,038 यूनिट रह गई। बैंकिंग और फाइनेंस, एफएमसीजी, आईटी और फार्मा को छोड़ दें तो बाकी कंपनियों की बिक्री जून तिमाही में औसतन 35% और मुनाफा 60% घटा है। प्रो. अरुण कुमार के अनुसार मांग कम होने के चलते निवेश भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जब पुरानी क्षमता का ही पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा तो नए निवेश से नुकसान और बढ़ जाएगा।

कॉमर्शियल वाहनों की बिक्री आर्थिक गतिविधियों का संकेत देती हैं। केयर रेटिंग्स का अनुमान है कि मौजूदा वित्त वर्ष में इनकी बिक्री 30% से 35%



पीटीआइ

फीसदी घट सकती है। मझोले और बड़े आकार के वाहनों में ज्यादा गिरावट का अंदेश है। इन वाहनों के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी आरएसबी ट्रांसमिशन के एमडी और वाइस चेयरमैन एस.के. बेहरा ने बताया कि पिछले साल इस सेगमेंट की कंपनियों की बिक्री 35% गिर गई, इस साल पहली तिमाही में गिरावट 80% है। उनकी कंपनी में अभी सिर्फ 15% उत्पादन हो रहा है। बेहरा के अनुसार सरकार ने अब भी कुछ नहीं किया तो हालात काफी बिगड़ जाएंगे।

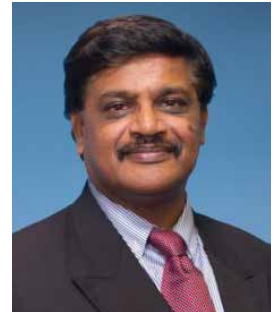
मांग कम होने के चलते कोर इंडस्ट्री का उत्पादन चार महीने से लगातार गिर रहा है। अप्रैल-जून तिमाही में गिरावट 24.6% है। ऐसे में जीएसटी संग्रह का घटना भी लाजिमी है। जुलाई में हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे औद्योगिक राज्यों के जीएसटी संग्रह में 12% से लेकर 25% तक की गिरावट आई है। इसलिए विभिन्न संस्थाओं ने मौजूदा वित्त वर्ष में विकास दर -3.2% से -9.5% तक रहने का अंदेशा जताया है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का आकलन है कि प्रमुख एशियाई देशों में रिकवरी के मामले में भारत की स्थिति सबसे खराब है। यानी कोरोना से पहले के स्तर पर पहुंचने में भारत को सबसे अधिक समय लगेगा। प्रो. मेहरोत्रा मानते हैं कि 2019-20 में अर्थव्यवस्था का जो आकार था, उस स्तर पर 2023-24 में ही पहुंच सकेंगे।

आने वाले दिन फाइनेंशियल सिस्टम के लिए भी संकट भरे हो सकते हैं। रिजर्व बैंक ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कहा है कि बैंकों का ग्रांसे एनपीए मार्च 2021 में 12.5% तक पहुंच सकता है, जो मार्च 2020 में 8.5% था। स्थिति और खराब हुई तो यह 14.7% तक भी जा सकता है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के मुताबिक सरकार को यह

राहत पैकेज को वैक्सीन के अनिश्चित टाइमलाइन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, खासकर तब जब अर्थव्यवस्था घोर मंदी की ओर बढ़ रही हो और करोड़ों लोग इसकी मार झेल रहे हों

राजीव विश्वास

चीफ इकोनॉमिस्ट, आइएचएस मार्किट एपीएस



सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी रहे ताकि फाइनेंशियल सिस्टम संकट में न आए। मौद्रिक नीति की समीक्षा में केंद्रीय बैंक ने कर्ज की एक बार रिस्ट्रक्चरिंग की अनुमति दी है, उम्मीद है कि इससे बैंकों को कुछ राहत मिलेगी।

पहले पैकेज का असर

सरकार ने मई में जीडीपी के 10 फीसदी के बराबर, 21 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की थी लेकिन इसका खास असर नहीं दिखा। प्रो. अरुण कुमार इसकी वजह बताते हुए कहते हैं कि सरकार सिर्फ दो लाख करोड़ रुपये खर्च कर रही थी, बाकी तो लिक्विडिटी और कर्ज बढ़ाने के उपाय थे। उनका आकलन है कि इस साल जीडीपी 35 फीसदी गिर जाएगी, इसलिए कम से कम पांच-छह फीसदी के बराबर पैकेज चाहिए। प्रो. मेहरोत्रा बताते हैं, 2008 का आर्थिक संकट अभी की तुलना में आधा भी नहीं था लेकिन उस समय जीडीपी के तीन से चार फीसदी के बराबर पैकेज दिया गया था, जबकि इस बार अभी तक सरकार ने सिर्फ एक फीसदी का पैकेज दिया है।

प्रो. मेहरोत्रा सरकार के खर्च बढ़ाने के कई दावों को भी सही नहीं मानते। वे कहते हैं, एक तो पूरे साल के दौरान खर्च के बजटीय प्रावधानों को शुरू में ही खर्च करने की बात कही गई। आयकर रिफंड लोगों को वैसे ही मिलना चाहिए, उसे भी पैकेज में जोड़ दिया गया। सरकार ने एमएसएमई के बकाए का जल्दी भुगतान करने की बात कही। प्रो. मेहरोत्रा पूछते हैं, बकाए का भुगतान पैकेज का हिस्सा कैसे हो सकता है? राजीव विश्वास तत्काल दूसरे पैकेज की वकालत करते हुए कहते हैं कि मई के बाद महामारी काफी बढ़ी और मंदी ज्यादा गहरी हो गई है, इसलिए अतिरिक्त उपायों की जरूरत है। यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड और अमेरिका भी नए पैकेज ला रहे हैं।

पहले पैकेज के सकारात्मक पक्ष बताती हुई सीआईआई की विदिशा कहती हैं, गरीबों को नकद और अनाज उपलब्ध कराया गया जिसने रिकवरी शुरू करने में बड़ी भूमिका निभाई है। सीएमआई के अनुसार जून में बेरोजगारी दर घटकर 11% पर आ गई जो अप्रैल-मई में 23% से अधिक थी। जीएसटी संग्रह, रेलवे से माल ढुलाई, पेट्रोल की खपत, बिजली की मांग और टोल कलेक्शन के आंकड़े बताते हैं कि अर्थव्यवस्था में रिकवरी हो रही है।

क्या करना चाहिए

प्रो. अरुण कुमार के अनुसार लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए तत्काल पैकेज जरूरी है। सरकार को मनरेगा के लिए चार लाख करोड़ रुपये देने चाहिए और शहरी इलाकों में सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे



रौनक गायब: कई राज्यों में मॉल खुले पर खरीदारों की संख्या बहुत कम

भारत की विकास दर का अनुमान

वर्ल्ड बैंक	-3.2%
आईएमएफ	-4.5%
एडीबी	-4%
इका	-9.5%
एचडीएफसी बैंक	-7.5%
नोमुरा	-5.2%
एसएंडपी, फिच	-5%

पीटीआइ



संकट गहरा: कॉमर्शियल वाहन पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों में सिर्फ 20% उत्पादन, तस्वीर आरएसबी ट्रांसमिशन के जमशेदपुर प्लांट की

प्रोजेक्ट तेज करने चाहिए। सरकार 5-6 लाख करोड़ रुपये खर्च करे तो जरूरी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, इससे संगठित क्षेत्र में भी रोजगार बढ़ेगा। अप्रैल में कुल उत्पादन 25% से अधिक नहीं हो रहा था, यानी -75% की ग्राह्य थी। मई में यह -65% थी और अब भी -50% है। बजट भी नए सिरे से तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि पहले जो बजट बना था वह 10% नॉमिनल ग्रोथ के आधार पर था। प्रो. मेहरोत्रा की राय है कि सरकार को न्यूनतम आय की गारंटी देनी चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को तीन से चार महीने तक दो-दो हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाने चाहिए। उनका आकलन है कि इस पर लगभग 70 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा, लेकिन मांग बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी।

वाहन स्क्रेप पॉलिसी लागू करने से नए वाहनों की मांग बढ़ेगी। अनेक छोटे नर्सिंग होम बंद हो गए हैं, उनकी मदद करने से लोगों को नौकरियां तो वापस मिलेंगी ही, महामारी से लड़ने में भी मदद मिलेगी

विदिशा गांगुली

चीफ इकोनॉमिस्ट, सीआइआइ

सीआइआइ की विदिशा गांगुली कहती हैं, संकटग्रस्त सेक्टर को समर्थन की जरूरत है ताकि लोगों को नौकरियां मिल सकें। इससे एनपीए का खतरा भी कम होगा। वाहन स्क्रेप पॉलिसी लागू करने से आठ लाख पुराने वाहन सड़क से हटेंगे और नए वाहनों की मांग बढ़ेगी। पूंजी की कमी के चलते अनेक छोटे नर्सिंग होम बंद हो गए हैं। उनकी मदद करने से लोगों को नौकरियां तो वापस मिलेंगी ही, कोविड-19 महामारी से लड़ने में भी मदद मिलेगी। आइएचएस मार्किट के राजीव के अनुसार सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वैक्सीन के विकास में किसी तरह की रेगुलेटरी बाधा न आए। वैक्सीन डेवलपमेंट के अलावा सरकार उन करोड़ों लोगों की मदद करे जिनकी नौकरी चली गई या जिनकी कमाई के रास्ते बंद हो गए।



जीएसटी दरें बढ़ाने का सुझाव

आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती से एक नई समस्या खड़ी हो गई है। इस वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में कुल जीएसटी संग्रह 4.16 लाख करोड़ की तुलना में 34% गिर कर 2.72 लाख करोड़ रुपये रह गया है। केंद्र सरकार ने एक संसदीय समिति को बताया कि वह फिलहाल राज्यों की टैक्स की कमी की भरपाई (कंपेनसेशन) करने की स्थिति में नहीं है। कोविड-19 से लड़ने में राज्यों की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण है, इसलिए उनके पास फंड की कमी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में बाधक बनेगी। कुल सरकारी खर्च में 60% हिस्सा राज्यों का ही होता है। कर संग्रह बढ़ाने के लिए पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कुछ वस्तुओं को दोबारा 28% जीएसटी स्लैब में लाने, अमीरों के इस्तेमाल वाली सेवाओं पर 18 की जगह 28% टैक्स लगाने और सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पादों पर लगने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क को कंपेनसेशन सेस में शामिल करने के सुझाव दिए हैं। बादल के अनुसार केंद्र को उधार लेकर राज्यों को पैसा देना चाहिए क्योंकि राज्य सरकारें जो कर्ज लेंगी उस पर ब्याज की दर अधिक होगी। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का कहना है कि कोविड-19 की समस्या लंबे समय तक रहने वाली है, राज्यों के साथ केंद्र के सामने भी राजस्व का संकट है, इसलिए जीएसटी दरें बढ़ाई जानी चाहिए।

चंडीगढ़ से हरीश मानव

सहत्वाकांक्षा तो लाजवाब है। हरियाणा सरकार की उम्मीदें चीन से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के तथाकथित मोहभंग को देखते हुए परवान पर हैं। दावा है कि 60 बहुराष्ट्रीय कंपनियों समेत 600 से अधिक कंपनियों ने निवेश की संभावनाएं तलाशने के लिए राज्य सरकार के साथ संपर्क किया है। इनमें दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल से लेकर भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी भी शामिल हैं। मौके का फायदा उठाने के लिए राज्य की मनोहरलाल खट्टर सरकार नई औद्योगिक नीति लेकर आ रही है। लेकिन सवाल है कि क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने के लिए भारत अभी पूरी तरह तैयार है? विशेषज्ञ इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और ऑटोमेशन जैसे मामलों में भारत अभी चीन से बहुत पीछे है। विपक्ष का आरोप है कि यह सब सरकार के लिए बस एक इवेंट है।

चीन छोड़ो तो आओ हमारे देस

विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करने की खट्टर सरकार की खाहिश, पर इन्फ्रास्ट्रक्चर और दूसरी तैयारियों पर सवाल

विस्तार की कवायद: मारुति ने हरियाणा सरकार से 325 एकड़ अतिरिक्त जमीन मांगी

मुख्यमंत्री खट्टर कहते हैं, “सरकार ने कोविड-19 को अवसर के रूप में लेते हुए औद्योगिक और आर्थिक सुधारों पर जोर दिया है, जिसके चलते 60 बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने राज्य में निवेश की इच्छा जताई है।” उन्होंने बताया कि अनेक कंपनियां चीन से बाहर निकलना चाहती हैं और वे हरियाणा को निवेश के लिए आदर्श गंतव्य के रूप में देख रही हैं। नई इकाइयां स्थापित करने से पहले एक हजार दिनों के लिए श्रम कानूनों में राहत प्रदान की जाएगी। सरकार ने निवेश करने के इच्छुक उद्यमियों को लीजहोल्ड पर जमीन देने की पहल की है।

कहा जा रहा है कि राज्य के 22 में से 10 जिले दिल्ली-एनसीआर की 60 किलोमीटर की परिधि में होने का लाभ हरियाणा को मिल सकता है। राज्य में निवेश की संभावनाओं को सिरे चढ़ाने के लिए 15 अगस्त तक नई औद्योगिक नीति भी लाई जा रही है। हरियाणा में औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को रोजगार में बरीयता के लिए 75 फीसदी आरक्षण देने और फैक्टरीज एंड इंडस्ट्रियल एक्ट में संशोधन के लिए बिल बनाया है, जो राज्यपाल के पास विचाराधीन है। राज्य में 90 फीसदी सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम (एमएसएमई) हैं, इसलिए नई औद्योगिक नीति एमएसएमई पर केंद्रित होगी। इसके लिए अलग से एमएसएमई निदेशालय भी स्थापित किया जा रहा है।

लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला का कहना है, “विदेशी निवेश और निजी

पीटीआइ



क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण केवल झांसा है। बेरोजगारी कम करने की दिशा में सार्थक कदम उठाने के बजाय मनोहर लाल खट्टर सरकार निवेश और रोजगार को भी इवेंट की तरह ले रही है।" सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआई) के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुरजेवाला ने कहा कि कोरोना काल के पहले तीन महीने में हरियाणा में बेरोजगारी की दर देश में सर्वाधिक हो गई है। जून में आंध्र प्रदेश में बेरोजगारी की दर 2.1, असम में 0.6, बिहार में 19.5, गुजरात में 2.8, झारखंड में 21, मध्य प्रदेश में 8.20, महाराष्ट्र में 9.70, ओडिशा 4.2, राजस्थान 13.7, उत्तर प्रदेश 9.6, पश्चिम बंगाल 6.5 फीसदी रही जबकि हरियाणा में यह दर 33.60 फीसदी रही।

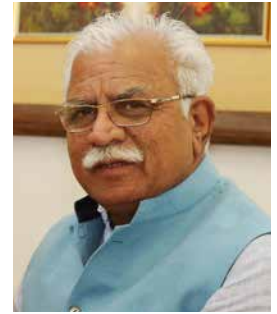
उपमुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री दुष्यंत चौटाला के मुताबिक नई औद्योगिक नीति में राज्य के सभी 22 जिलों में औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जाने की योजना है। एमएसएमई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने सभी जिलों में कृषि आधारित क्लस्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है। अभी तक राज्य में गुड़गांव, मानेसर, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल और यमुनानगर जिलों तक सिमटे औद्योगिक विकास को अब 'सी' और 'डी' श्रेणी के शहरों में भी उनकी विशेषता के मुताबिक विस्तारित किया जाएगा। औद्योगिक विकास के लिए एचएसआईआईडीसी के पास करीब 17,000 एकड़ लैंड बैंक है। जिन पंचायतों के पास 500 एकड़ या इससे अधिक भूमि अनुपयोगी है, वहां भी औद्योगिक इकाइयां विकसित करने की अनुमति होगी।

चौटाला ने आउटलुक को बताया, "2025 तक लागू रहने वाली इस नई औद्योगिक नीति के तहत राज्य में नई औद्योगिक इकाई लगाने और मौजूद औद्योगिक इकाइयों के विस्तार की प्रक्रिया सुगम करने के साथ कारोबार की प्रक्रिया को भी आसान किया जा रहा है।" उन्होंने बताया कि हरियाणा में उत्पादन बढ़ाने के लिए मारुति सुजुकी ने राज्य सरकार से 325 एकड़ भूमि मांगी है।

आउटलुक से बातचीत में केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा, "बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए राज्यों का मागदर्शन

अनेक कंपनियां चीन से बाहर निकलना चाहती हैं और वे हरियाणा को आदर्श गंतव्य के रूप में देख रही हैं। नई इकाइयां स्थापित करने से पहले एक हजार दिनों के लिए श्रम कानूनों में राहत प्रदान की जाएगी

मनोहरलाल खट्टर
मुख्यमंत्री, हरियाणा



किया जा रहा है। राज्यों से कहा गया है कि वे निवेश के लिए कारोबारियों से संबद्ध केंद्र और राज्य की तमाम स्वीकृतियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी ढंग से लागू करें।" केंद्र सरकार ने एफडीआई नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद कोई भी विदेशी कंपनी किसी भारतीय कंपनी का अधिग्रहण या विलय नहीं कर सकेगी। दुनिया भर में जारी कोरोना संकट के चलते गिरी अर्थव्यवस्था के बीच भारतीय कंपनियों का वैल्युएशन भी काफी गिर गया है, इसलिए सरकार को लगा कि कोई विदेशी कंपनी इस मौके का फायदा उठाते हुए कहीं किसी भारतीय कंपनी का औन-पौने दाम पर अधिग्रहण न कर ले।

हालांकि चीन में उत्पादन कर रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरफ से भारत में निवेश फिलहाल आसान नहीं लगता। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) मोहाली के पूर्व डीन डॉ. अजित रानगेकर का कहना है, "मैं ऐसी कोई संभावना नहीं

देख रहा हूं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन से अपने प्लांट हटाकर भारत में स्थापित करेंगी। ऐसी अटकलें चीन-अमेरिका के बीच चले ट्रेड वॉर के वक्त भी लगाई जा रही थीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था।" रानगेकर के मुताबिक इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और ऑटोमेशन के मामले में भारत अभी चीन से बहुत पीछे है। लेकिन सरकार समर्थकों के अपने तर्क हैं। स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक तरुण ओझा का कहना है कि कोरोना संकट के दौरान बहुराष्ट्रीय कंपनियों का चीन के प्रति नजरिया तेजी से बदला है। दो दशक से विश्व अर्थव्यवस्था चीन पर निर्भर थी, पर अब बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर उनके देशों की सरकारें चीन से कारोबार हटाने का दबाव बना रही हैं। ऐसे में चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी 135 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत में दूसरे देशों की तुलना में निवेश के अधिक मौके हैं।

लघु उद्योग भारती हरियाणा के महासचिव शुभादेश मित्तल मानते हैं कि कोरोना महामारी की चपेट में आने के बाद दुनिया के तमाम बड़े देश 'आत्मनिर्भर भारत' की तर्ज पर घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देंगे और विदेशी कंपनियों की जगह अपने देश की कंपनियों को संरक्षण देंगे। ऐसे में विदेशी निवेश के पीछे भागना तर्क संगत नहीं है। उनका कहना है कि विदेशी कंपनियों के प्रति आकर्षण की बजाय देश के एमएसएमई को वरीयता दी जानी चाहिए।

सेंटर फॉर रिसर्च इन रुरल एंड इंडस्ट्रियल डवलपमेंट (क्रिड) के नेहरु रिसर्च सेल के प्रमुख डॉ. आरएस घुम्पन का कहना है कि विदेशी निवेश के लिए उदारवाद का जो दौर भारत में 1991 में शुरू हुआ, वह चीन ने 1978 में शुरू किया था। इन चार दशकों में चीन ने खुद को एक वैश्विक उत्पादन धुरी के रूप में स्थापित कर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित किया। गरीबी में रह रहे वहां के करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर मिले, जिससे अमेरिका के बाद चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। दूसरी ओर, उदारवाद के तीन दशक बाद भी भारत में अपेक्षित विदेशी निवेश नहीं हो पाया। इन तीन दशकों में आईटी के क्षेत्र में भारत ने जरूर पहचान कायम की पर यहां के आईटी विशेषज्ञों ने भी बड़ी संख्या में अमेरिका और यूरोप का रुख किया है।

देश में नए औद्योगिक निवेश का रुझान (खरब रुपये)

सितंबर 2019	31.7
दिसंबर 2019	52.4
मार्च 2020	34.9
जून 2020	5.9

(आंकड़े सीएमआई के मुताबिक)

देश की सूचीबद्ध कंपनियों की माली हालत (आंकड़े प्रतिशत में)

	सितंबर 2019	दिसंबर 2019	मार्च 2020	जून 2020
आय	-2.3	-1.7	-4.7	-23.8
खर्च	-3.1	-2.2	-1.6	-25.7
शुद्ध लाभ	-1.3	-10.7	-44.1	-14.4

(आंकड़े सीएमआई के मुताबिक)

प्रशांत श्रीवास्तव

मैं दिखता इनसान हूँ
पर हूँ एक मशीन-
फिल्म रोबोट का

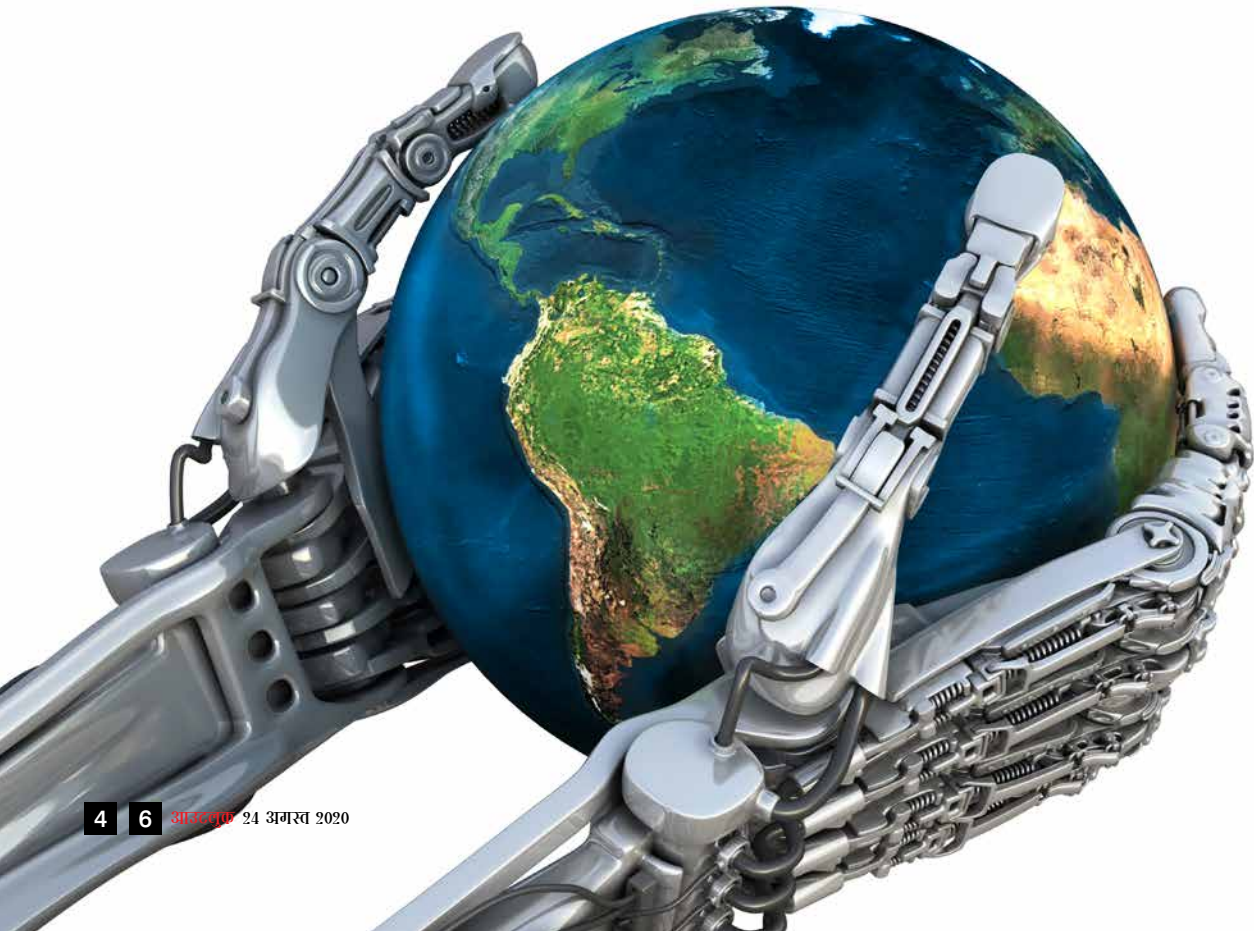
यह डायलॉग अब हकीकत के करीब है। कोविड-19 ने आपकी दुनिया में रोबोट की बड़े पैमाने पर एंट्री करा दी है। वह दिन अब दूर नहीं जब होटल की रिसेप्शनिस्ट, अस्पताल की नर्स, आपके घर की मेड, बिल्डिंग के सिव्क्योरिटी गार्ड की जगह रोबोट ले लेंगे। यही नहीं, आपको ऑनलाइन डिलीवरी भी ड्रोन से होने वाली है। चौंकिए मत, यह ऐसी दुनिया है जहां एक मशीन आपके सारे काम करेगी। “रोबोट वर्ल्ड” बड़ी तेजी से आपके चारों तरफ तैयार हो रहा है।

रोबोट लाओ, लोग हटाओ

कोरोना की वजह से तेजी से बढ़
रहा रोबोट का इस्तेमाल, सुविधाएं
तो बढ़ेंगी लेकिन बड़े पैमाने पर
नौकरियां खत्म होने का डर

भारत रोबोट के इस्तेमाल में सिंगापुर, थाइलैंड और कनाडा को पीछे छोड़ चुका है। सामान्य परिस्थितियों में जो मांग चार से पांच साल में आती, वह कोविड-19 की वजह से पिछले तीन से चार महीने में ही आ गई है। हालात यह है कि रोबोटिक्स सॉल्यूशन देने वाली कंपनियां मांग की तुलना में आपूर्ति नहीं कर पा रही हैं।

इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स की रैंकिंग-2019 के अनुसार भारत दुनिया में रोबोट के इस्तेमाल में 11वें स्थान पर पहुंच चुका है। फेडरेशन के प्रेसिडेंट जुंजी सूडा के मुताबिक, “भारत में रोबोट का इस्तेमाल सालाना 39 फीसदी की दर से बढ़ रहा है। खास बात यह है कि रोबोट के इस्तेमाल में जहां ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की हिस्सेदारी 44 फीसदी पहुंच गई है, वहीं रबर, प्लास्टिक, मेटल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी अन्य इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है।” फिक्की-नैसकॉम-ईवाय की रिपोर्ट ‘भारत में भविष्य की नौकरियां 2.0’ के अनुसार देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्रों में 2022 तक 5-20 फीसदी बिल्कुल नई तरह की नौकरियां होंगी। इनमें ऑटोमेशन का बोल-बाला होगा। मसलन ऑटोमोबाइल सेक्टर में मशीन लर्निंग आधारित साइबर सिव्क्योरिटी एक्सपर्ट,



आइटी सेक्टर में ऑर्टिफिशियल रिसर्च साइटिस्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज में रोबोट प्रोग्रामर, ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट, रिटेल सेक्टर में डिजिटल इमेंजिंग रीडर जैसी नई नौकरियां आने वाली हैं।

कोरोना ने कैसे बदली दुनिया

कोविड-19 की वजह से अचानक लगे लॉकडाउन ने कंपनियों के सामने ऐसी चुनौती खड़ी कर दी जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी समय आएगा कि वे तीन से चार महीने अपनी फैक्ट्रियां नहीं चला पाएंगी। इसे देखते हुए अब कंपनियों का जोर ऑटोमेशन पर है। उनका कहना है कि हम ऐसी व्यवस्था देख रहे हैं, जिसमें लॉकडाउन जैसी स्थिति में कम से कम नुकसान में काम कर सकें।

इंडिया रोबोटिक्स सॉल्यूशंस के संस्थापक एवं सीईओ सागर गुप्ता नौगरिया और सह-संस्थापक एवं सीएमओ प्रशांत पिल्लै के अनुसार, “मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो मांग हम अगले चार-पांच साल में उम्मीद कर रहे थे, वह इन तीन से चार महीने में आ गई। हर सेक्टर में मांग बढ़ रही है, खास बात यह है कि अब सर्विस सेक्टर में रोबोट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ने वाला है। मसलन होटल, अस्पताल, रेस्तरां और ऑनलाइन कंपनियों की तरफ से काफी मांग आ गई है। कंपनियां सोशल डिस्टेंसिंग और कम से कम मानव संपर्क की जरूरत को देखते हुए प्रोडक्ट की मांग कर रही हैं। कंपनियों ने वोकेशनल ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है।”



पिल्लै कहते हैं, “बदलाव कितनी तेजी से आ रहा है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कंपनियां अब वेयरहाउस में उत्पादों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी ऑटोमेशन पर जोर दे रही हैं। यानी जहां इनसानों के बिना काम करना संभव है, वहां वे मशीन का इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसा करने की एक बड़ी वजह यह है कि कंपनियों को इस बात का डर सताने लगा है कि अगर एक भी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हुआ तो तुरंत वेयरहाउस या ऑफिस को सील कर दिया जाएगा।” इसलिए कई कॉरपोरेट हाउस में अब कर्मचारियों का अटेंडेस सिस्टम भी बदलने वाला है। मसलन, वे ऐसे रोबोटिक्स सॉल्यूशंस मांग

नया अंदाज: बेंगलूरु के एक रेस्तरां में वेंटर की जगह रोबोट को काम



रहे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कर्मचारियों का तापमान लेने, उनकी पहचान करने और उनका पुराना रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था होगी। इसी तरह, पैकेजिंग का काम जो ज्यादातर मानव द्वारा किया जाता है, उसमें भी बड़े पैमाने पर कंपनियां ऐसी मशीनें मंगा रही हैं जो पैकेजिंग करेंगी। कारोबारियों ने सैनियाइजर के स्टिकर लगाने और मास्क बनाने के लिए भी अब मशीन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।

नौगरिया कहते हैं, “पिछले तीन-चार महीने में मांग दो से तीन गुना बढ़ गई है, लेकिन उसकी तुलना में आपूर्ति नहीं हो पा रही है। आयात नहीं हो पाना इसकी एक बड़ी वजह है। साथ ही दाम भी 25 फीसदी तक बढ़ गए हैं। इसलिए अब कंपनियां चाहती हैं कि उन्हें घरेलू स्तर पर ही सॉल्यूशन मिले। अगर सही नीतियां बनें और रोबोटिक्स इंडस्ट्री की जरूरतें पूरी होती हैं, तो भारत एक बड़ा निर्यातक भी बन सकता है।” पिल्लै के अनुसार कोरोना के दौर में ड्रोन ने सैनियाइजिंग से लेकर लोगों के तापमान लेने में बेहतरीन काम किया है। उनकी कंपनी ने ड्रोन के जरिए दिल्ली के स्लम एरिया में सैनियाइजेशन का काम किया है। ऐसा हेलमेट भी डिजाइन किया है, जिसके जरिए पांच मीटर की दूरी से एक साथ कई लोगों का तापमान लिया जा सकता है।

बढ़ती मांग को देखते हुए अब कंपनियां आदमी के आकार के रोबोट बना रही हैं जो होटल, एयरपोर्ट और ऑफिस में भी दिखने वाले हैं। ऐसे ही रोबोट बनाने वाले मिलाग्रो ह्यूमनटेक के चेयरमैन राजीव करवाल का कहना है, “पिछले तीन से चार महीने में कंपनी ने पूरे साल के बराबर काम कर लिया है। अगर आपूर्ति की समस्या नहीं आती तो कंपनी 1000 फीसदी की ग्रोथ हासिल कर लेती। उनका कहना है कि अस्पताल में मरीज से कम से कम संपर्क हो, इसके लिए मानव आकार वाले रोबोट काम आएंगे। इसी तरह एयरलाइंस टिकट चेकिंग के लिए, होटल में रिसेप्शन और दूसरी कस्टमर सर्विस के लिए, घर और ऑफिस में फ्लोर की सफाई के लिए, स्वीमिंग पूल और एयरकंडीशनिंग की सफाई के लिए भी रोबोट का इस्तेमाल शुरू हो गया है। करवाल के अनुसार उनके पास देश के प्रमुख होटल समूह आइटीसी, ओबेरोय और ताज होटल के साथ-साथ सोडेक्सो, सीबीआरआइ, रिलायंस जैसी कंपनियों से मांग आ रही है। इसके अलावा कंपनी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को भी सेवाएं दे रहे हैं। करवाल एक अहम बात और बताते हैं कि अब घरेलू स्तर पर भी काफी डिमांड आ रही है। मसलन, फ्लोर सफाई के लिए वरिष्ठ नागरिकों और कामकाजी कपल्स की ओर से रोबोट की काफी मांग आई है।

रोबोट की मांग देश के सभी क्षेत्रों से आ रही है। मसलन, करवाल कहते हैं, “कोविड के पहले 95

फीसदी मांग टॉप-5 शहरों (दिल्ली, मुंबई, चेन्नै, कोलकाता और बेंगलूरु) से थी, लेकिन अब इसका विस्तार 15 शहरों में हो गया है। इनमें पुणे, हैदराबाद, नागपुर, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, पटना, लखनऊ, रांची, इंदौर, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम जैसे शहर शामिल हैं। बढ़ती मांग को देखते हुए अब हम देश भर में चैनल पार्टनर (डीलर) बनाने की तैयारी कर रहे हैं। दिसंबर तक हम अपना नेटवर्क तैयार कर लेंगे।”

इसी तरह की मांग की बात प्रशांत पिल्लै भी करते हैं। उन्होंने बताया, “अहम बात यह है कि मांग मेट्रो शहरों के अलावा छोटे शहरों से भी आ रही है। कंपनियां नए-नए तरीके के सॉल्यूशंस पर जोर दे रही हैं। जैसे, लागत कम करने के लिए उनका फोकस सेंट्रलाइज्ड स्कैनिंग पर है। इसके लिए किसी बिल्डिंग या ऑफिस कॉम्प्लेक्स के प्रवेश द्वार पर ही स्कैनिंग सिस्टम लगाया जाएगा। इससे लागत घटने के साथ जोखिम भी कम होगा। इसी तरह, कृषि क्षेत्र में कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है।” हाल ही में राज्य सरकारों ने टिड्डियों के सफाए के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया है।

मोटर इंश्योरेंस क्लेम में ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) का इस्तेमाल एक और बेहतरीन उदाहरण है। इंश्योरेंस कंपनियां इसके जरिए क्लेम प्रक्रिया को बहुत तेजी से निपटाने की कोशिश कर रही हैं। इसका इस्तेमाल कर इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने नई सुविधा शुरू की है। इसके तहत जब कोई गाड़ी डैमेज हो जाती है तो उसकी मरम्मत या रिप्लेसमेंट पर कितना खर्च आएगा, इसका आकलन सर्वेयर और दूसरी टीम के जरिए किया जाता है। हमने नए सिस्टम में ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया है। इसमें ग्राहक को डैमेज वाले हिस्से की फोटो कंपनी के ऐप के जरिए खींच कर हमारे पास भेजनी होती है। फोटो के आधार पर ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अब हम कुछ मिनटों में आकलन कर लेते हैं कि मरम्मत पर कितना खर्च आएगा। अब हम 30 मिनट के अंदर कस्टमर की मंजूरी के बाद खर्च की राशि उसके अकाउंट में जमा कर देते हैं। पहले इस काम को करने में तीन से चार दिन लग जाते थे। इसका एक फायदा यह भी हुआ है कि अब कस्टमर को खर्च का आकलन करने के लिए गैरेंज में गाड़ी ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वह अपनी सुविधा के अनुसार गैरेंज में ले जाकर गाड़ी ठीक करा सकता है। कंपनी अभी

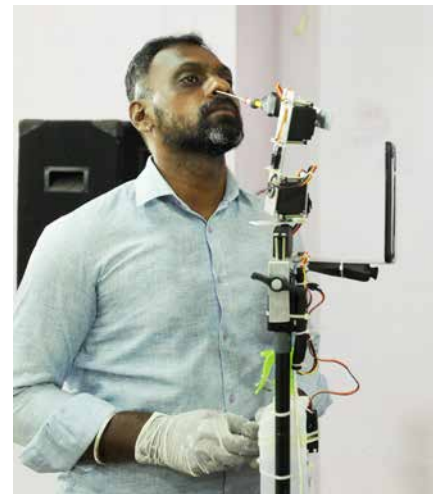
चार पहिया वाहनों के लिए 50 हजार रुपये और दोपहिया वाहनों के लिए 25 हजार रुपये तक का क्लेम एआइ की नई व्यवस्था के जरिए दे रही है। इसके जरिए ग्राहकों के साथ-साथ उनके लिए भी काम करना आसान हो गया है।



नए रूप में अस्पताल: कोविड संकट में अस्पतालों ने मरीजों की जांच और देखभाल के लिए रोबोट का इस्तेमाल शुरू कर दिया है

नौकरियों पर खतरा

ऐसा नहीं कि रोबोट की दुनिया जीवन को आसान ही करेगी। मशीनी दुनिया की एक कड़वी सच्चाई भी है। मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार एक रोबोट तीन लोगों का काम कर सकता है। यानी एक रोबोट लगने से तीन लोगों की नौकरी चली जाएगी। इसी के आधार पर रिपोर्ट बताती है कि भारत में 2030 तक 4.4 करोड़ पुरुषों और 1.2 करोड़ महिलाओं की नौकरी चली जाएगी। बढ़ते खतरे को स्वीकारते हुए सागर कहते हैं, “लॉकडाउन की वजह से नौकरियों में औसतन 10-20 फीसदी कटौती हुई है। जो कंपनियां ऑटोमेशन कर रही हैं वहां इन नौकरियों के तुरंत आने की संभावना नहीं है। ऐसे में यह एक नई तरह की चुनौती भी है। लेकिन एक बात हमें और



घर में भी एंट्री: फ्लोर की सफाई के लिए रोबोट का इस्तेमाल



समझनी होगी कि भारत रोबोटिक्स क्षेत्र में बड़ा निर्यातक बन सकता है। ऐसे में कंपनियों को अति कुशल श्रमिकों की जरूरत होगी। अभी जिस तरह के श्रमिकों से काम चलता है, वैसे श्रमिक जरूरत पूरी नहीं कर पाएंगे। हमें भविष्य की जरूरतों को देखते हुए श्रमिकों को तैयार करना होगा।” जाहिर है, कोरोना वायरस ने भारत को समय से पहले रोबोट की दुनिया में पहुंचा दिया है। ऐसे में अब इस हकीकत से हम मुंह नहीं मोड़ सकते कि हमारे चारों तरफ रोबोट का संसार तैयार हो रहा है। अब यह सरकार और कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वे इस चुनौती को अवसर में कैसे बदलती हैं। अगर वे ऐसा नहीं कर पाती हैं तो पहले से बढ़ती बेरोजगारी से परेशान युवा वर्ग के लिए रोजगार पाने की राह और मुश्किल हो जाएगी।



निर्माता-निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा ने पहली बार कश्मीर की पृष्ठभूमि पर थ्रिलर फिल्म खामोश (1985) बनाई थी। वही कश्मीर, जहां उनका बचपन बीता था। इसके बाद निजी जीवन में वे और गहरे उतरे और 2020 में शिकारा फिल्म लेकर आए। यह कश्मीरी पंडितों पर बॉलीवुड में बनी शायद पहली फीचर फिल्म है जिसने उनकी भावनाओं को व्यक्त किया, हालांकि कुछ ने इसका विरोध भी किया। लक्ष्मी देबरॉय के साथ बातचीत में चोपड़ा ने कश्मीर, अपनी यादों और फिल्म से जुड़े विवाद के बारे में बताया। मुख्य अंश:

आपकी यादों में जो कश्मीर बसा है, उसके बारे में बताइए।

कश्मीरी हमेशा कश्मीरी ही रहता है। वहां की

खूबसूरती, लोगों की गर्मजोशी, खान-पान, विरासत, संस्कृति सब मेरी यादों में गहरे बसे हुए हैं। उन्हें कोई भी मुझसे अलग नहीं कर सकता। कश्मीर में बड़ा होना, मेरे साथ हुई सबसे अच्छी बातों में से एक है। मेरा पहला क्रश, पहला प्यार, पहला चुंबन, सब कश्मीर में ही हुआ। मैं अपने बच्चों से कहता हूँ- मुझे अफसोस है कि तुम्हें कश्मीर में बचपन बिताने के मौका नहीं दे पाया।

कल्पना कीजिए, वहां साल के सभी चार मौसम हैं। पहले वसंत है, फिर गर्मी। फिर सेब पकते हैं और फिर चेरी। इसके बाद बर्फ गिरती है और मौसम बेहद ठंडा हो जाता है। रजौई में दुबके हुए गरमा-गरम खाने का लुत्फ लेना। स्कूल से लौटते ही बुखारी के पास बैठकर ट्रांजिस्टर पर बिनाका गीतमाला सुनना। मैं यह सब याद करता हूँ। अगर मुझे दोबारा जीवन जीने

का मौका मिले, तो मैं भगवान से कहूंगा कि वह मुझे कश्मीर में फिर जन्म दे। आज की तमाम समस्याओं के बाद भी यह खूबसूरत है।

1970 के दशक में परिवार के साथ हाउसबोट में सफर करना मेरी सबसे खूबसूरत यादों में एक है। करीब हफ्ते भर के सफर के बाद हम खीर भवानी मंदिर पहुंचते थे। रास्ते में ही खाना बनाते थे। बीच में हजरतबल दरगाह पर रुकते थे। हम हर साल वहां जाते थे। दोनों पूजास्थलों को लेकर हमारे मन में कोई भेद नहीं था।

मेरी मां की भी अनेक यादें हैं, किसी एक को बताना मुश्किल है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था प्रेम और स्नेह का संस्कार, नफरत से नफरत करने का संस्कार। उनसे ये संस्कार हमारे भीतर समा गए। अनेक तकलीफों से गुजरने के बावजूद वे सकारात्मक बनी रहीं। वे अच्छी तरह जानती थीं कि उनके व्यवहार का उनके बच्चों और नाती-पोतों पर क्या असर होगा, इसलिए वे हर जख्म को प्यार से भरती रहीं। मुझे लगता है कि यह मेरे डीएनए में है। मैं उनकी सीख ताउम्र याद रखूंगा। शिकारा की कहानी के जरिए मैंने बताने की कोशिश की है कि प्रेम कैसे जख्म भरता है।

फिल्म बनाने में 11 साल कैसे लग गए?

शिकारा मेरी मां की श्रद्धांजलि है। परिंदा के

“मैं पैसे के लिए कभी नफरत नहीं बेचूंगा”



प्रीमियर के लिए वे 1989 में मुंबई आई थीं, लेकिन वापस कश्मीर नहीं जा सकीं। *शिकारा* उनके घर, मेरे घर और उस घर को खो देने की कहानी है। यह काफी हद तक व्यक्तिगत है। 2007 में मां के गुजर जाने के बाद मैंने *शिकारा* पर काम शुरू किया। कश्मीरी पंडितों के पलायन के बारे में सबको पता है, लेकिन इस पलायन के पीछे की घटनाओं और जटिलताओं के बारे में किसी को नहीं मालूम।

इस फिल्म के लिए काफी शोध की जरूरत थी ताकि हम तथ्यों पर आधारित, दिलचस्प तरीके से कहानी कह सकें। मैंने कई वर्षों तक इस पर काम किया। शायद यह मेरा सबसे चुनौतीपूर्ण काम था, क्योंकि एक तरफ तो सच्चाई दिखाने के लिए फिल्मकार के रूप में मुझे निष्पक्ष रहना था, दूसरी ओर यह भी दिखाना था कि सिर्फ प्रेम से ही नफरत को खत्म किया जा सकता है। यही मेरी फिल्म का केंद्र बिंदु है। नायक शिव कुमार धर और शांति धर (शांति मेरी मां का भी नाम है) के बीच का प्रेम हमें नफरत से परे सोचने पर मजबूर करता है।

फिल्म की ज्यादातर शूटिंग कश्मीर में हुई। हम कड़ी सुरक्षा के बीच काम करते थे, इसलिए हमारे पास सीमित समय था। फिल्म लिखने में भी बहुत समय लगा क्योंकि परदे पर वास्तविकता को दर्शाने के लिए मुझे अनेक दस्तावेज खंगालने पड़े और वीडियो फुटेज देखने पड़े। इस सब के बीच समय निकलता चला गया।

कश्मीरी पंडितों की कहानी महत्वपूर्ण क्यों है?

तीस साल पहले चार लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित कश्मीर में अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए और अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। अभी तक वे घाटी में अपने घर नहीं लौट पाए हैं। उन्होंने अपना घर, विरासत और आत्मसम्मान सब कुछ खो दिया। फिर भी आजादी के बाद के इस सबसे बड़े शरणार्थी संकट को देश की जन चेतना में कभी जगह नहीं मिली। मुझे इस बात से बड़ी कोफ्त होती है कि सरकारों, मीडिया, सिविल सोसायटी और बुद्धिजीवियों ने पंडितों के मुद्दे पर आंखें मूंद लीं। हम सब कुछ न कुछ कश्मीरी पंडितों को जानते हैं, लेकिन कोई यह नहीं जानता कि उन्होंने कितना कुछ खोया है।

हमने कभी नहीं सोचा था कि यह सिलसिला लंबा खिंचेगा। आतंकवाद और कश्मीर के भीतर आंतरिक संघर्ष को संभालने में हमारी अक्षमता ने कश्मीर को एक अशांत राज्य बनाए रखा। इस कारण पंडितों की वापसी का सवाल कहीं खो गया। अगर पंडित लौटते, तो यह इलाका ज्यादा अच्छा, शांतिपूर्ण और आर्थिक रूप से समृद्ध होता। स्थानीय लोग चाहते हैं

कि सभी समुदाय एक साथ आएँ। *शिकारा* मुख्यधारा की पहली फीचर फिल्म है, जिसने 30 साल पहले जो हुआ उस पर दोबारा चर्चा शुरू की।

यह विडंबना थी कि पंडितों ने फिल्म को ट्रोल किया। क्या यह विवाद जानबूझ कर पैदा किया गया था? यह बात राजनीति के बारे में आज क्या बताती है?

यह शायद पहली और आखिरी बार है, जब मैं विवाद के बारे में कुछ कह रहा हूँ। फिल्म की रिलीज वाले दिन, दिल्ली में एक विशेष स्क्रीनिंग रखी गई थी, जहां मैंने कई कश्मीरी पंडितों को आमंत्रित किया था। उन्होंने खड़े होकर फिल्म की तारीफ की। तभी पीछे बैठी एक महिला ने चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा कि मैंने फिल्म में ज्यादा हिंसा और नफरत नहीं दिखाई। उन्हें इस बात पर भी ऐतराज था कि फिल्म में मुस्लिम कलाकारों ने पंडितों की भूमिका क्यों निभाई।



“शिकारा पर विवाद करने वाले ऐसी फिल्म चाहते थे जो दो समुदायों के बीच की खाई चौड़ी करे ताकि वे अपना राजनैतिक एजेंडा आगे बढ़ा सकें”

मैं हतप्रभ रह गया। महिला के साथ मौजूद एक व्यक्ति घटना की रिकॉर्डिंग करने लगा। उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और कुछ ही मिनटों में फिल्म को गलत तरीके से पेश करते हुए ट्रोल किया जाने लगा। जांच करने पर हमें पता चला कि कुछ लोगों ने दिल्ली-एनसीआर की दो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों को यह सब करने के लिए हायर किया था। फिल्म को कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें बड़ी रकम दी गई थी।

यह जबरन खड़ा किया गया विवाद था और

फिल्म की रिलीज से कई दिन पहले इसकी योजना बनाई गई थी, क्योंकि चीखने-चिल्लाने वाली महिला दोपहर को कर्नॉटप्लेस के प्लाजा सिनेमा से सीधे नोएडा पहुंच गई और खबरिया चैनलों पर घंटों इंटरव्यू देती रही। जाहिर है, उन्हीं लोगों ने महिला को भेजा था। इसके बाद चंद घंटों में हमारी आइएमडीबी रेटिंग 8.1 से गिरकर 1.5 रह गई। इससे क्या पता चलता है? ये लोग कश्मीरी पंडितों पर ऐसी फिल्म चाहते थे जो नफरत और हिंसा को बढ़ावा दे। वे ऐसी फिल्म चाहते थे जो दो समुदायों के बीच की खाई और चौड़ी करे ताकि वे अपना राजनैतिक एजेंडा आगे बढ़ा सकें।

केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के लिए भी *शिकारा* की स्क्रीनिंग की गई थी, उनमें से कई ने मेरे काम की प्रशंसा की। लेकिन फिल्म को लेकर नकारात्मकता इतनी अधिक थी कि ज्यादातर लोग इसे देखने सिनेमाघर गए ही नहीं। जब टेलीविजन पर *शिकारा* दिखाई गई तो मेरे पास ऐसे मैसेज की बाढ़ आ गई कि फिल्म और इसमें दिया गया संदेश कितना अच्छा है। जाने-माने कश्मीरी कलाकार मसूद हुसैन ने टीवी पर फिल्म देखने के बाद मुझे फोन किया और कहा कि लोग नफरत से इस कदर अंधे हो गए हैं कि उन्हें *शिकारा* में दिया गया शांति और प्रेम का संदेश भी नहीं सूझा। लेकिन मेरा मानना है कि कभी देर नहीं होती।

क्या आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा लोगों को पसंद आने वाली फिल्म बनानी चाहिए थी?

सिनेमा बेहद शक्तिशाली और प्रभावशाली माध्यम है और कलाकार के रूप में समझदारी से इसका इस्तेमाल करना मेरा दायित्व है। समाज में चल रही सांप्रदायिक कलह और घृणा को सिनेमा के माध्यम से बढ़ावा देना बहुत आसान है। मैं और अधिक हिंसक और शायद ज्यादा लाभ कमाने वाली फिल्म बना सकता था, लेकिन मैं पैसे के लिए कभी नफरत नहीं बेचूंगा क्योंकि नफरत सिर्फ नफरत को और हिंसा सिर्फ हिंसा को जन्म देती है। अपनी कहानी में मैंने अतिरेक की जगह संयम और नरसंहार की जगह मार्मिकता को चुना। घटनाओं को दिखाने की प्रतीकात्मक राह चुनी। ए.आर. रहमान ने जब यह फिल्म देखी तो उन्हें यह बात काफी पसंद आई कि हिंसा करने वालों की सिर्फ छाया दिखाई गई, क्योंकि हिंसा का कोई चेहरा नहीं होता। उन्होंने इस फिल्म पर महीनों मेहनत की, क्योंकि उनका मानना है कि अतीत के जख्मों को भरना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। मैं खुद इस दर्शन में दृढ़ विश्वास करता हूँ और बेहद आशावादी हूँ।



भारतीय रंगमंच के पितामह

इब्राहिम अल्काजी थिएटर में क्रांति के जनक थे, उन्होंने इसे आधुनिक बनाकर उसकी दिशा बदल दी

सुनील मिश्र

इब्राहिम अल्काजी की गणना भारतीय रंगमंच में बीसवीं सदी के शिखर पुरुषों की तरह होती है। उन्होंने अपने सर्जनात्मक कार्य से श्रेष्ठता के नए रंग प्रतिमान स्थापित किए। उन्होंने कई पीढ़ियों पर रंग संस्कार की अमिट छाप छोड़ी। हिंदी रंगमंच को राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाने और उसमें नई सर्जनात्मकता तथा ऊर्जा का संचार करने में उनकी भूमिका ऐतिहासिक है। रंगकर्म को जिम्मेदारी से लेने, उसकी गंभीरता की फिक्र करने, उसके लिए उपयुक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस करते हुए उसे गहरे अनुशासन से संबद्ध करने के लिए उन्होंने नई परंपरा का सूत्रपात किया। अल्काजी ने पश्चिम की आधुनिक दृष्टि को भारतीय परिवेश में समाहित कर ऐसे रंगमंच की अवधारणा विकसित की जिसकी जड़ें हमारी परंपरा में गहरी हों और पश्चिम के स्वस्थ प्रभावों के प्रति सहज खुली हों। बीसवीं सदी के छठवें, सातवें और आठवें दशक में हिंदी रंगमंच में जो आत्मविश्वास दिखाई देता रहा है, निर्विवाद रूप से उसका श्रेय अल्काजी को जाता है।

उन्होंने रंगस्थान के कल्पनाशील और विविध उपयोग, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के नए मौलिक नाटकों के पहले-पहल श्रेष्ठ प्रदर्शन, रंग सामग्री के परिष्कार, दृश्यबंध के सुरुचिपूर्ण उपयोग आदि का निराला सिलसिला शुरू किया। इसका गहरा प्रभाव समूचे भारतीय परिदृश्य पर पड़ा। रंग निर्देशक होने के साथ-साथ वे देश के श्रेष्ठतम रंग गुरु के रूप में भी उभरे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक के रूप में उन्होंने अनेक रंग पीढ़ियों को प्रशिक्षित किया। पिछले पचास सालों में भारतीय रंगमंच पर सक्रिय श्रेष्ठ निर्देशकों में से अधिकांश उनके शिष्य रह चुके

हैं। अल्काजी की शिक्षा में स्वतंत्रता और मुक्ति का गहरा संस्कार था। यही कारण है कि उनके अधिकांश शिष्यों ने उनसे अलग राह अपनाकर अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व विकसित भी किए।

इब्राहिम अल्काजी का जन्म 18 अक्टूबर 1925 को पूना में हुआ था। रॉयल अकादमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लंदन से नाट्य कला में उपाधि पाने के बाद उन्होंने 1954 में मुंबई में रंगकर्म के क्षेत्र में अपनी शुरुआत की। उन्होंने वहां थिएटर यूनिट ऑफ ड्रामेटिक आर्ट की स्थापना की। इसके माध्यम से एक ओर विभिन्न नाट्य प्रस्तुतियों की शुरुआत हुई और शहर में एक तरह से रंग आंदोलन की शुरुआत हुई। इस अवधि में वे नाट्य अकादमी के प्राचार्य के रूप में भी काम कर रहे थे। उनके द्वारा संपादित *द थिएटर बुलेटिन* उस समय रंगकर्म और सहधर्मी कलाओं पर

मूल्यवान रचनात्मक हस्ताक्षर बन चुके थे। बाद में उनको पद्मभूषण और पद्मविभूषण से भी नवाजा गया। 1986 में मध्य प्रदेश सरकार के रंगकर्म के राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से भी वे विभूषित हुए।

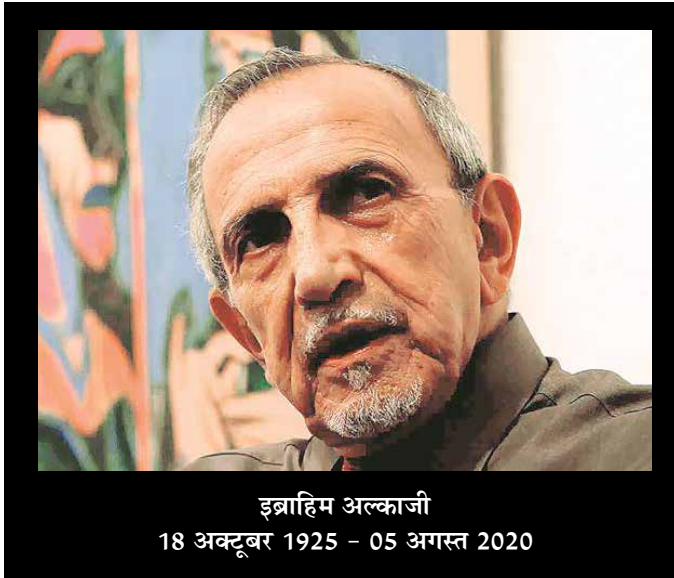
1962 से 1977 तक वे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के निदेशक रहे। उस समय उनकी उम्र 37 वर्ष थी। वे 15 वर्ष इस संस्थान के प्रमुख रहे। अल्काजी ने यहां नाट्य साहित्य सिद्धांत और प्रस्तुति के तकनीकी पक्षों का गहन प्रशिक्षण शुरू किया और रंगमंच के उच्चतम प्रतिमानों के प्रति संकल्पित प्रतिबद्धता की निष्ठा जगाई।

एक कुशल परिकल्पनाकार के रूप में भी उनकी ख्याति और आदर कम नहीं था। उनकी प्रेरणा से भारत में आधुनिक रंगमंच ने समकालीन साहित्य और रूपंकर कलाओं आदि से नया अंतःसंबंध भी विकसित किया। यही नहीं, 1982 में म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट आक्सफोर्ड में *इंडिया मिथ ऐंड रियलिटी* शीर्षक प्रदर्शनी में उनके अनेक कला प्रकाशनों की शृंखला और दिल्ली, चेन्नै तथा मुंबई में वार्षिक प्रदर्शनियों की।

इब्राहिम अल्काजी का व्यक्तित्व विराट और सम्मानबोध से भरा हुआ था। उनकी नाट्य प्रस्तुतियां विषयगत और शिल्पगत वैभव से समृद्ध मानी जाती हैं फिर चाहे वह ऐतिहासिक *अंधा युग* हो, *ययाति* हो, *अषाढ़ का एक दिन* हो, *तुगलक* हो, इन सबमें कालगत, समयगत और उत्कृष्टतागत ऐतिहासिकता मौजूद रही और आकलनकर्ताओं ने ढूंढकर रेखांकित भी की। उन्होंने शेक्सपीयर और कई ग्रीक नाटक भी निर्देशित किए। उनका सृजन और अपने समय के दिग्गज रंगकर्मियों मनोहर

सिंह, ओम शिवपुरी, मोहन महर्षि, रामगोपाल बजाज, उत्तरा बावकर, विजया मेहता, रोहिणी हट्टंगड़ी, ओम पुरी, राजेन्द्र गुप्त, पंकज कपूर, नसीरुद्दीन शाह के गुरु के रूप में उनका आदर इस बात का प्रमाण है कि वे एक सच्चे कलाकार थे। जिनके होने से कलाओं को, विशेषकर रंगमंच को उसका सर्वोच्च मिल सका।

(लेखक सिनेमा पर सर्वोत्तम लेखन के लिए नेशनल अवार्ड से पुरस्कृत हैं)



इब्राहिम अल्काजी
18 अक्टूबर 1925 - 05 अगस्त 2020

एकमात्र प्रकाशन था। अल्काजी को 1950 में ब्रिटिश ड्रामा लीग का तारांकित प्रमाण पत्र और ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का प्रसारण पुरस्कार मिल चुका था। 1962 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी ने निर्देशन के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया और 1967 में वे अकादमी के फैलो भी बनाए गए। 1966 में भारत सरकार ने उन्हें जब पद्मश्री प्रदान की तब वे 41 वर्ष के थे। वे निष्पक्ष और पारदर्शी समय के



छोटे लाल का कमाल

भोजपुरी फिल्म *दोस्ताना* का ट्रेलर रिलीज होते ही इसे हाथोहाथ ले लिया गया। वजह है, फिल्म के हीरो **प्रदीप पांडे चिट्ठू**। वे युवाओं में अभी सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं और उनसे भी ज्यादा लोकप्रिय हैं, उनके डांस मूव्स। भोजपुरी इंडस्ट्री के पहचाने नाम रवि किशन, मनोज तिवारी, खेसारी लाल यादव और दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' को चिट्ठू बहुत तेजी से पीछे छोड़ रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात, चिट्ठू ने निरहुआ के साथ बतौर बाल कलाकार शुरुआत की।



ब्यूटिफूल माइंड

यूपीएससी में रैंक 93वीं हो और देश फिर भी बात करे, तो जाहिर है, वजह कुछ खास ही होगी। उनका नाम भले ही पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय के नाम पर रखा गया हो लेकिन **ऐश्वर्या श्योराण** ने नाम मेहनत से कमाया है। श्योराण को लोग ब्यूटी विद ब्रेन कह रहे हैं, क्योंकि वे मिस इंडिया की फाइनलिस्ट रह चुकी हैं।

तूफान से पहले

सारा अली खान ने अपने इंस्टा पर पूल टॉय पर बैठ कर आंखें मूंदे फोटो पोस्ट की और कैप्शन लिखा, 'तूफान से पहले की शांति।' लेकिन उनके प्रशंसकों का कयास न उस तूफान में है न उस शांति में जो सारा दिखाना चाह रही हैं। उनके प्रशंसक तो यह जानना चाह रहे हैं कि आखिर वे इतनी तल्लीनता से किसके खयालों में खोई हुई हैं। मुंबई की रिमझिम फुहारों के बीच सफेद घोड़ेनुमा पूल टॉय पर क्या वे सपनों के राजकुमार के बारे में सोच रही हैं?



मां से आगे

आप अभी भी कैडल और काइली जैन्स के कैटवॉक और उनकी निजी जिंदगी में ही दिलचस्पी ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप एक खूबसूरत बाला को नजरअंदाज कर रहे हैं। नजरें घुमाइए और **काया गरबर** को देखिए। परफेक्ट फिगर और बोलती-सी आंखों वाली यह लड़की महज 18 साल की है। अब यह मत कहिएगा, जैसी मां वैसी बेटी, क्योंकि वे तो अपनी मां और सुपरमॉडल रह चुकी सिंडी क्राफर्ड से भी बढ़कर हैं।



गेट, सेट, गोल

2017 में फीफा अंडर 17 विश्व कप से **नरेंद्र गहलोत** को चोट लगने की वजह से बाहर होना पड़ा था। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा मैदान में लौटे। वे देश के दूसरे सबसे युवा गोलकीपर बने। 18 साल 83 दिन की उम्र में यह लक्ष्य हासिल कम बात नहीं।



हार्दिक खुशी

हार्दिक पंड्या की सर्बियाई अभिनेत्री और मंगेतर, नताशा स्टेनकोविक ने बेटे को जन्म दिया है। हार्दिक ने अस्पताल से ही फोटो शेयर की और कमेंट की बौछार शुरू हो गई। कुछ दिनों पहले हार्दिक अपनी पत्नी के लिए रसोई में खाना बनाते हुए भी नजर आए थे, हार्दिक के चेहरे की खुशी ही बता रही है कि गोद में बेटा किसी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से कम नहीं है।

शहरनामा

अयोध्या

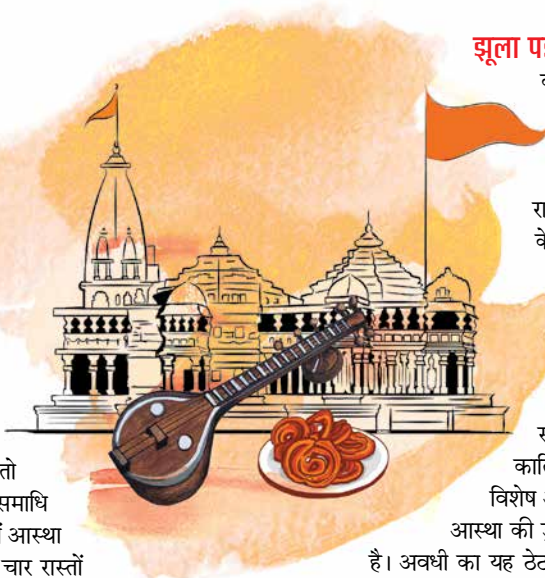


यतीन्द्र मिश्र

(अयोध्या राज परिवार से जुड़े संगीत, कला मर्मज्ञ। लता मंगेशकर और बेगम अख्तर पर चर्चित पुस्तकें)

समन्वयवादी नगरी

अगर आप पहले अयोध्या नहीं आए हैं, तो एक बार जरूर आइए। मर्यादा के सनातन प्रतीक भगवान राम की जन्मस्थली का गौरव पाया यह शहर अपनी समन्वयवादी छवि के लिए प्रसिद्ध रहा है। कई परतों में लिपटी हुई धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक महत्व के स्थलों के लिए भी अयोध्या जानी जाती है। एक ओर, त्याग और तप के लिए प्रसिद्ध नंदीग्राम है, जहां भरत ने चौदह साल तक राम की अनुपस्थिति में अयोध्या का राज्य-संचालन किया, तो दूसरी ओर गोप्रतार घाट, जहां राम जल-समाधि लेते हैं। इन्हीं अंतरध्वनियों के बीच हजारों आस्था केंद्रों के साथ सांस लेता यह शहर, उन चार रास्तों (गौरा गयासपुर, पुरवा चकिया, तारडीह और रामपुर भगन) का भी साक्षी है, जिधर से राम वन-गमन के लिए गये। यही नहीं, अयोध्या पांच जैन तीर्थकरों की जन्मस्थली और गौतम बुद्ध के वर्षावास के रूप में भी इतिहास में समाहित है।



झूला पड़ा कदम की डारी

कोविड-19 महामारी के चलते इस वर्ष अयोध्या में बरसों पुरानी परंपरा टूटी, जब हरियाली तीज के दिन होने वाला मणिपर्वत का झूला महोत्सव नहीं हुआ। इस दिन अयोध्या के छोटे-बड़े लगभग छह हजार मंदिरों से राम-जानकी के विग्रह अपने मंदिरों से निकलकर झूलन के लिए जाते हैं। उसी दिन से शुरू होकर रक्षाबंधन तक अयोध्या के मंदिरों में सावन झूला होता है। इन दिनों गौनिहारियों और कथावाचकों से गलियों में गूंजता ये गीत सुन सकते हैं- 'झूला पड़ा कदम की डारी, झूलें अवधबिहारी ना।' अयोध्या में वर्ष भर के ऋतु-परिवर्तन के साथ लाखों की भीड़ वाले कई पर्व देखे जा सकते हैं। इनमें रामनवमी और राम-विवाह के अलावा कार्तिक मास की पंचकोसी और चौदहकोसी परिक्रमा का विशेष अभिप्राय है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सरयू में स्नान, जैसे आस्था की डुबकी में अयोध्या की सनातन नगरी को पुनर्नवा करता है।

अवधी का यह ठेठ मंगल-गीत आज डिजिटल युग आ जाने के बाद भी लोकलय में स्त्रियां गाती हैं, 'चलो अस्मान बिमल जल सरजू के/राम कहें हम सरजू नहाबै/सीता कहें हम चलब जरूर...'। दीपावली हमेशा से ही अयोध्या का भव्य आयोजन रहा है, मगर पिछले कुछ वर्षों से वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार ने राम की पैड़ी पर बड़ा दीपोत्सव आयोजित करना शुरू किया है, जिस पर देश-भर के लोगों और मीडिया की निगाह गई है।

परिक्रमा सूत्र

गोस्वामी तुलसीदास ने 1574 ई. में रामनवमी के दिन *रामचरितमानस* लिखने का आरंभ यहीं से किया और शुरुआत के तीन कांड यहीं लिखकर वे काशी गए। अनगिनत रामरसिक भक्त कवियों ने अपनी पदावलियां राम की भक्ति में लिखीं, जिनमें संत कृपानिवास, अग्रदास, युगलानन्दशरण और रामसखी जैसे ढेरों नाम शुमार हैं। डच इतिहासकार हंस बेकर ने इस क्षेत्र की पौराणिक महत्ता पर अंग्रेजी में एक किताब *अयोध्या* लिखी। अवधवासी लाला सीताराम बीए की दो प्रमुख कृतियां *श्री अवध की झांकी* और *अयोध्या का इतिहास* से इस शहर के अंतरमन का पता लगता है। वैसे कुछ ऐसी किताबें भी हैं, जिनके बगैर अयोध्या-परिक्रमा पूरी नहीं होती। इनमें भागीरथ ब्रह्मचारी (*अयोध्या दर्पण*), रामनाथ ज्योतिषी (*रामचंद्रोदय*), महात्मा बनादास (*उभय प्रबोधक रामायण*), पंडित उमापति त्रिपाठी 'कोविद' (*सरयू अष्टक*), महारानी वृषभान कुंवर (*वृषभान विनोद*) और मानसिंह 'द्विजदेव' (*शृंगार लतिका सौरभ*) वगैरह यकीनन याद की जा सकती हैं। और भी बहुत कुछ है यहां।

मिलीजुली विरासत

वैष्णव परंपरा के इस शहर का मुख्य स्वभाव राम की नवधा भक्ति के साथ बीतरागी जैसा रहा है, क्योंकि यह साधुओं और बैरागियों का भी नगर है। फिर वह, प्रेममार्गी संत पलटूदास हों या बाद के भगवानदास और रामशंकर दास 'पागलदास', जो कुदरू सिंह 'अवधी घराना' के बड़े पखावजी हुए। बगल सटे हुए फैजाबाद (अब अयोध्या) की नवाबी रवायतें इसे सहकार का एक अलग रंग देती हैं, जैसे- ईशा लेखन, कैनावास पर तैल माध्यम से बनाई जाने वाली पोर्ट्रेट कला, जिसे यूरोपीय चित्रकार टिली कैटल ने 1766 ई. में नवाब शुजाउद्दौला के समय में आरंभ किया और हस्तकला की जामदानी और तंजेब का काम। गजल की दुनिया की महान गायिका बेगम अख्तर ने अपनी शुरुआत अख्तराबाई फैजाबादी नाम से इसी शहर से की थी। कई अन्य अफसाने भी हैं, जो अयोध्या और फैजाबाद को मिलाकर संस्कृति का खूबसूरत पन्ना रंगते हैं।

मनभावन खुरचन

अयोध्या आएँ, तो खुरचन पेड़ा खाए बगैर न जाएँ। खाने-पीने की कुछ चीजें अयोध्या को विशिष्ट बनाती हैं, जिनमें हनुमानगढ़ी के बाजार में बेसन के लड्डू, रामदाना, बताशे के अलावा महावीर की टिकिया, रामआसरे के पेड़े-रबड़ी और चिरंजीलाल की लस्सी जरूर चखें। शृंगारहाट से शास्त्रीनगर की छोटी-छोटी दुकानों में समोसे, कचौड़ी, पूड़ी-सब्जी, दही-जलेबी, इमरती और मालपुए की अपनी ठसक है। अफसोस कि बरूआ महाराज के समोसे अब इतिहास हो गए हैं।

नदियों की गोदी

अयोध्या में सिर्फ सरयू ही नहीं बहती, बल्कि इस परिक्षेत्र को अपने जल से कुछ अन्य नदियां भी भिगीती हैं, जिनमें तिलोदकी गंगा, तमसा, वेदश्रुति, धेनुमती और मंजूषा भी अपनी धारा के साथ शामिल हैं। 'जय सियाराम' का अभिवादन आत्मीय है और पारंपरिक भी...